श्री दिग्विजय सिंह : सर, डिबेट नहीं करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। सभापति जी, हम तो आग्रह करना चाह रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया : जब आर्थिक नाकेबंदी हो जायेगी, तो डिबेट तो अपने आप ही हो जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मोशन ऑफ थैंक्स। ...(व्यवधान)... श्री संतोष बागड़ोदिया। ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि : माननीय मंत्री जी को यह ...(व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): सर, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आज जीरो आवर नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: You should give an assurance to us. I am speaking on behalf of the State. I am a representative of the State...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... We will now resume the discussion on Motion of Thanks on President's Address. Shri Santosh Bagrodia..*(Interruptions)*.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, please ask him to keep quiet. Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to thank the hon. President of India for his enlightened Address. Every word of his Address is containing something which cannot be disputed. Nobody can have queries over the 'Vision', as elaborated in his Address. He makes a prominent comment in his opening para itself, and I just quote. "As a nation, we have collectively decided to sink the differences of the past; that we have restored to our polity a sense of healing; that we have restored to our society a sense of inclusiveness..." The hon. leader of the Congress Party, the Chairman of U.P.A., Shrimati Sonia Gandhi, has mentioned something in her address in Hyderabad, and I quote from her address. "Every individual citizen in the country will have a life of security, prosperity, and dignity of each and every Indian citizen will be ensured". This is the main perspective.

यह आम आदमी का भाषण है, यह आम आदमी की सरकार है, यह आम आदमी के लिए भाषण दिया गया है, आम आदमी के लिए सरकार काम कर रही है। इस पर कल हमारे भाई राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अभिभाषण में रोमांच क्यों हो रहा है, इस सरकार को रोमांच क्यों हो रहा है। डिप्टी चेयरमैन सर, प्राब्लम तब हुई जब वर्ष 2004 में एनडीए की सरकार गई, उनका रोमांच खत्म हो गया, हमेशा-हमेशा के लिए मर गया क्योंकि रोमांच के लिए sensuality चाहिए, वह sensuality खत्म हो गयी। यह जो इन लोगों के मन में था, इनका यह कहना कि इंडिया शाइनिंग, कोई इंडिया शाइनिंग नहीं था, सारे अंधकार में इनकी पार्टी चली गई, तब से इनका रोमांच होना बंद हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह आम आदमी की सरकार ने, जो यह काम आम आदमी के लिए किया है, जो विज़न है... । और पांच बरस में पूरा करेंगे - यह नहीं की बीस बरस की बात करेंगे - पांच बरस में इन्होंने कहा, नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके लिए अगर राजनाथ सिंह जी को रोमांच नहीं होता है तो मैं नहीं समझता कि उनको कभी रोमांच हो सकता है। इन्होंने भारत निर्माण की बात की, जिसमें कि 2009 तक सारा रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टीविटी इम्प्रूव हो जाएगी, उसके लिए अगर उनको रोमांच नहीं होता है तो उनको रोमांच हो ही नहीं सकता। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन जो सरकार ने बनाया, अगर हैल्थ के लिए, रूरल हैल्थ हो, उसमें भी अगर उनको रोमांच नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं?

Basic Services to Urban Poor, 63 सिटीज़ में जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, उसमें भी इनको रोमांच नहीं होता है Sarva Shiksha Abhiyan alongwith the universalisation of Mid-Day Meal programme now covers 12 crore children. इतना बड़ा काम सरकार ने अपने विज़न में दिया, फिर भी उनको रोमांच नहीं होता है क्योंकि sensuality नहीं रही। एक हजार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बन रहे हैं for underprivileged girls, इसके लिए भी रोमांच न हो The Government is for the *aam admi*, by the *aam admi*. इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको रोमांच तब होगा - इनको थोड़ा बहुत रोमांच इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी पार्टी ने इनको प्रेज़ीडेंट बना दिया, कुछ परिस्थितियों में बन गए, लेकिन उस रोमांच से पूरा असर नहीं होने के कारण उनको सब खामियां नज़र आ रही हैं। All the financial reforms of the Government are with a human face; that is why, the Government is committed to reforms. One billion people moving at a steady rate of eight per cent is very real now. इन्होंने जीडीपी की बात की, मैं जीडीपी के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। उन्होंने 2003-2004 के फिगर्स दिए और कहा कि थर्ड क्वार्टर में 10 प्वाइंट कुछ परसेंट हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय 2000-01 में 5.3, 6.7, 4.3, 1.8 - as low as that of GDP हुआ। 2001-02 में फर्स्ट क्वार्टर में, 4.5, 5.3, 6.3, 6,7 हुआ। इसी प्रकार अगर आप देखें तो 2002-03 में लास्ट क्वार्टर

में 3.8 हुआ और थर्ड क्वार्टर में 1.8 हुआ। चूंकि यह 1.8 हुआ, 2002-03 में—इसको जब हम कम्पेयर करते हैं, 2003-04 से—तब 11 परसेंट हो गया। इतना लो जो हुआ, सडनली फिर बढ़ा, वह उस लो के कारण हुआ। इस परिस्थिति में भी, इस नयी सरकार के आने के बाद कैसे स्टेडी ग्रोथ हुई है, उसको समझने की दरकार है। 2004-05 में जब से सरकार आयी, फर्स्ट क्वार्टर में 7.6, सेकेंड में 6.7, थर्ड क्वार्टर में 6.4, फोर्थ क्वार्टर में 7 प्वाइंट और ये जो दो क्वार्टर 2005-06 के गए हैं, उसमें 8.1 और 8 परसेंट जीडीपी ग्रोथ हुई। Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government says that this growth rate become 12 per cent, and this growth will be a miraculous growth for the country and we will assume the eminence at the global and regional trading. जब हम इनफ्लेशन की बात करते हैं तो उसके भी मैं कुछ फिगर्स आपको देना चाहता हूं। इनकी सरकार के समय इनफ्लेशन बहुत ऊंचा गया। लेकिन कोई प्रोग्रैस नहीं हुई। आज जब प्रोग्रैस हो रही है तब नेचुरली कुछ इनफ्लेशन बढ़ता है। गेहूं के दाम इन्होंने बताए, गेहूं के दाम बढ़े, कहा कि 11-12 बरस से कोई इम्पोर्ट नहीं हुआ। इम्पोर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़ा भंडार इनके लिए छोड़ा, उसको इन्होंने 6 बरस में नष्ट किया, 6 बरस में कोई काम ऐग्रीकल्चर के लिए नहीं किया।

इसी का असर हो रहा है कि आज हमारे यहां गेहूं की शॉर्टेज है। गेहूं की शॉर्टेज होते ही सरकार ने निर्णय लिया कि इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करना कोई खराब बात नहीं है। अगर शॉर्टेज है, तो हमारे देश की जनता भूखी नहीं रह सकती, उनके लिए इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसमें भी इनको ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

महोदय, यहां 29 परसेंट सेविंग रेट बढ़ा है। पचास वर्ष में इस तरह की गवर्नमेंट की economic management is reflected in the imperssive 29 per cent savings rate अगर एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं, तो 60 परसेंट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। लोग हल्ला तो करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल रेट, एग्रीकल्चरल लोन का वॉल्यूम देखिए, the rate of interest is one side of the story. But has it increased? There is 60 per cent increase in the rural credit. The Government has implemented all the recommendations of the Vaidyanathan Committee. The Centre, alongwith the States, is planning a Rs. 14,000 crore revival package for short-term credit. The Government proposes to create a common market for agriculture in order to make agriculture more remunerative. To minimise the risk involved in agriculture, the scope and coverage of the National Agricultural Insurance Scheme has been expanded. A National Horticulture Mission has been launched to diversify agriculture to more remunerative sectors of fruits and vegetables.

The food processing industries and warehousing technologies will take full advantage of the new dynamism in agriculture. I would like to inform this august House that even in countries like Malaysia and Indonesia, 60-70 per cent of their agricultural produce is processed, whereas in our country we are processing only one per cent of our produce. This Government has plans to increase the processing of agricultural produce. If it is processed, it is the farmer who is going to get the best price for his produce. Then there will be no need for any subsidy because they will get the right price.

The Government proposes to launch an ambitious National Biodiesel Programme this year. This single Programme can revolutionise the agriculture and power sectors. It can also help use wastelands and to meet the clean energy needs of the villages.

Sir, when we talk about infrastructure development, the National Highway Development Project has entered a new phase. Besides the Golden Quadrilateral, the Government is now four laning additional 10,000 kilometres of National Highways. The Golden Quadrilateral is extended to six lanes. फिर भी इनको रोमांच नहीं होता।

We shall have to upgrade our airports and ports to world standards. Effective steps have been taken by this Government so that Delhi and Mumbai airports will very soon be as good as any international airport. This is what is necessary for the country. This is for the development of the country. We feel that there is no development. We feel that the Government is not doing anything. Please don't oppose for the sake of opposition. If you give any contructive proposal, this Government will take it into consideration. In the entire speech of the Opposition there was not a single constructive proposal on what should be done. In his speech, there was complete opposition for the sake of opposition on every point. Besides modernising Mumbai and Delhi airports, Bangalore and Hyderabad will get new greenfield international airports. After that, we are going to get new airports at Kolkata and Chennai also.

The Railways have been built up with the hard-earned money of the ordinary citizens of the country. At this point, I have to mention something about the Railways. Laluji was sitting here. I don't see him just now. A lot of further development has to be done for cargo handling. We have seen a lot of advertisements. The Railways have done very

well. They want one billion dollars. I congratulate Laluji for this. The passenger services have been improved. There is no doubt about it. But, most unfortunately, the cargo services require much more improvement. It is only the Railways which have gone to every corner of the country. If the Railways stop booking small goods, if they don't help the small industries, if they don't help the rural industries, if they don't help them to get the raw materials, if they don't help them to transport their finished products, the small and rural industries cannot develop. These small and rural industries can't handle rake loads. The Government has to think over it; otherwise, these industries will be left far behind and this will be a great disaster for the economy of the coutnry because 40 per cent of the production comes from these small and rural industries.

When we come to the social sector, the initiative towards setting up a National Commission for Minority Educational Institutions or the proposed Bill to give the National Commission for Minority a constitutional status should be seen in this context. Sir, I am only trying to highlight what the Government is planning.

Similarly, the Government deserves to be complimented for amending the Hindu Succession Act, 1956 in order to ensure that women get inheritance rights in the property. So far, the parents used to think that whatever they were giving to their daughters, they were just doing charity to them. They used to say that they are trying to help them because they are helpless; they want to have a name in the society and that they do not want that the public at large should think that they are not helping their daughters. There was no commitment towards daughters. But after this Bill, there will be commitment towards the daughters. Similarly, the Government is indeed considering making registration of marriages compulsory. That will also help the women a lot. I don't want to go into the details. I compliment the Government for enacting a National Commission for Protection of Child Rights. Children are the future of the nation. I have a Private Member's Bill which is coming, may be in 15 days from now on the child rights. Even if the Bill is coming, I would like to draw the attention of the Government that there are many issues relating to children which are not covered in this Bill. It can be a more exhaustive Bill. I wish to call on the Government to bring forward a comprehensive legislation for the welfare, protection and promotion of child rights. We still don't have such a legislation which is very much required.

Sir, India is a knowledgeable society. The Government has set up a Knowledge Commission consisting of eminent persons who would envisage requirements of the future. The Government is investing in science. It proposes to set up Centres of Excellence in pure sciences in Pune, Kolkata and Punjab. However, the recent report from Scientific Education by NCAER leaves much scope for improvement. With several private universities coming up, it is essential that the Government ensures quality of educational infrastructure and teaching faculty.

A great decision-this is the vision of the Government—which the Government has taken is of restructuring the bureaucracy. The hon. Member, Shri Raj Nath Singh said, "The Right to Information Bill is nothing". They wanted to do everything in a hush-hush manner. When we talk about transparency, this is the Bill which brings transparency in all the activities of the Government. श्री राजनाथ सिंह जी अभी यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मुम्बई में सैन्ट्रूर होटल बेचा, उसमें कौन-सी ट्रांसपेरेंसी थी? उन्होंने जितना डिस-इनवेस्टमेंट किया, उसमें 'स्ट्रेटेजिक पार्टनर' शब्द यूज किया गया।

What is the strategic partner? Sir, you can understand it as a Chartered Accountant. Why do we need a strategic partner? The argument given during those days when they were in the Government was 'somebody who knows the job'. why do you need a strategic partner who knows the job? Somebody who is spending thousands of crores to buy a particular industry knows how to run his business. But the Government did not want to do things in a transparent manner; they wanted to have their own rights and select people of their own choice. That is why they wanted strategic partners, and that is how they created more monopoly in the country than competition. And that is how the consumer has been hurt very much. I do not want to name different companies. Whatever disinvestments they have done, every disinvestment has a shape; every disinvestment should be looked into, that is, see whether it has been done in a proper manner or not. That is where the Right to Information Bill comes in. This is such a great Bill; I have discussed with bureaucrats and I have discussed with individual citizens. For a small price of Rs. 10 or Rs. 25, you can get all the information. Why did the Government take this decision? Even nothing of the officers is available to an ordinary citizen. You can know why the nothing has been made available. What else do you want? You still want to say that the Government is not

transparent. I compliment the Government for bringing in the Second Administrative Reforms Commission. It will submit its Report during the course of the year. The Commission will make the bureaucracy more professional, prompt and accountable. I must also compliment the Government for deciding to constitute the Sixth Pay Commission for Central Government employees. They are also a part of *'Aam aadmi'*. If you do not want corruption, if you want a corruption-free bureaucracy, we have to raise their salaries. Every sector is witnessing a surge in income and salaries. It is essential that the service conditions of the Government servants must be made accordingly. There should be parity with other sectors of the economy so as to attract best talents to the bureaucracy. There was a time when people wanted to become IAS officers. There was a time when people wanted to take up Government jobs because they knew that the services and perquisites were at a very high level. This Sixth Pay Commission, I am sure, will do something about this.

श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बातें कहीं, उनके बारे में मैंने कुछ बातें कही हैं, कुछ और कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा-''बंगलादेशी घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी identify करके इस देश की सीमा के बाहर किया जाए, आपने इसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की''। इतना बड़ा allegation कोई responsible आदमी नहीं लगा सकता। मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी तो बहुत responsible हैं, लेकिन राजनीति के लिए ...(व्यवधान)

श्री बलबीर के० पुंज (उत्तर प्रदेश): बागड़ोदिया जी ... (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप बैठ जाइए, आपका नंबर आएगा जो आप जो मरजी हो बोलिएगा। हमने कोई objection नहीं किया था, जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, तो हम चुप बैठे थे ... (व्यवधान) I am not yielding ...(*Interruptions*)

श्री बलबीर पुंज: महोदय,*

श्री उपसभापति: यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ....(व्यवधान) पुंज जी, बैठिए ...(व्यवधान)

श्री बलबीर के० पुंज: *

श्री उपसभापति: आप बैठिए ... (व्यवधान)

* Not recorded.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): आपने राजनाथ सिंह का भाषण सुना होगा, आधा पोलिटिकल भाषण था।

श्री उपसभापति: आप बैठिए, भंडारी जी, उनको उनका भाषण पूरा करने दीजिए ...(व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं जानना चाहता हूं कि यह कहना कि आपने उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की है, यह इतना पततमेचवदेपइसम`जंजमउमदज है। एक बजपवद ऐसा बता दें, जिसमें सरकार ने यह चेष्टा की है कि बंगलादेश के जो गलत आदमी आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको यहां रखा जाए। कोई एक एक्शन तो बताएं। फिर इतना बड़ा एलीगेशन सरकार का लगा देना मेरी समझ में यह जिम्मेदारी की बात नहीं है। मुझे यह भी बताएं कि उन्होंने ये जो सारे आँकड़े दिए कि 50 लाख असम में हैं, पूरे हिन्दुस्तान में 2 करोड़ हैं, क्या वे सबसे मिल कर आए हैं? यह खबर उनके पास होगी, क्योंकि वे उन सबसे मिल रहे होंगे। मुझे बताएं कि उन्हें ये आँकड़े कहां से मिले और यह भी बताएं कि क्या ये एक वर्ष में आए हैं, 2004 में यूपीए की सरकार के आने के बाद आए हैं? 1998 से 2004 तक आपकी सरकार ने क्या किया? मुझे बताएं कि एक भी घुसपैठिए को आपने वापस भेजा। यह सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, चाहे अमेरिका हो। लोग दूसरे प्रदेशों में रेल से भी पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अच्छा काम-धंधा मिलता है। यूएसए में वे बोट से भी पहुंच जाते हैं। सब जगह लोग आते हैं। लेकिन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने केवल यह कहा कि जैसे यह बात मानी जाती है कि एक भी दोषी आदमी हम नहीं छोड़ेगें, चाहे सौ दोषी आदमी बच जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि आप जिसे भी आइडेंटिफाई करें, उसको यह बताने का अधिकार है कि वह इंडियन है तो कैसे? इसमें क्या बुराई की बात है। एक इंडियन के साथ भी आप चाहते हैं कि ज्यादती हो, क्योंकि आप धर्म के नाम पर ज्यादती करना चाहते हैं।

सर, ये कहना चाहते हैं कि आर्मी में माइनोरिटी की गिनती क्यों हो रही है। अगर ये थोड़ी-सी खबर लेकर बात करें, तो अच्छा होगा। आज 5 बजे हमारे रक्षा मंत्री जी का क्लैरिफिकेशन आएगा, तब हम और बात कर लेंगे। लेकिन गिनती करना इंफार्मेशन लेना है। इन्होंने वहां से आगे कह दिया कि हम रिजर्वेशन चाहते हैं। रिजर्वेशन की कोई चर्चा ही नहीं हुई। रिजर्वेशन की कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में फितूर है कि हम जो गिनती कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट यही है कि हिन्दुस्तान में गरीब तबके का आदमी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उसे ठीक किया जाए। केवल यही एक चर्चा का विषय है।

श्री उपसभापति: आप अभी कितना टाइम लेंगे। आप अपनी बात खत्म करने का कष्ट करेंगे।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, 5-7 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा।

श्री उपसभापति: क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी के दो घंटे हैं और 8 लोग बाकी हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, एक-दो इकोनॉमिक इश्यूज पर मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये इश्यूज मुझे बहुत प्रिय हैं। इन्होंने डाइरेक्ट इंवेस्टमेंट इन रिटेल सेक्टर की चर्चा की है। ये ऑर्डिनरी ट्रेडर्स के बड़े हिमायती होना चाहते है। पता नहीं वे ट्रेडर्स का टी भी जानते हैं या नहीं। लेकिन मैं ट्रेडर फेमिली में पैदा हुआ हूँ । मैं जानता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है सारी दुनिया में बड़ी-बड़ी दुकानें लगी हुई है, चाहे अमेरिका जाएँ, चाहे यूरोप जाएँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्माल ट्रेडर का कोई नुकसान हुआ है। स्माल ट्रेडर उसी तरह काम कर रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लेफ्ट के भाइयों में से कोई यहां नहीं दिख रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं लेफ्ट के भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान)... मैंने पीछे नहीं देखा, मैं आगे चेयरमैन साहब को देख रहा था, मैं माफी चाहता हूँ , मैं लेफ्ट के भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि आप ये जो विरोध कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिल कर, उनके साथ मत मिलिए, वे अभी थोड़ा-बहुत आपका साथ देंगे, फिर आपको धोखा दे देंगे ...(व्यवधान)..

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, he has mentioned about the Left. I have to say something on this.

श्री संतोष बागड़ोदिया: लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बाद में बोलिएगा ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: क्या बोलेंगे सर ...(व्यवधान)... party which has got the RSS working for them in Kerala, they are trying to tell us something. What is this?

श्री संतोष बागड़ोदिया: और ज्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा, जो स्माल ट्रेडर होगा, उसे बड़ा काम करने का और ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें बाधा मत डालिए, आप उनके हितैषी बनने की चेष्टा मत कीजिए। यह कोई हितैषी बनने की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि समय हो गया है। सर, केवल एक-दो बहुत जरूरी बात है, मैं वह बोलना चाहता हूँ। आज सुबह ही ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब दूसरा विषय आप छोड़िए , सब आप ही बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति: अब दूसरा विषय आप छोड़िए , सब आप ही बोल रहे हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया: बस अन्तिम बात बोल रहा हूँ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, my Chief Whip is satisfied. So, I am also going to be satisfied. But, before I am satisfied, Sir, आज सुबह टेलीविजन में एक न्यूज आई, जिसकी तरफ मैं गवर्नमैंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। I want to bring to the attention of the House that Master Surya Prabhakar of Chennai is very unwell. He is in the hospital. His father is very poor and he has no money to look after his son and get him treated. So, he has requested the Government and the Judiciary to please kill him. He wants that his son be killed because he has no money to pay for his treatment. This is very said situation. The doctor has said that the disease is not such which cannot be treated. Sir, as I was busy, my wife brought this issue to my notice and said this is what is happening there. I saw it myself. Sir, I request the Government to please look into it; help him with whatever help can be given. if the Government cannot help this child, my wife wants to help this child to survive. So, through the Government, whatever is required, she is willing to do it. I want to convey this to the Government, through you, Sir, that this child should be saved; otherwise, we will have no face to live in this country. So, this is the case of Chennai. This is the latest news. I don't know what has happened to the Best Bakery case. By this time, the decision might have come. They want to talk about big things. Their own MLA has accepted that he had bribed the witnesses in Gujarat. What face do you have to talk about morality? ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आप कंक्लूड कीजिए, बागड़ोदिया जी।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने चीफ व्हिप को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मै यह भी धन्यवाद देता हूँ कि वे सैटिस्फाइड है।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr, Deputy Chairman, Sir, I thank the President for this Address to the Joint Session of Parliament last week. The President has presented a ....(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, there will be no lunch hour today.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): But, lunch will be there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Lunch will be there, but the House will continue. There will be no break for lunch today.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, the President has presented a rosy picture about the economy saying that the growth rate is going to exceed eight per cent during the current year. But, the Government has not bothered to mention how this increase in growth rate will make a dent into the level of poverty in the country.

Sir, the UPA Government came to power on the main plank of doing justice to *aam aadmi.* The UPA's campaign was that the previous NDA Government had failed to improve the lot of the common man. Sir, what we see in reality is that the Government is unwilling to increase the rate of interest of provident fund even by half-a-per cent. The Government which talks big about labour reforms should realise that provident fund is the one and the only major social security for the unorganised workforce.

Sir, the private sector in the country which has a total backing of this Government is resorting to large scale retrenchments under the garb of improving productivity. Sir, the Labour Ministry is toothless on that, and cannot effectively deal with the corporate sector. Sir, the corporate sector owes several thousands of crores of rupees to the nationalised banks, and the Government and the banks have not succeeded in recovering even 10 per cent of the total dues. Sir, I charge the Government of begin sold out to the corporate sector, unmindful of the consequences on *aam aadmi.* I demand that the Government takes effective steps to stop large-scale retrenchment in the organised sectors. Sir, the only Aam Aadmi scheme this Government has formulated is the National Rural Employment Guarantee Scheme. Even this Scheme remains only on paper now. Even in this Scheme there is a lot of discrimination in selection of districts. The Rural Development Minister, Reghuvansh Prasad Singh, has included nearly 35 districts of Bihar and Jharkhand for inclusion in this Scheme. Half of Uttar Pradesh is also included, but when it comes to my State, Tamil Nadu, even the most backward districts have been deliberately excluded. How can a Scheme be in operation in my State without the inclusion of Ramanathapuram and Dharmapuri Districts, which are the most backward areas in the country? I demand that both these

districts, which are fully qualified for the Scheme, are included forthwith. Sir, the President in his Address has talked in terms of the work being begun in the interlinking of peninsular rivers. The President's Address also says that two such links are being established. The Central Government has been taking the people of Southern India for a major ride insofar as linking of rivers is concerned. The Central Government is totally insensitive to the drought-prone regions of Southern India. In the name of implementing river linking, the previous Government finalised a scheme to link rivers between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. This link will benefit only the Gwalior Region, which happens to be the hometown of the former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. The present UPA Government has also approved the same scheme and has launched it at a cost of several thousand crores of rupees brushing aside the demand of water-starved regions in Tamil Nadu. I would like to emphasise that no Central Government, which derives political power from the heartland, is keen on implementing this project. The design of the project was drawn by former Irrigation Minister late K.L. Rao way back in 1960. The heartland States have vetoed this project. The project never got revived though the Northern parts of the country suffered from massive floods and its Southern counterparts suffered from severe drought. The Centre unwillingly revived the project after the Supreme Court intervened in the matter. I would like to emphasise that the Ken Batwa link scheme, as proposed, will not address the acute water problem of peninsular India. I demand that the Centre rises above partisan considerations and takes steps to link the ever-perennial Himalayan rivers with peninsular rivers. Such a project should be accorded the highest priority of drought and poverty in the country have to be fought. Therefore, the component of the rivers linking scheme should include the linking of Himalayan rivers with Peninsular rivers and simultaneous linking of peninsular rivers. I urge the Government not hoodwink the people of Southern States on a continuous basis. Another river linking project that has been pending with the Centre is the linking of Achankoli-Vaipar Rivers. The Central Water Commission has cleared the project on the basis that much quantities of water from Achankoli River in Kerala flowed into the Arabian Sea. But the Governments in Kerala ruled by Congress and the Communist Parties, which swear by nationalism and internationalism respectively, are blocking the scheme. Centre should think in terms of implementing a barter deal between these two States. Water for rice

scheme could be formulated to end this impasse. Kerala does not grow rice and imports nearly 95 per cent of rice requirements from other parts of the country. Rice grown in Vaipar region can be offered to Kerala in return for water from Achankoli river. The nation is bound to gain by this project. Sir, the President has talked in terms of Railways becoming a source of pride and that the Government has decided to build two dedicated high capacity freight corridors from Ludhiana to Somnagar (West Bengal) and from Jawaharlal Nehru Port Trust, (Mumbai) to Dadri (Near Delhi) with an investment of Rs. 20,000 crores. While I welcome the scheme primarily intended to promote growth in Northern India, I do not understand why here also the Central Government would mete out a raw deal to Southern India. The Central Government may defend this project on grounds of traffic projections but Central Government cannot act like a Moghul Durbar and not address the question of removing imbalances between various regions of the country.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Moghul Durbar is only in Tamil Nadu. Your Chief Minister is running the State as a Moghul Durbar. The Central Government...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not yielded. He has not yielded.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, let him not yield.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will not go on record. If he is not yielding, it will not go on record.

SHRI P.G. NARAYANAN: You are acting like Moghul Durbar.

SHRI V. NARAYANASAMY: I agree. Tamil Nadu Chief Minister is running a Moghul Durbar.

SHRI P.G. NARAYANAN: He is misleading the House.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, ...(*Interruptions*)... Don't worry about it. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayansamy, you are taking his time.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, he is taking my time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he says that I am worried. I am not worrying at all. It is their problem. Let them face it. They will have their

own music. We are seeing what is happening to DPA. It has become UPA. Why should the Chief Minister ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): You are far away from Tamil Nadu. Why are you talking about Tamil Nadu? What do you know about Tamil Nadu?

SHRI V. NARAYANASAMY: You cannot ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Why are you so obsessed with the Chief Minister of Tamil Nadu?

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, the manufacturing sector has shied away from investment in Southern States and the only major reason for their attitude is Southern States are quite distant from the consuming market. Coal, essential raw material for power, is also moved on a large scale from East to South and thermal plants in Southern India have a hand to mouth existence as far as coal is concerned. Taking these factors into consideration and the Prime Minister's repeated assertions for a better connectivity between ports, the current freight corridor project needs to be expanded forthwith. Jawaharlal Nehru Port Trust needs to be linked with Chennai Port and Somnagar in West Bengal needs to be linked to the Ennore Port. The Container Traffic will also receive a big boost if this project is expanded. Southern India contributes nearly over one lakh crore to country's foreign exchange. There is no way they will wait indefinitely for the Centre to strengthen their infrastructure. The attitude of the Centre in responding to demands of States affected by natural calamities is apathetic. The Government of Tamil Nadu sought Central assistance to the tune of Rs. 9,800 crores to provide relief to Tsunami victims. Tsunami had claimed more than 10,000 lives in my State. The Centre rejected aid from several countries, saying that it will handle the situation on its own, but a meagre sum of Rs. 812 crores was sanctioned to Tamil Nadu. This only reveals the negative attitude of the Centre to the demands of affected States. Sir, Tsunami is a major human tragedy and even this has not sensitised the rules in Delhi.

Tamil Nadu suffered an extensive damage due to heavy floods a few months ago. The State Government and our Chief Minister prepared an elaborate memorandum and sought Central assistance of Rs. 13,685 crores. The Centre had sanctioned only Rs. 1,000 crores. I would like to

warn the Central Government against this type of indifferent attitude which would only pose a threat to the unity and integrity of the country.

Sir, regionalism is growing all over the world. The Centre is already tackling armed insurgencies in Jammu and Kashmir and in the North-East. Naxalite movement is rearing its ugly head all along the terror corridor from Jharkhand to Andhra Pradesh. This kind of indifferent attitude would only add fuel to such forces. I therefore, call upon the Centre to set up a Commission to look into the question of division of resources between the Centre and the States.

Sir, northern parts of the country are sitting on major coalfields, which is a source for thermal power. It also has more Himalayan perennial rivers, source of cheap hydel energy. Barring Neyveli, Southern States have no coal and no major hydel projects, because rivers in this region are riddled with inter-State water disputes. Inherently, there is an imbalance in the availability of power resources between the two regions of the country. When such is the situation, the Bombay High natural gas was taken to Northern India through HP pipeline. If the Central Government believes in natural justice and fair play, the pipeline should have been laid to Southern India to cater to the growing energy needs, but this did not happen in the 80s.

Now, another move is on to divert the natural gas discovered in the Krishna-Godavari Basin of Kakinada to Uttar Pradesh and Maharashtra. The move should be put on hold and the ONGC and private players should be directed to supply gas to a massive shore-based gas power plant near Kakinada. The power generated there should be shared among the energy-starved Southern States.

The natural gas pipeline from Myanmar is now at a conceptual stage by GAIL. According to the current design, the pipeline from Myanmar goes to Bihar and then on to Uttar Pradesh. I demand that another pipeline should be laid along the East Coast to meet the energy requirements of Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. North India will also benefit from the proposed pipeline from Iran and Turkmenistan.

Sir, India is about to sign a nuclear deal with the United States by which the Western countries will provide the much needed fuel to nuclear reactors. I suggest that the Government should set up two nuclear power plants along the Tamil Nadu coast and the capacity of Koodankulam

Power Project should be stepped up substantially. The Government should also revive the LNG terminal at Ennore.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P.G. Narayanan, how much time you want to leave for your colleague?

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I will complete my speech in a few minutes. Mr. Narayanasamy has already taken a lot of time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just asking you how much time you want to leave for Mr. Jothi.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, he says that he will complete in a few minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY: Now, I can understand your support.

SHRI N. JOTHI: Why are you reading in between the lines? Don't read between the lines. This is our problem.

SHRI P.G. NARAYANAN: The Government has finalised expansion of Delhi and Mumbai Airports. Hyderabad and Bangalore will have greenfield airports in the next two years. Unless the Chennai Airport is expanded, there is a possibility of flights getting diverted to these modern airports. Chennai is likely to be left behind unless the Government finalises the contract for expansion within a few months. The land for this project has already been given free of cost by our Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma.

I also hear disturbing reports that the expansion of Coimbatore Airport is going to be delayed and is being pushed to the second phase. I demand that the Coimbatore Airport should be expanded forthwith since the town is emerging as a software exporter. The Airport is an essential ingredient for software exports.

Chennai is a fast growing city. The drinking water requirement of one crore population has to be fulfilled. So, the Tamil Nadu Government has decided to put up a desalination plant in Chennai. Though the tendering process and the contract were finalised nearly six months back, the project could not be implemented because of the negative attitude of the Ministry of Environment and Forests. The Minister, Mr. Raja, who hails from Taiml Nadu is deliberately blocking this project by withholding environmental clearance. ...(*Interruptions*)... This is a fact. ...(*Interruptions*)... This is a fact. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: In the tendering process there was ...(*Interruptions*)... and they went to the court. The people of this country know everything. ...(*Interruptions*)... In the tendering process everybody knows how much corruption is there. ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Another Union Minister who also hails from Tamil Nadu, Shri P. Chidambaram, announced Rupees thousand crores for this desalination plant, but has not released that amount so far. He refuses to release the amount on filmsy grounds. The people of Tamil Nadu will teach them a lesson in the coming Assembly elections. (*Interruptions*)...

Sir, the Cauvery Tribunal ...(*Interruptions*)... He is taking my time, what do I do? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I now come to the Cauvery Water Tribunal. The Cauvery Water Tribunal has completed 15 years of work. It is nowhere in sight when the final Award will be announced. I urge the Government to direct the Tribunal to give the final Award within one month. Thereafter, the Centre should not remain a passive spectator as it was doing in the past. The Centre should nofity the final Award and ensure its implementation in letter and spirit.

The other major river, Palar, that flows in Northern Tamil Nadu remains bone-dry for most part of the year because of impounding of water by the Andhra Pradesh Government. The Andhra Pradesh Government is now constructing a dam to further impound the water of the Palar river. The Centre and the Andhra Pradesh Government are ruled by the Congress Governments. The Congress President, Shrimati Sonia Gandhi, and Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, should direct Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Rajasekar Reddy, to stop construction of this dam. If both of them act, there is no way that Mr. Reddy will decline. ...(*Interruptions*)...

1.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can say that when your turn comes. ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN: I am sure that neither Mrs. Sonia Gandhi nor Dr. Manmohan Singh will act in this matter. ...(*Interruptions*)... My friends in the DMK will remain passive spectators. This is the politics of water that is ruining the country.

The Southern part of Tamil Nadu is, basically, drought prone. It has no industries despite the presence of the Tuticorin Port. The Southern Tamil Nadu has the highest incidence of poverty and deprivation. In view of this fact, the Centre should consider declaring this region as the most backward and earmark substantial funds for the development of this region. One major project that would help development of this region is laying of second broad gauge line from Chengalpattu to Tuticorin. Railways have already completed the survey. This project would also improve the industrial activity between Chennai and Tuticorin Ports. Tamil Nadu has the highest network of meter gauge lines in the whole of India. Several ongoing gauge conversion schemes are languishing due to paucity of funds.

Railways are currently flush with funds. Therefore, the Railways should earmark substantial funds this year for speedy completion of the ongoing gauge conversion projects in the State. With thes words, I conclude. Thank you.

SHRI N. JOTHI: Mr. Deputy Chairman, Sir, time taken by Shri V. Narayanasamy be allocated to our party. This is my humble request.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is not much time, but he has taken 20 minutes.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, but Mr. Narayanasamy has taken more than ten minutes ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: By intervention ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to participate in the debate on the President's Address. I am happy that the President of India came and addressed the Joint Session; but, I am unhappy over the contents of this President's Address. It lacks direction, commitment, and there is no correlation with the Common Minimum Programme which they themselves have placed before the nation. What has happened in the last twenty months? Almost 20 months are over. That means, one-third time of the tenure of this Government is over.

What is it they have achieved? ...(*Interruptions*)... I wish they continue for five years, and go on doing things like that, so that they are not there in future. Sir, the main thrust of the...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Don't worry. I know that you are more concerned about us than your Party..(*Interruptions*).. Sir, initially, the main thurst of the Common Minimum Programme and the commitment of the Government was आम आदमी के साथ न्याय होना चाहिए। That was their main thrust of campaign. Second campaign was about the plight of farmers and their welfare. And the third thing was about the unemployed youth. On these three counts, they have totally, miserably failed. If you read President's Address, it is very much reflected there. I would like to pose a straight question:

आपने इस 20 महीने में इस दिशा में क्या काम किया है? आम आदमी के लिए कौन-सा बड़ा काम आपने किया है, एक भी काम ऐसा किया है, तो बताइये, हम खुश हो जायेंगे। आपने इसमें कहा कि हम लोग तुरन्त एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट लायेंगे, इस के बारे में सुना, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, पूरे देशभर में फोटोग्राफ लगाये जा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है फोटोग्राफ लगाने में। मगर ..(**व्यवधान**)....

श्री वी॰ नारायणसामी: आपके चीफ मिनिस्टर के फोटोग्राफ हैं। ..(**व्यवधान**)..

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: यह होना चाहिए। वे चीफ मिनिस्टर हैं। यह आपकी दया से या आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, वी॰ नारायणसामी जी की ओर से रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, let him speak, and then, you can speak whatever you want to speak.

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: आपने तो वाजपेयी जी के फोटो साफ करने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च किये, यह ठीक है क्या। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा कहना यह है ...(**व्यवधान**)...

श्री वी नारायणसामी: आपने छह सौ करोड़ रुपये इंडिया शाइनिंग पर खर्च किये। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We had put the Prime Minister's photo. You are putting somebody's photo who is not even authorised to ... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: We are not putting somebody's photo. We are putting photos of people who are officially entitled to. You should understand that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, if you go through the photograph in Tamil Nadu, particularly, you will find photos of some people who are not at all connected, either with the Government or with the system ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): How can you say like this that they are not connected? ...(*Interruptions*)...

आपकी तरफ से आरएसएस और वीएचपी के फोटो लगते थे। ...(व्यवधान)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, in a federal system, if it comes to that, it should be Prime Minister, then, Chief Minister; but, the Chief Minister is missing. What is the explanation? You don't like to see the face of Chief Minister simply because you are against ...(*Interruptions*)...

यह है इस सरकार के काम करने का तरीका, मैंने केवल उदाहरण के लिए यह बताया है। मुझे इसमें कोई विवाद नहीं है कि फोटो कैसा है, अच्छा है या नहीं है, यह तो उनका है। मगर मेरा कहना यह है कि पब्लिक मनी को खर्च करके आप ऐसे लोगों के फोटो लगा रहे हैं जो पद पर नहीं हैं, प्रधान मंत्री नहीं हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं, अन्य लोगों के फोटो लगा रहे हैं, मैंने इतनी ही आपत्ति व्यक्त की है। व्यक्तियों से हमको क्या लेना-देना है, नम्बर वन।

Sir, the second thing is that this Government is leaderless. सरकार को कौन चला रहा है, देश अवश्य जानना चाहता है। Who is leading this Government? Sir, we also saw a coalition. We know the compulsion of running a coalition Government. We also ran a coalition, a successful coalition. We had taken twenty-three political parties with us. We had divergent views. It is quite but natural that the coalition partners will express views which they feel are good for the country. But, at the same time, at the end of the day, you have to evolve a broad consensus and then move forward. But, that is not happening to this Government. It is not only my saying. My friends from the Left are also saying so, and the other people who are supporting the Government are also saying it. ....(*Interruptions*)... And, the entire country is watching. ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, this running commentary should stop. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have no problem. I can go along with them, but they are provoking me and getting more and more flak. If they want it, I have no problem. Sir, who is the Prime Minister? The entire country is saying, there are four Prime Ministers; one, PM; second SPM, super Prime Minister; third, the CPM; and the fourth, UPM, Ultra Prime Minister, Man from Bihar, Ultra Prime Minister. This is the talk of the common man in the country. ...(*Interruptions*)... Everywhere, this is a common talk ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: ... was ruling the country ...(*Interruptions*)...

श्री धर्मपाल सभ्रवाल (पंजाब): नागपुर से आदेश नहीं आ रहा। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, in this country, what is happening in this Government? I totally agree with my Left friends that if you are running a coalition Government, you need to follow the coalition *dharma*. ...(*Interruptions*)... But you are not doing it. That is why every day you are seeing what is happening. Let us take it very seriously. I am not simply trying to make a political criticism. You have not evolved a system so far in the last twenty months to take your own allies, your own people who have not joined the Government. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): What did you do when the POTA was misused and Vaiko was arrested? What did you do? ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: I think the DMK was your ally at that time. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Yes; DMK was our ally. We have no complaint on that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, in this way, we would not be able to complete this debate on the Motion of Thanks. ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You must have the fundamental knowledge who arrested whom and who used or misused POTA. I am not going into that. ...(*Interruptions*)... Sir, my point is, in this Government,

there is no patience. ...(*Interruptions*)... There is no proper appreciation of the other point of view. I have heard your Finance Minister earlier saying — I would like my friends to know it; and he quoted a quotation from *Thirukkural,* — "Hear everybody, give them an opportunity and do whatever you want to do." This is what he has said. Exactly, my friend, Shri Sitaram Yechuryji, is doing the same. The Finance Minister says, "I am hearing everybody. I am doing whatever I want to do." My point is, you cannot do it because you are not the Government. I was not the Government in NDA. The BJP was not the Government in NDA. The BJP, as the head of coalition, have to see that certain issues which are dearer to us are kept aside. We followed the coalition *dharma.* You are not doing it. So, today that is why the problems are coming in this Government. That is why today the public perception is, 'Right proposes, Left opposes and mind disposes'. दाएं हाथ से प्रोपोज़ करते हैं, बाएं हाथ से आपोज़ करते हैं और दिमाग खराब करते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ रहे। 20 महीने में क्या हुआ? ...(व्यवधान)... Sir, if every one of them wants to stand up and pose a question to me, I am happy to answer it. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurian, please ...(*Interruptions*)... This cannot be allowed. ...(*Interruptions*)... One or two interventions can be allowed, but it cannot be like this because we have to complete this debate. Every person has his own view to express, and when his turn comes, he can speak. ...(*Interruptions*)... Please avoid it. It should be avoided from either side. It is not from one side only. It is from both the sides. Please avoid it. Please avoid it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, every word that I am saying, I am uttering these words, after a careful consideration and detailed study. I am not making a general comment. I am ready for a debate on this with anybody either here or outside also. What has happened in these twenty months? What is the direction? One step forward, three steps backward, situation awkward. That is the position throughout the country. This is the position of the country. In this Government, who is running the Government?

Sir, as I said, Pradhan Mantriji is in the driver's seat, steering is by SPM, brakes by CPM, and power brake, by Lalu Prasadji. So, nothing is moving definitely...(*Interruptions*)... Always three

promises...(*Interruptions*)... Madam, please enjoy the debate ...(*Interruptions*)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सर, यह क्या हो रहा है? क्या ये रनिंग कमेंटरी चलाएंगे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am telling both sides ...(*Interruptions*)... नहीं, नहीं, अगर ये रनिंग कमेंटरी ...(व्यवधान)... बैठिए... बैठिए।...(व्यवधान)...

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सर, ऐसा लगता है कि ये इनकी पोलिटिकल पार्टी को address कर रहे हैं, हाऊस में नहीं बोल रहे हैं। अहलुवालिया जी सुन सकते हैं, उनको, लेकिन सदन की भाषा जो गरिमापूर्ण होती है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): क्या गरिमा होती है, कौन सी गरिमा की बात आप करते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए...बैठिए। देखिए, मुझे दोनों तरफ से...(व्यवधान)...

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: सर, ये मुझे गरिमा सिखा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, वह मेरा अधिकार है। मुझे रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: You have to speak on the President's Address ....*(Interruptions)*... You cannot speak according to our whims and fancies ....*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Even if you provoke ....*(Interruptions)*...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान): सर, अगर ये उलटा-सीधा बोलेंगे ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री जी के बारे में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन ...(व्यवधान)... इस तरह से जो मरज़ी आए, वह कह दें, हम कैसे बरदाश्त कर सकते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए न, जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)... He has yielded; what can be done... *(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि नारायणसामी जी और राजू परमार जी अति उत्साहित हैं। अगर यही चलाना है, रनिंग कमेंटरी चलानी है, तो आपके बहुत सारे वक्ताओं ने अभी बोलना है और आपके प्रधान मंत्री ने जवाब भी देना हैं

श्री संतोष बागड़ोदिया: तो ये धमकी दी जा रही है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं धमकी नहीं दे रहा हूं।

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप क्या समझाना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**).. आप * की बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति: बागड़ोदिया जी, आप बैठिए। देखिए, यह * बर्ड को निकाल दीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसा वातावरण बनाइएगा, वैसे वातावरण में रहना पड़ेगा, इसलिए कृपा करके थोड़ा सा धीरज रखिए। ...(**व्यवधान**)... हर आदमी को बोलने का अधिकार है, आप भी बोलिए, वे भी बोलेंगे।

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, बैठिए। देखिए ...(**व्यवधान**).. अगर हम इस डिबेट को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो let us participate in the debate. अब यह रनिंग कमेंटरी इस साइड से भी हो रही है, उस साइड से भी हो रही है, स्पीकर्स को disturbance होती है, they will not be able to express their thoughts. ठीक है, बीच में एक-दो बार intervention हो सकता है, मगर it should not be done so often. I appeal to you to avoid this. If you wish to make a point, you have got every change to do so. If you wish to say anything, when your turn comes, you can mention in your speech whatever they are saying. Why do you want to go on talking? It will not help the debate.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Deputy Chairman Sir, if there is a single sentence, which is objectionable, derogatory, unparliamentary, undignified and indecent that I have said, I have no hesitation in accepting it. I am the last man to do that. Let them bring it to my notice. But, these are hard facts. They may be unpalatable for them Madam said हम बरदाश्त नहीं करेंगे - नहीं करना है, तो मत कीजिए; क्या जेल में डालेंगे? जैसे emergency में डाला था, वैसे डालेंगे क्या? बरदाश्त नहीं करेंगे - ऐसा बोला। क्या बोल रहे हैं, ज़रा सोचकर बोलना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि हम विपक्ष में हैं। हम सरकार का भजन करने के लिए

---

* **Expunged as ordered by the Chair.**

नहीं आए हैं, यह हमारा अधिकार है, विशेष अधिकार है, पार्लियामेंट ने दिया है, लोगों ने दिया है, संविधान ने दिया है। संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार का सदुपयोग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको क्या आपत्ति है? सर, इस समय मेरा कहना यही है कि कॉमन मैन के साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात कैसे हुआ - वह डिस्प्यूट कर रहे हैं। अभी देखिए, inflation के बारे में बहुत सी बातें लोगों ने कहीं। Inflation की स्थिति क्या है, मार्केट में स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा घर जाकर मां से पूछो, बहन से पूछो, पत्नी से पूछो, आज की गृहिणी का बजट क्या है? क्या हुआ? सीमेंट के दाम बढ़ गए, डीज़ल के दाम बढ़ गए, केरोसिन के दाम बढ़ गए, कोयले के दाम बढ़ गए - चीनी के दाम बढ़ गए, गेहूं के दाम बढ़ गए, ब्रेड के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए - यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, I am not raising any prices in the House. I am the last man to do that. If the prices are controlled, if the common man is happy, we will also be happy. We may indulge in political criticism. But there is a total betrayal; they are unconcerned to the plight of the common man today.This is the point I wish to make.

Sir, the second point is about the PDS - the Public Distribution System. Our Government had increased the quota to 35 kilos. This Government, without applying its mind, without consulting friends, without bothering about the common mimimum programme which they have mentioned - I don't want to quote it and take more time - have reduced it to 20 kilos.

And they say that there are enough foodgrains everywhere available. Is it the common man's concern for the common men? They have not only reduced the PDS quota, but also atrociously increased the prices. Subsequently, what happened? My friend, the Agriculture Minister, has given a statement that 'I am keeping it pending.' It is not the question of pending. Pending का Ending होना चाहिए। It should be given up. That step should be given up. The very fact that this Government could dare to think in terms of increasing the price and reducing the quota is an indication that they have no concern for the common man. This is my criticism. You rebut me. The second point, I said, was about the price rise. Sir, today all the industries are happy. Sensex is booming and grooming. We are also happy. They production of steel has gone up; production of cement has gone up and the production of sugar has gone up. You are exporting sugar. But you are increasing the price of sugar. They price of sugar has gone up from Rs. 12 to Rs. 22. Is my figure wrong? Tell me. Is it not a fact

that the prices of rice and wheat have gone up? If my figures are wrong, you tell me. I am not quoting all the figures. In case of PDS, How can I understand the rationale. But there is an international situation like on petrol and diesel, you have increased 32 per cent. On that there can be a debate as to how it has happened or how it can be reduced. Some suggestions have been given from the other side and they can be considered. Alternative mechanism can be avolved. Administered Pricing Mechanism was decided to be abolished during the United Front Government and admitted by one part of the Communist friends also. They were in Government and Telugu Desam was also there. That was to be implemented from a particular time. Now if we try to score political points and then try to accuse each other and do not bother about the vulnerable sections of the people, the increase in the charges of the petroleum products will have a direct bearing and cascading effect on the common man because the transport system is mostly depending on that. The third point is about the farmers. Our friends have been telling that agricultural credit has been increased considerably. After 48 years when we came to power and when the agricultural credit was Rs. 36,000 crore , we had taken it to Rs. 80,000 crore plus and then put a target of Rs. 1,05,000 crore. You are moving in that direction. I am not quarrelling over that. I have a press cutting of 'India Today'. It says about a situation in a State in Maharashtra which is supposed to be a progressive State. I am just quoting this. This is an interview from Shri R.R. Patil. There is nothing negative in it. So, there cannot be any objection to that. The Deputy Chief Minister was there. He says, "A few months ago, an M.P. from the State told me that in his constituency a moneylender kidnapped farmer's wife and his daughter for non-repayment of loan. We decided that we could not tolerate this nonsense." That is why he has gone for some action. By quoting this I am not trying to say that moneylenders were not there yesterday and they came today only after this Government came. My point is that 60 per cent of the farm credit is coming through informal sources, not from the formal sources. There is a World Bank Report, there is a Standing Committee Report and there are reports by so many Committees about it. The Swaminathan Committee also spoke of the rural credit and the need to enhance it. You have not said anything. You are trying to defend your Government saying that you have increased this; population is increasing; the number of people who want credit is increasing; accordingly, it should be commensurate to that. That is not

happening. So, the Centre's spending on agriculture had fallen steeply during the liberalisation era. This is a serious allegation on all of us who are supporting liberalisation. It was in real term about 20 per cent lower than it was in 1991. Even after so-called increase in 2005, in actual terms it is less. Dandekar, the famous Economist, has opined like that and the spending on agriculture is getting reduced year after year. Despite the Planning Commission, which has got experts sitting over there, the Prime Minister, who is also supposed to be an expert in economy, the Finance Minister, and particularly the Agriculture Minister who has got agriculture dearer to his heart, this is happening. It is a matter of concern. I only urge upon the Government to seriously address this problem and try to do something and prevent these suicides. Suicides are taking place in different parts of the country as admitted by the Minister on the floor of the House two or three days back. In Andhra Pradesh, it is happening. The promise was made to the people that the moment we come into power, the suicides would stop. There is no *Alladin's Adbhut Deepak or Zinda Tilismat* to stop it. I also know. But you must go into the root cause. There was a Jayati Ghosh Committee report.

And, that report has to be seriously considered. What I am saying is that airport privatisation, or privatisation, or liberalisation is okay, but what about the concerns of the common man? I am not here to oppose the reforms. I have a different point of view from my friends of the Left. We have a different point of view. We had opened up the economy. It is paying dividends; it is showing some positive effect also. But, at the same time, till such time that the Government is able to provide a level-paying field, it is the duty of every elected Government to take care of those people who do not have access to these things. This is an important issue which has to be understood.

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): Privatisation के मामले में दोस्ती है, बाकी जगह कुश्ती है।

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो ओपन है, आपका तो ऐसा है दीपांकर बाबू कि दिल्ली में दोस्ती, कलकत्ता में कुश्ती, दिल्ली में cooperation और तिरुवनंतपुरम में operation, बीच में separation. Sir, what is said in this President's Speech is only fumbling on issue, jumbling on figures. For Bharat Nirman, Rs. 1.74 lakh crores. Where is the money? Where is the allocation? It took 18 months for Employment Guarantee Act to start. The Government

should go through the CMP. There, they have said that within 100 days of coming into power, they would do it. The Government have not shown the concern. The Government have not made enough allocation even today for the Employment Guarantee Scheme. I am not going into the details of that.

Then, another thing is about Golden Quadrilateral. Hon. Minister, Shri T.R. Baalu, appears to by dynamic Minister. One full year is lost. not even one kilometre is added as per my information. North, South East, West Corridor, work is commencing now. There is an article in one of the leading newspapers that all the tenders have been called. it took nearly 18 months to call the tenders. The scheme, which had been envisaged, finalised, approved and implementation was there. They did not bother about that. The only great thing, if it was, was removing Vajpayee's photo, the great achievement. I have no problem with that if the Government wants to do it. Second thing is with regard to *Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana.* Even after 58 years, the nation said, "We started the initiative". It is going very slowly today. In spite of having a rural friendly Minister at the helm of affairs, what can he do unless Finance Minister supports him? Thirdly, in the housing sector also, the pace of progress is very slow, for whatever reason it is. And, with regard to cold-storage chain, rural godowns, what are the priorities we have. Sir, farmers are producing perishable items. They are going waste. Onion की कहानी सुननी चाहिए हमको। महाराष्ट्र के लोग जो onion का उत्पादन कर रहे हैं, उनको एक किलो के लिए एक रुपया या दो रुपया मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए और हमारे इलाके में भी एक किलो प्याज की कीमत 12 से 16 रुपए, बीस रुपए तक जा रही है। क्यों? किसानों के सामने स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। इसके बारे में वाजपेयी सरकार ने कोल्ड स्टोरेज चेन और रूरल गोडाउन बनाने की योजना बड़े पैमाने पर शुरू की थी, फिर आप आए और इसको जितनी प्रॉयोरिटी देनी चाहिए थी, आपने उतनी प्रॉयोरिटी नहीं दी। इसके साथ ही साथ शॉर्टेज है। पहले कांग्रेस के ज़माने में हरेक चीज की शॉर्टेज होती थी। There was a problem of shortage. MPs were given coupons of telephones and LPG saying that some priority should be given and people used to come to us. During our regime, people started coming to us and said, "Sir, there is no need. There is no queue." But, today, after so much boasting by you, there is a shortage of LPG. There is a queue. There is a black-market for the LPG. Can the Government deny this? It is not an artificial shortage. If it were artificial, it should have been sorted out immediately. With the dynamic

Ministers, both for Civil Supplies and Petroleum, what has happened? LPG is not a luxury now. The average household women even in the rural areas, the middle class and the lower middle class also, are now using LPG because we have the Forest Conservation Act and people can't cut trees as they used to do earlier. That is also a problem. During the NDA rule, I say that there was no line, no queue, no shortage, no black market; and, now, everything is back again. How do you rebut my argument on all these things? That is why, Sir, I say that farmers are committing suicides. Unemployed youth are worried and agitated because the Government could not and did not provide any single job. I do admit it is not that much easy to provide jobs by the Government. But, the Government must accelerate the progress by bringing in more investment in the agriculture, which you are not able to do; and more investment in infrastructure. I have heard my friend, Shri Santosh Bagrodia Ji was saying, आपको क्या आपत्ति है, उसमें क्या आपत्ति है, इसमें क्या आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा concern इतना ही है कि we started this revolution of linking - air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, port connectivity, *Sagarmala.* All these initiatives were taken by our Government. But what are you doing now?

What is happening to that connectivity revolution? Please try to understand. Rural telephony, which is another important factor, is being neglected. If you look at this sector, the cell phones are reaching the lower middle classes and middle classes also but, at the same time, they are catching their pockets. You must understand that even today, there are thousands and lakhs of villages where the telephone has not reached. That was our priority and we had given a commitment. We moved in that direction. You are not moving in that direction. You are now saying, 'one rupee, anywhere in India'. Okay, it is fine. I hope the Minister of Communications will take note of it. We are, after all conscious people who have taken BSNL connection because in BSNL, if you are in South, you talk to your wife, your friend or group of people, it is treated as local call. hoping that the BSNL would be benefit us, we have taken the connections, even 3-4 connections; one for wife, one for PA and so on.

Now, in BSNL, to get the other side, there is lot of congestion. I had politely brought it to the notice of the CMD. He wrote back saying, "Sir, we are trying to add the lines." Twenty months are over. And, now, you are giving offer of 'one rupee', and, then, again there will be rush. It is like

saying that for some functions, they put a board saying - "Attractive offer, 'one rupee' sale", 'first come, first get' and so on. The first one gets the offer, afterwards, things are the same. Should it happen like that? Are you focussing your attention on the rural telephony? It is another question that I want to ask the Government.

Now, I would like to say something with regard to the commitments you have made. You are keeping your allies in dark. With regard to the issue of Telangana, what is the stand of the Government? What is the stand of the Congress Party? I am not able to understand. My Communist friends are clear; they have been saying it. But the people of Andhra have been told that they would be given a separate State if they vote. And, they say, what is your view. सरकार में हम बैठे हैं या आप बैठे हैं। जब हम हैं, हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। हमने वादा किया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल का निर्माण करेंगे, हमने वादा पूरा करके दिखाया। BJP's views are different. But unless you have broad consensus, being in Government, you cannot do it. Is it the position with regard to UPA? Can you make it clear? We want Vidarbha; we wanted Statehood even for Telangana, but we could not proceed further because there was no consensus, our allies did not agree in Maharashtra and Andhra Pradesh. You have to follow the coalition *dharma*. You just take their support and then tell them, 'no, no.-It is my commitment.' What I am saying again is that the Congress Party has not been given the mandate by the people. At that time, the NDA lost the mandate, I do agree. But the diference between the Congress Party and the BJP is of seven seats, only seven. We got 138 and you got 145. Please understand this message. Later on, our friends have joined you. The Left has joined, the Samajwadi party has joined, the BSP joined and the other parties gave you support. That is why you are able to govern the country and, now, one after another is becoming unhappy. You go through the speeches made by our friends. They are very critical. The only saving grace for you is our presence and our dominance in Indian politics is making you sit there. Otherwise, these people would not have supported you. It is very clear. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है then, the Samajwadi Party is unhappy, totally unhappy. The Bahujan Samaj Party is partly unhappy, our friend, Gandhiji is smiling at me. (*Interruptions*) No, no. He cannot come also. We also have some experience. There is a saying, "wise men learn from others' experience, fools learn from their own experience. So, I am not going into that. They are unhappy. TRS is unhappy and they are saying, "We

have been betrayed". And, you are just keeping quite and silent, and, they say, "we have written a letter to the BJP. If BJP sends their reply, everyghing is over." Okay, we will send our reply. Is everything going to be over? Can you do it? Why are you doing it? My point is: जब हमने लोगों को कहा कि हम इतना कर सकते हैं, हमने उतना किया, उसे करने के लिए प्रयास किया। आपने बहुत कुछ कहा और उसे करने में आपके पास क्लैरिटी नहीं है, एकता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, दिशा-निर्देश नहीं है।

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) in the Chair]

सर, मैं एक और इम्पार्टेंट प्वाइंट पर आता हूं। The Congress Party do not believe in running a coalition. It is my charge. My friend, Mr. Suresh Pachouri, can effectively counter me. Coalition is not a conviction for you; coalition is a compulsion for you. You have not developed the art of running a successful coalition. The latest example is the State of Karnataka. It is not that BJP has done something. We have not done anything. These people, MLAs, who were supporting your Government, felt that they have been taken for a ride, they were insulted and they were never consulted. That is why they made a charge saying that you were trying to divide them.

Then, they came out. And, we said, the 2004 mandate was an anti-Congress mandate. BJP got 80 seats, JD(S) got 56 seats and Congress got 65 seats. You managed it. You had the majority and you ran the show for 18 months. You could not successfully implement it. That is why our Government came. So, you cannot blame or accuse us that we had done something wrong in that regard.

Then, I would say something about the institutions. One after another, after this Government came, institutions are under attack. The Election Commission is being attacked as being caste-biased, Higher Court Judgements are being attacked. Judgements can be criticised. We already have some precedents. We can have a healthy debate. Discussion can take place on a judgement of a court. But, it was attacked. Positions were taken. The Governor's institution was totally misused. In spite of the Supreme Court or other courts saying something -- I do not want to use harsh words -- still you have not learnt lessons. Whether it is Goa, whether it is Jharkhand, whether it is Bihar, what has happened? What happened in Bihar is a national shame. You should have the audacity, at least, to admit the mistake simply and say, yes, a mistake

has been committed. He has to go. You did not say that. You owned it. Even the Prime Minister said it. The Prime Minister also said that we had not done anything wrong. Then, who has done wrong? Let the country know what exactly happened. So, you have misused the institution of even the Governors also.

Then, Sir, coming back to the issue of corruption, we are not making any charge. The Mitrokhin, the Volcker, the Quattrocchi, the tainted Ministers, these charges are not made by the BJP. These are not the cases filed by our Government. Some of these cases were filed during your earlier friend's Govrnment, and some of them are at the initiative of the court. And, you are trying to defend it, the undefendable. And, in the process, you are getting defame. You are not bothered about that and you have the audacity to say that we support the tainted Ministers. There are different Ministers. I talked about PMs earlier. Now, about the Ministers, there are non-performing Ministers like the non-performing assets. There are tainted Ministers. There are Ministers who are absconding, absconding from this very House. Earlier, a question was raised: Where abouts of the Minister? तो मंत्री जी ने जवाब दिया। कहां हैं, मंत्री जी? उन्होंने कहा कि जनता के साथ हैं। हम लोग बेकार बैठे हैं क्या? यहां जो हैं, यहां जो बैठे हैं, वे जन प्रतिनिधि नहीं हैं? दो मिनिस्टर्स को यहां से जाना पड़ा। फिर उसी मिनिस्टर को, without getting relief from the court on clearing his cases, he has been taken back. If it is a political agitation, I can understand. But the charges that were made against those two Ministers, I do not want to take their names because they are not here, are criminal in nature. Moral turpitude issue was there. You have taken them back instantly with any hesitation. Even in the case of cement scandal, an impression is going around that the court has absolved him. No. Let me make it very clear. No, Sir. The criminal case was struck down. The court finding fault with the person and then passing strictures in High Court and Supreme Court, remains. You have no hesitation in taking him back. Then, there was the issue of phone tapping फोन टेप किया गया। हमारी बहन श्रीमती अम्बिका जी यहां बैठी हैं। मैं इनसे झगड़ना नहीं चाहता हूं। ये बहुत presentable हैं और argue भी अच्छी करती हैं। पूछा–आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे कांग्रेस के स्पोक्समैन ने जो कहा, इस पर आपको क्या आपत्ति है? लैला आयी, मजनू आया। पार्लियामेंट के एक मैम्बर ने अपनी वेदना प्रकट की, उसमें उन्होंने जोर से किसी का नाम जोड़ा होगा, वैसे नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, किसी का नाम जोड़ना उचित नहीं है। मैं भी ऐसा महसूस करता हूं। मगर वह फीलिंग आया कि फोन

टेपिंग हो रहा है। फोन टेपिंग हो रहा है, तो इस पर उसका मजाक उड़ाना और यह कहना कि किससे बात की, कब बात की, क्या बात की? हर एक को अधिकार है। Privacy is a Fundamental Right in this country unless it is concerned with the security of the nation. Privacy is a right. If you say why do you go to bathroom and close the door, open it, because after all you are a public representative. Can anybody talk like that? No, Ambikaji, I am telling you, I was really suprised and hurt because we did not have the present situation earlier. We used to go different parties and meet, greet and also exchange views. आज के situation में थोड़ा-सा एटमोस्फेयर कम हो रहा है। तमिलनाडु में कम हो रहा है, यू. पी. में कम हो रहा है, बाकी इलाकों में भी कम हो रहा है, इसलिए meeting and greeting and eating together are also missing. I am not doing *vakalat* for Mr. Amar Singh. He is capable to do so. He can do *vakalat* to others. He does not need any support from others. But, what happened subsequently? Every political party is saying that its phone is being tapped. The Tamil Nadu Chief Minister said that her phone was being tapped. The former Chief Minister of Andhra Pradesh, an important political functionary, has also said that his phone was being tapped. And then, latest is that there is a news which has not been contradicted so far that telephone of a Supreme Court judge is being tapped. Who is doing this?

I am not saying the Congress is doing it. But the Government is yours. You have the control; you have the wherewithal to find out and then clinch the issue and then immediately those persons who are responsible for that and being that. यह होना चाहिए, न? यह नहीं हो रहा है। ... (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी: सर, वेंकैया नायडु जी हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हैं। फोन टेपिंग के मामले में इन्होंने यह कहा कि सरकार फोन टेपिंग करा रही है। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं, नहीं। यह नहीं कहा।

श्री सुरेश पचौरी: इन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सरकार करा रही है। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: इन्होंने यह नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि फोन टेपिंग हो रहा है। ...(व्यवधान)... यह नहीं कहा कि आपने कराया है। किसने कराया है, यह पता लगाना आपका काम है, यह कहा था।

श्री सुरेश पचौरी: सर, मैं इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने बारंबार इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि सुप्रीम-कोर्ट के माननीय जज के फोन टेपिंग का मामला उठाया गया था, उससे सरकार का कोई वास्ता नहीं है। जो माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... सुनिए तो आप, या तो आप अपनी बात कह लीजिए। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please, listen.

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सदस्य से संबंधित मामला जो आया, उसका भी स्पष्टीकरण दिया। मैं इस चीज को इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो फोन टेपिंग का मामला हुआ है। उसकी जांच चल रही है और वह मामला अभी कोर्ट के सामने विचाराधीन है, सब-जुडिस है। इसलिए उसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार का उससे कोई लेना-देना नहीं है, इसके मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री बलवीर के. पुंज: नहीं, नहीं। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, Mr. Naidu will answer it. Don't worry.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have not made any charge that the Government is tapping the phones of anybody. I am saying the fact that serious allegations have been made by responsible people, including Members of Parliament, and people who are holding posts at various levels that their phones are being tapped. I said it was the duty of the Government to see to it and reach the bottom of the truth and book the culprits.

SHRI SURESH PACHOURI: We have seen it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Naidu, since the Minister has told the House that the matter is in the court and hence *sub judice,* please try to avoid any such remarks.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we have discussed such issues umpteen times, like Ayodhya issue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): You know how to control it. You know how to manage it.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है। I am not going to question the Minister about *sub judice* subjects. But this is about a Member of Parliament, a Member of this House, and a very senior Member. This is his second term. Why cannot we discuss it?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Okay. I did not give any ruling that it should not be discussed. I did not say anything like that. Please, sit down. I did not give any such ruling. There is no such ruling.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: You cannot stop us from ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): I did not say like that.

SHRI N. JOTHI: What could be *sub judice* ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PFOF. P.J. KURIAN): No, I did not say ...*(Interruptions)*

SHRI N. JOTHI: But the fact remains that it has been tapped. That can be discussed here.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Yes. I did not say more than that. Mr. Jothi, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am not going into the merits of the case, though on umpteen number of occasions in the vary House, we discussed Ayodhya, and we are discussing so many issue. But I am not going on that point.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, we have been talking about phone tapping for the last one-and-a-half years. The Home Minister has categorically said that it is not being done. It is proved that it is being done. What you have to say? सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या हुआ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): The Parliamentary Affairs Minister has said that it is already in the court and the inquiry is going on. I think that should satisfy you. No. That is over. Now, let Mr. Naidu continue. Nobody else should disturb now. How many more minutes do you want?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My partymen are looking for it. Sir, my point is that when serious allegations are made and that too by Members of Parliament, Chief Ministers and senior people, and now the name of judge has also come, it is the bouden duty of the Government to respond immediately. MTNL is a public sector organisation. I am not saying that MTNL should not do it and Reliance can do or Bharti can do

or somebody else can do. Nobody. Even if a private operator does this dirty thing, it is the duty of the Government, that is the only mechanism. Otherwise, my friends will say, देखो, हमने कहा है, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा? आपकी प्राइवेसी चली गई। यही बोलने वाले हैं आप।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप असली इश्यू पर नहीं आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बंद कराइए, तब होगा न। ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Privatisation does not mean that we are selling our properties to China or Russia to any other foreign countries. After all, we are giving it to the people. We have a difference of opinion. Like what you are doing in Bengal also. You have listed some thirty-forty companies for giving to private people, which is a partial disinvestment.

Sir coming to this ...(व्यवधान)... आपका शासन नहीं है, फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... If it is in the larger interest of the country, if something is being done by this Government, I am not here to blindly oppose each and everything taken up by this Government. Simply because I am going by Rajdhani and suddenly I find Dipankar Babu in the compartment, I will not get down, saying no, no, I won't join him and if I go to Kolkata, then I will be misunderstood. I have no problem at all on these things, even with the Government also. Our leader, Shri Advaniji has made a clear-cut offer to the Government that, on issues, you discuss with us and take us into confidence. We can work together on larger issues concerning the country. There is a place for honest difference of opinion. You also have some difference of opinion on this issues.

Then coming back, they have assured in the CMP that there won't be any contentious issues. Another important point was, the focus will be on *Aam Admi*. Contentious issue नहीं होगा, मगर उन्होंने किया है। पिछले 18 महीने में जो डिस्कशन हो रहे हैं, वे डिस्कशन हो रहे हैं 'मित्रोखिन' पर, 'वोल्कर' पर, 'क्वात्रोची'- पर, पर देश का जो पैसा है, वह बैंक में जमा किया है। भारत का Additional Solicitor General of India goes without the permission. This never happened. He can't leave the country to my knowledge. I am also one advocate. I could not practise. Madam put me in *jail*. So, I could not get an opportunity. From there, I came to politics directly from *jail*. Sir, I was studying and I invited Shri Jai Prakash Narayan. Putting that as a reason, they put me behind bar for seventeen-and-a-half months. Then, I came out, took another

direction and came into politics. Otherwise, I was to become an advocate and I would not have the problem of facing Mr. Narayanasamy and others because in courts, normally, interruptions are not allowed. But in Parliament, yes, we have a lively debate. We do discuss and we also have the sort of interruptions and all. So, that is the situation, Today, all the issues—text-book change, denigrating Jaats, denigrating Sikh community, denigrating Brahimns, denigrating some others. Even 'महावीर', 'तीर्थांकर' है ही नहीं। है या नहीं, यह विश्वास की बात है। अभी हमने देखा उस Danish कार्टूनिस्ट को। वह पागल है या क्या है, यह मुझे समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति के विश्वास का अपमान करना कोई किसी का अधिकार नहीं है। You may have right to speech, you may have right to expression, but at the same time, your right to expression should not hurt or offend the feelings of the other side of the people who are large in number, even though they are in minority. But, उसको लेकर जिस तरह का विवाद छिड़ गया। हमारी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय ने बयान दिया 51 करोड़ देंगे ऐवार्ड। ऐवार्ड या रिवार्ड, मुझे मालूम नहीं है। 51 करोड़, how can a Minister, being in the Government, makes such statement and still gets away with that? Who is vitiating the atmosphere? Is is BJP? Text Books का मामला आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का मामला आपका है, आपको देखना होगा। सर, अभी एक अखबार में दिखाया गया, they have shown cards-like situation in India Today. The first one is, the Prime Minister saying about the minorities and all as if minorities were not at all concerned for the last fifty years; then, Mr. Rajsekhar Reddy, the Chief Minister of Andhra Pradesh, a Congressman, brings a Bill and the Bill is struck down by the court; then, Shri Arjun Singhji announces a National Commission; then, competition by other political parties also; then, it is also talked about, approving communal reservation for the Muslims in the PG courses in the Aligarh Muslim University; then, hindsight reservations in IITs and IIMs and then you come to the survey of headcount in the Army. It is atrocious; blood is boiling. Sir, I belong to BJP, but I am not a religious person. I believe in God. Recently, I went to Tirupati. I offered my prayers. Once in a while, I do it. But I am not a deeply religious man. But the very news that there is going to be headcount in the Army has disturbed me like anybody else in the country. The entire country has been outraged and astonished. Why is this being done? And they have not yet told, this is not being done. They are trying to give different interpretations. They are trying to find out their status, their position and all. Army means

discipline; Army means dedication; Army means devotion; Army means determination and patriotism. With that spirit, they have joined Army. That's why they have not mentioned religions; they have mentioned regions. From different regions people are recruited in the Army and they have to fight our enemy who is using religion for the furtherance of their cause. And that being the case, we being here and with such neighbours using such tactics, if you start this, where it leads to?

I am really frightened to imagine and think about this very divisive and sectarian thing, and it is capable of having a potentially of dividing the nation further, and ultimately, it will go for communal reservation in Parliament and Assemblies. Our Constituent Assembly framers were great leaders. They discussed it in depth. It is not that they did not have foresight, but they dropped the idea. They disagreed saying that no such thing should be done. They were great people who have become the President of India twice or thrice, the Chief Justice of the Supreme Court. They have risen to their positions not because they are Muslims, not because of their community. They are great people. We salute them. We salute the present President of India. There are Air Marshals, Supreme Court Judges, President, Vice-President earlier, all these things have happened in a normal course because of their merit. And now, we are talking in these terms and sowing seeds of that mentality in the younger generation of the country. History will not excuse us. Please note. I am not trying to join a political debate on this issue. Of course, you give your version, and I give my version outside. But, in the House, I take this opportunity, while speaking on President's Address, to request you to please clarify, put an end to it, put a full stop to this divisive idea. They know that this can not be done. But they want to show this to the people हमने तो इसके लिए प्रयास किया था, बीजेपी वालों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, इसमें और क्या किया जा सकता था? ...(व्यवधान)

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): वे तो आप ही के साथ-साथ हैं।

† [شری ابو عاصم اعظمی : سر، میں مسلم کمیونٹی کا ہوں۔]

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: ठीक है। सर, वे एक मैसेज देना चाहते हैं, यह गलत मैसेज जा रहा है, यह अच्छा मैसेज नहीं है।

सर, अभी मैं एक चीज कोट कर रहा हूं,

† Transliteration in Urdu Script.

"It is a misguided exercise and will only embarrass the Muslims serving in the Armed Forces," says Major General (Retd.) Afsar Karim. That is the feeling of even Muslims. Call it Muslims or Hindus, they really feel shy and ashamed. So far as the Army is concerned, Abdul Hamid is a great man. How many people have laid down their lives for the sake of the country? So, if you get into this, it may temporarily be of advantage to you. But it is not going to help you permanently. You have seen what has happened in Kerala. Our other friends have seen it in other States also. Beyond a point, if you try to communalise these things, then, it will boomerang on you. So, for the sake of God, don't get into this. Already, we are not able to rise above these considerations, take the country forward, and set up good examples at these levels. If the Ministers are using such a language, they should be dismissed forthwith, and they should be proceeded against also. Otherwise, there will be some more statements like that, and I have seen the Central Government washing off its hands saying that the law and order is a State issue. It is a violation of the Constitution. There is a Governor, who is supposed to be the representative of the Centre. He is supposed to send a report to the Government of India. Your Party should also take a note of it that they are not going to benefit by this competitive populism in U.P. It is not going to do good to anybody. This issue also has to be remembered.

Sir, IMDT is another issue. The Illegal Migration Detection Tribunal came after so much struggle by the youth and people of Assam, and then, there was a great disappointment because, the onus of proving that x is a foreigner, lies on the person who says that he is a foreigner, whereas, in the Foreigners Act, if there is an allegation or accusation against x, y or z that he is a foreigner, the onus lies on him to prove that he is not a foreigner. He is an Indian. I am told that the Government of India is thinking of changing the Foreigners Act, bringing IMDT in the entire country. It will be atrocious and will be disastrous. As I told you for the time being, you are having tough time in Assam. It may or may not help you. I do not know how it is going to help people finally in Assam. But in the long term, this thinking of bringing the IMDT across the country will ruin the unity of the country. Please, for God sake, for the sake of the unity of the country, let us not move in that direction. This is another suggestion which I am giving during my speech on the President's Address.

Then, coming back to the economic situation, Yes, the economy is moving. My friend, Shri C. Ramachandraiah, is having more knowledge than me on economic issues. He is going to speak, and he will throw further light. We have handed over to you a resilient economy. This resilient word is not Mr. Venkaiah Naidu's word or Mr. Atal Bihari Vajpayee's word. This is there is the Economic Survey, presented by this Government to Parliament. We have got the resilient economy, highest foreign exchange reserves, lowest inflation, very positive atmosphere for investment, a competitiveness not to go for strikes, but to produce more.

Now, that atmosphere is getting affected because of your Alliance politics. We have seen what happened, also recently, at the Airport strike. A wrong signal has gone. Definitely, the workers' concern has to be addressed. It is the duty of the Government. You need to have a dialogue and a debate with them to sort out the issue. If you go for this and put a lot of inconvenience to public, then a wrong signal will go.

Sir, today, coming to the trade deficit, in the last 20 years, our trade deficit was 5-8 billion dollars. Now, this year, in the first nine or ten months, it has gone up to 30 billion dollars. It is very, very disturbing. And compared to this, we are not able to produce more foodgrains. The per acre production in China is 60 quintals, per hectare; in India, it is 30 quintals and in a small country like Indonesia, it is 45.5 quintals. This is the situation. We have to focus our attention on this, not on the Aligarh Muslim University, reservation after 50 years.

उनका कुछ उत्थान नहीं हुआ। Are you accepting that you could not do anything in the last 50 years? Is it your stand that you have neglected the minorities and you are now concerned about them because you lost base and you came to 148 from 448, from Rajivji's spirit? Have you forgotten the Shah Bano case and its side effects? Please focus on this rural credit, rural infrastructure, and drinking water.

Swajaldhara has gone; Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna is at a very slow pace. And, then, you have the problem of river linkage, which is being talked about by everybody. We have set up a Task Force, headed by Shri Suresh Prabhu. Excellent work has been done; everything is ready. You are taking 18 months to move further on that very important initiative. Focus your attention on river linkage. Do good things; earn a good name; we have no problem. We have no problem, Sir.

SHRI N. JOTHI: It is difficult for them.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is difficult for anybody, for that matter It is not easy. Saying is easy, talking is easy, but walking is very difficult! ...*(Interruptions)*... It was a Report prepared by our Government. Whether a Task Force is there or not, hundreds of Task Forces have been appointed by our Government, but the task is not being done. And the force also will go because already, 20 months are over.

Narayanasamyji, 20 months are over out of the 60 months' period. Its one-third period is over. The honeymoon period is over. That is why, our friend's tone and tenor also has changed. And I also read a statement from my friend, Shri Sitaram Yechury, that the Left will not only bark but will also bite! ...*(Interruptions)*... The bites now given are only sound bites, not real bites! I do not want him to bite also because Manmohan Singh is such a nice man, a good man ...*(Interruptions)*... Sir, the testing case for the Communist friends and the Congress is EPF, the Employees Provident Fund. ...*(Interruptions)*... You accused us, the BJP, by saying that we are anti-workers. We made it 9.5 per cent. You joined with them. You are representing the labour, according to you, and you have now weakly and meekly accepted 8.5 per cent! ...*(Interruptions)*... And we reduced the interest rate from 16 per cent to 9 per cent in the agriculture sector. The Finance Minister has said, "You do not reduce. You advised" Okay; we advised. You also advise, now, the Reserve Bank to reduce it further and, then, make farmers happy. Women Self-Help Group is a socially, revolutionary movement across the country, the Self Help Group Movement. I am part of it because I was there as Minister for that Department. You will subsidise the interest on that. For that, what is wrong in giving subsidies? You are giving subsidies to industry, you are giving subsidies to export, you are giving subsidies to others; I am not objecting. But why don't you give subsidies to those helpless women? Andhra Pradesh is giving now. Panchayati Raj elections are coming. They are giving. Tamil Nadu also is giving. ...*(Interruptions)*... But they are saying that the elections are coming in Tamil Nadu also. ...*(Interruptions)*... But my point is ...*(Interruptions)*... On that, let there be a competition, on giving cheaper credit, timely credit, to Self-Help Groups, weavers, toddy-tappers and fishermen. They are suffering. This is another issue on which I want the Government to focus its attention.

And coming to the black money, there are estimates of two lakh crores of black money that is available in the market. The Government should come out with some steps to see that the black money is unearthed. And there are reports—and if the reports are wrong, I will be happy—that Rs. 80,000 crores are non-performing assets in various public sector banks. Who are holding this money? Why are you hesitating to publish those names, and, then, proceed against them? If they are helpless people, okay; what you call insolvent. If they have become insolvent, okay; I have no problem. But you are attaching the farmers' properties. And you are not able to do it. बहुत बहस चला इस देश में, हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं।

The BJP feels that industry. Industry and agriculture are two eyes of the country. We have to give them importance. Agriculture needs preferential treatment because there is no level playing field. Coming to television, the channel of communication, nothing has been said. It is really sometimes frightening to see television along with family members. Then there is a big debate whether we should allow this or that or not. No focus has been made on that particular issue. With regard to Sarva Shiksha Abhiyan, there is further need for more focussed attention on Sarva Shiksha Abhiyan which is very vital for strengthening our country. Then IT is given concessions. BT is being also talked about. Yes, there has to be a combination of IT and BT. It is our duty to see that IT and BT get equal preference. That makes the country's beauty. Then the country can move forward.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are a poet.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not a poet. I am an ordinary agriculturist's son, which you don't know. I don't have any poetry capacity. I don't have much knowledge either in Hindi or in English. I speak common man's language. I am still getting on with that because you people are able to tolerate me. When I go to the north, I speak Hindi also. मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैंने हिन्दी बचपन में पढ़ी नहीं है। दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत में आकर हिन्दी बोल रहा है इसलिए लोग तालियां बजा रहे हैं। हिन्दी सीखनी चाहिए, लेकिन देर हो गयी। Thanks to our friends, usually, I was also tempted. I went to the railway stations to put tar on Hindi boards and later I realised it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The BJP did not appreciate you talent. I am appreciating your talent. You mentioned Kusthi, dosthi, right, beauty, duty, etc. The BJP did not appreciate it. I am appreciating that talent, at least.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is the BJP which made Venkaiah Naidu to this position. From High School to College to University to Yuva Morcha to State to Centre, I held every post in this party. The only post that was missing was the post of Vice President. I became the Vice President also after becoming President. I have no problem. I am now experimenting a new system that without post also you can work for the people. This experiment I have chosen for myself. My friend has just made a comment. I am sorry for bringing in personal thing; otherwise, they are not part of our debate.

Coming back to running of the Government, take your friends into confidence. At least, you take them into confidence; you tell them where do they stand. Are they doing it only because of Bengal and Kerala elections? Or, is it because of serious concerns? If it is because of serious concerns, they should address their friends. They may ask, "How are you bothered?". We are bothered because you are proposing something and they are opposing. It is openly appearing that they are opposing.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, your concern is about yourself.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: As regards the House, please have patience. Hear the other side. Rebut them more effectively. If you are lacking in that, your friends are there because they are more anti-BJP than pro-Congress. That much I know. They are there to supplement your efforts.

Sir, with these words I have expressed my views on the Presidential Address and I take your permission to close my remarks. Thank you.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. After an eloquent presentation by Shri Venkaiah Naidu, who has covered all the aspects pertaining to polity, economy, industry, etc., I don't think that anything is left to add except a few comments.

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, आधे घंटे का लंच कर दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, आधे घंटे के लिए लंच कर दीजिए।...(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): I think since there is shortage of time and we want more Members to participate, we will continue with the discussion.

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, half-an-hour का लंच कर दीजिए। ....(व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI: We can have half-an-hour lunchtime.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It has already been decided "one can have lunch, but no lunch break".

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Yes, Mr. Ramachandraiah has given a good suggestion. One can have lunch, but no lunch break.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I congratulate Mr. Venkaiah Naidu who has really given a speech like a statesman covering various subjects and making sound suggestions for the improvement of polity and the economy of this country. He said-it is a proverb—"Wise people learn from other's experiences and fools try to learn from their own experiences".

Let us be wise. The President of India said, "We are achieving 8 to 10 per cent growth. Very good. Very good edifice has been created by the earlier regime and now the next regime is trying to build on that edific.

2.00 P.M.

I would like to quote one survey of the Chinese economy. Chinese economy is worth 2.3 trillion dollars and their growth rate is 9 per cent for the last 12 years. In spite of that they could find—very clean observation they have made—a lot of economic disparities and urban-rural divide. Now they are seized of the matter. This is happening in this country also. I was privileged to speak on the similar subject earlier. The so-called reforms which have been introduced in this country have yielded results. There is no doubt about it. But we need a harmonious society. We have to build an imbalanced society. It has been enshrined in the Directive Principles that economic disparities have to be removed. Sir, may suggestion to the Government is, let us not beat our own drums that we are going to achieve 8 per cent to 9 per cent growth rate. Just by exceeding 10,000 mark in the Sensex or by achieving the 8 per cent growth rate or

by accumulating more foreign exchange reserves, the real problem, the problem of common man cannot be addressed. The President of India has said, "It is an inclusive society". Sir, I will quote certain figures as to what extent this society is inclusive. India, information technology giant and would be the super power by 2020 as written by international level economists and papers, is at 127th position among 177 nations; 34 steps below Sri Lanka, 64 steps below Brazil and 42 steps below China. You see the level of grading. The starting fact is that in terms of child mortality rate, Bangladesh has shown remarkable progress as compared to India. Bangladesh is a small neighbour of India and it has performed much better than Indian. Fifteen years back India decided to immunise 100 per cent children. In 2005, the achievement did not exceed 42 per cent. The result is that one in five children dying in the world is an Indian. Twenty-five lakh children die every year before they are five years of age. This is the sorry state of affairs which we can't boast of. I am not blaming the present Government or the present dispensation. These are all naked facts. On the economic front, the rural economy is virtually stagnating. It is virtually stagnating and rural wages are falling. Whatever progress we may have achieved, it is a jobless growth. The planners have to take into consideration how this benefit of development can trickle down to the common man. The most dangerous thing is jobless growth. We have been discussing about the subject since so many years. During the 90's when the Congress Government was in power, for every one per cent rise in GDP rate, there was three per cent unemployment. The value of one per cent GDP was around Rs. 16,000 crores. Of course, it is Rs. 25,000 crores today. But the percentage of growth in jobs is zero. Again I repeat my own economic theory. Sixty-six per cent of the population still depends on agriculture. I am not able to quote that paragraph, as I am not finding my papers. Anyway, he has said that the Government has taken care of the rural economy, the farmers' interests. Sorry, it is far from true. Of course, the President of India reads out whatever speech is prepared by the Government and which is endorsed by the Cabinet. But it reflects the opinion of the Government.

Sir, the capital formation in agriculture has gone down. The capital formation in irrigation has gone down; this is a vital input in the development of agriculture. And, the savings has gone down. There is a large contribution to GDP from the social sector, that is, 51 per cent, and every year, the contribution from agriculture is going down. It is a very

alarming picture. And, 51 per cent of the GDP is being contributed by services. Unless you improve the economic standards of the common men, who constitute the major section of the population, who is going to utilise the services which are being created? The only way is outsourcing to other countries. How long will you depend on other countries? Let domestic consumption take precedence over export markets. If at all excess production is there, then, you can export. But when your own people are starving, when your own people are deprived of the services which they are unable to produce, we cannot say that we have strived for the welfare of the society.

Another important thing is that the share of consumer spending has to be increased in this country. No doubt, the consumer rate has gone up. But that pertains only to middle-class population. When we take the spending of the people below-the-poverty line, that has gone down considerably. It is an alarming picture, and that has to be increased. So, let us produce for our own people first. It means that the products or services which are being produced in this country should be made available to our own people at an affordable price. That can be possible only by reducing the cost of production of goods or services and by increasing the economic standards of a major section of the population, which is the common man. It has got a cyclic effect. If you are able to improve the economic standards of the common man, if a major section of the population can buy more goods, then, we can have a kick-start in the economy; industrial activity will be more and you can produce more goods. There will be more investment. When the purchasing capacity is more, they can save some money. And, these savings can be channelised to the industrial sector, and the capacities can be increased. Sir, I am sorry that the planners have not taken this into this consideration, and we are trying to make mere cosmetic changes in the economy. Who is contributing to the census? It is the 38 or 40 companies, and a major percentage of the GDP is coming from a very few industrial houses in the manufacturing sector. Then how can we say that we have achieved a balanced growth? It is far from true. The President has said that this Government is very judiciously managing the public finance. As Mr. Venkaiah Naidu said, by allowing the amounts to be withdrawn by the accused from bank accounts, is it a judicious way of managing public finances? As per records, he is an accused. And does this method of releasing funds amount to judicious management of public finances?

Then, you have announced the Sixth Pay Commission. For whom have you announced this? It is to please 25 lakh employees. What will be its impact on the States? and, this country is being ruled by the Prime Minister—it is not sure whether he is ruling or somebody else is ruling, but for the outside world, he is ruling—who is a renowned economist. Sir, I can tell you the chaos that was created in the economy when the Fifth Pay Commission report was implemented. In 1996-97, the burden was to the extent of Rs. 21,865 crores.

It has gone up to Rs. 43,568 crores in 1999-2000, that is, within a span of three years. It has got an impact of Rs. 23,000 crores on Central Government's Budget and of Rs. 38,000 crores on the Budget of the State Governments. The States are virtually reeling under deficit financing. And have no concern for the precarious financial position that the States are in! I read in the newspapers the statement of the Prime Minister that the States have surplus funds to the tune of Rs. 40,000 crores. I do not know where the surplus funds are. The States in this country are surplus with funds! This is a very strange argument extended by the Prime Minister of this country. Either that publication is wrong or I don't know what it is. Sir, have you taken the concurrence of the States? What right does the Government of India has got to impose it on the States? The moment it is announced, the State Government employees will also demand a Pay Commission. They will also demand that the recommendations of the Pay Commission should be implemented. After a prolonged struggle, the Twelfth Finance Commission has increased the devolution of funds from the Centre to the States by one per cent. And by transferring Rs. 26,000 crores, which has been the impact of that one per cent increase, every time you have been saying that you are unable to bring the Fiscal Responsibility Amendment Bill; you are keeping it on hold because on this one per cent increase of the devolution of funds. What will be the impact of this? You want to hold the implementation of that for still more years. Where is the rationality? And you want to play a havoc with the economies of the States. And you collect huge taxes from the people of the States. The Centre does not have any people with it. They have to impose the taxes on the people of the States and collect them and you want to control the State economies also totally without the consent of the people of the States. It is a very sorry state of affairs, Sir.

It is a very wrong decision that has been taken. He should have consulted the States. You have got no right to impose such a huge burden on the States.

Sir, I am trying to restrain myself from making these comments but I feel compelled, honestly. I fully endorse the views expressed by Venkaiahji. Our Prime Minister is a clueless Prime Minister. Is he aware of the vital decisions that are being taken in this country? The Congress Party is achieving some sort of a target of searching for scapegoats. It has achieved a hatrick! For every vital decision, I have seen the Prime Minister claiming his ignorance. A new trend has been created in the history of this country, in the history of the parliamentary democracy in this country and, that is, that the power is being exercised without any accountability to the nation. No accountability! Absolute power is being controlled. This is a very, very bad precedent that is being created in this country. They should own the responsbility. It is the greatest extra-constitutional authority prevailing in this country. It is very bad. The country has paid a very heavy penalty for these elements. Such elements should not be there in the Indian polity. He is virtually a clueless Prime Minister. For everything, he has no clue and he claims ignorance. Sir, I was under the impression that it is a dual power centre. No. Multiple power centres are there. Multiple power centres!

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Why such remarks?

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It is nothing unparliamentary, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no. ...(*Interruptions*)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): He is expressing the truth. What is wrong? (*Interruptions*) There is nothing unparliamentary, Sir. (*Interruptions*) He is expressing the truth.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, my desire is that as a Member of Parliament representing some people, we need an authoritative, full-fledged Prime Minister in this country. We need an authoritative, full-fledged Prime Minister for this country.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. C. Ramachandraiah, when you refer to constitutional authorities, you should keep the dignity of those offices.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It is not an undignified comment, Sir. ...(*Interruptions*)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Today, it has come in the papers, Sir.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, it is the experience of the people of this country. ...(*Interruptions*)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, there is a letter from the 10 Janpath ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, he is only describing what is happening in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): This is not the way.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, as a citizen of India, I cannot expect the Prime Minister of this country to be a symbol of hidden power centre.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no; such remarks will not go on record.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this is not just my opinion. This is the opinion of the people. ...*(Interruptions)*... We want the Prime Minister to be more dynamic. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no. Okay, you please speak on President's Address. ...*(Interruptions)*... Don't go beyond that. Don't make such remarks.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, he is speaking on President's Address only. He is speaking in the House what the people are thinking

outside. What is wrong in this? ...*(Interruptions)*... It is not unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: On the Volcker issue, you had succeeded in making Mr. Natwar Singh as a scapegoat; on the Bihar issue, you succeeded in making Mr. Buta Singh as a scapegoat, and in the Bofors case, you made the CBI a scapegoat. How long will this continue? Umpteen number fo times the Prime Minister has claimed ignorance about the issues which are affecting the nation! Is it not my duty, or, my right to expect a dynamic Prime Minister, who is involved in all decisions of this country? I have got a legitimate right, in this regard. It is not kindness that you are showing to me.

Sir, for the past three months or so, the country has been treated on a list of subjects about which the Prime Minister knows nothing. As I said earlier, there was the Volcker issue and the case of telephone tapping, it was very elaborately explained by Venkaiahji, about which the Prime Minister said that he was completely in the dark. And, now, we have the curious case of the Prime Minister who was carefully insulated from dramatic developments involving the Bofors case. The two Ministers did not care to keep the Prime Minister informed about it. They had taken their own decisions and sent the message. They had deputed one senior officer so that the funds can be released. The Prime Minister has claimed innocence about it. What sort of administration are we getting? Sir, we expect the Prime Minister to be a real Prime Minister. We want a real Prime Minister in this country, not a* representative.

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): He is the real Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no; that will not go on record.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, if it is unparliamentary, you can remove it from the record. ...*(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, he can cite the word* ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no; you cannot make such personal remarks about the Prime Minister, or, anybody who is a constitutional authority. It will not go on record. * will not go on record.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, there is the recent judgement of the Supreme Court on the dissolution of the Bihar Assembly. Is it not the duty of the Cabinet to seriously consider it? You had dictated to the Governor of Bihar to send such report. In the midnight, you convened a meeting and you recommended for a dissolution of the assembly. And, now, you want to disown the responsibility, and made that poor chap a scapegoat. How long will it continue? Irrespective of party in power, this game is going on, using the institution of the Governor for political purposes. Sir, that is why the Telugu Desam Party has given its opinion on this issue. We had deposed before the Sarkaria Commission saying that it was the legacy of the imperialist British regime that we had inherited. We don't have belief in this institution of Governor. Let there be some alternative arrangement be made. Sir, this institution should not be utilised for political purposes in dethroning the elected Governments, as your illustrious party had done it by removing Shri N.T. Rama Rao in 1984. There is not just one case. There are a number of cases. Venkaiahji has quoted a number of cases, whether it is Goa or some other State. The Supreme Court has accused, not only the Governor but it has also accused the Government of India, it has accused the Prime Minister. And if you want to be so insensitive, then, we cannot help it.

Sir, with regard to the tribal rights, very proudly, President's Address had mentioned that the Government has introduced the Bill to protect the tribal rights. Sir, they have been fighting to protect their tribal rights. I have been observing this for the last sever-eight years. Who had prevented you from introducing this Bill? Who had prevented you from doing that?

*Expunged as ordered by the Chair.

I am rather constrained in quoting the name, but an influential person from the ruling clan has obstructed it. He is not interested. He is not interested int he introduction and passing of this Bill. And you claim that you are very welfare-oriented of the tribals while lakhs of people are being displaced in mega projects in Kolavaram and other areas. What is the concern you have shown? Mercilessly you are trying to remove the Narmada Valley Projects and other projects in Uttranchal. Nobody has prevented you from passing this Bill. What is the objection you have got towards it? Sir, the Scheduled Tribes Recognition of Forest Rights Bill was introduced in Parliament only after the intervention of the judiciary. Attempts are being made in the last minute not to grant the land rights to tribals by an influential group of Members of Parliament and polticians who call themselves Tiger and Wilderness Watch. This is an institution which has been promoted- Tiger and Wilderness Watch - TEWWE, and you are aware who are the persons responsible for the promotion of this institution which is obstructing the passing of this Bill. You have promised in your manifesto and in the UPA's National Common Minimum Programme that land of millions of tribals and forest tillers remain undisputed or unacknowledged over decades due to lack of proper records. So, you assure them that you will maintain it and you will set the record right and protect their rights. Till now you have not initiated any action even after a lapse of 20 months. And you say that only a Bill was introduced. Sir, I come to food security. This Address has not covered the food security. Sir, for the past ten years we have not imported wheat. The buffer stock we require for this country is about 16 million tonnes and our present stocks are more than 16 million tonnes. Unambiguously, the Agriculture Minister has to make a statement on why we are importing wheat. Is it to cover the component of the National Rural Employment Guarantee Scheme? Now you are covering 200 districts. For 600 districts, you are require 18 million tonnes. Are you running short of foodgrains? Are you requiring more foodgrains to cover this programme? So, what exactly is the position? The present indication says that Monsoons are very well in this country and we are expecting a good harvest. When such is the case, why do you import foodgrains? The Parliament has to be taken into confidence. There are certain issues on which you are not

taking the Parliament into confidence at all. For example, about the revival of Dabhol, till today you have not come to the Parliament saying that this is being done. It is such a controversial issue. You have created a special vehicle. ...*(Interruptions)*... To what extent the Government of India is making a sacrifice in this and to which extent Dabhol is getting benefit out of it? Dabhol itself is in doldrums. You are totally keeping the entire nation in dark. It is not your personal *fiefdom,* it is not your personal property to manage and say, "I can restructure this project." If it is your personal property, your personal empire, then you do it. But it is a people's property. It is a very big project belonging to the people. You have to take the House into confidence and the Parliament has to give its opinion whether the Government is going on right lines. My request is, do not take such vital issues on your own. Take the Parliament into confidence. You say everything is trasparent. "Inclusiveness," I do not know the word "inclusiveness," and now a new word is being used "enlightened national interest." The atomic agreement that was entered into with the USA was in the enlightened national interest and opposing Iran in IAEA is in the national enlightened interest.

Sir, I will tell you, our foreign policy virtually is based on the non-aligned system that has been adopted by Nehru. There were three persons in the world who were promoters of this movement: Marshall Tito, Gamal Abdul Nazar of Egypt and our great leader, Jawaharlal Nehru of India. This was an edifice on which our foreign policy was formulated for non-aligned movement. Now I have to wonder to what extent India is non-aligned and you are going totally into the garb of the United States and what benefit the country is getting. I was of the impression and I think the entire world is of the impression that Nehru was more enlightened person and such an enlightened person has created an edifice of non-aligned policy, which provides guidance to successive Governments to formulate their foreign policy, and now you come out with a concept of enlightened national interest. The earlier rulers like Nehru, Indira Gandhi, were they non-enlightened? Were they not enlightened? I do not know what is the concept that is being used and adopted and how the interest of India is protected when you are opposing Iran. Iran stood with India at very critical

junctures. I don't want to go into the electoral guise. As a layman I am asking: in what way our interest will be protected by opposing it? Could you prevent China from going nuclear? Could you prevent Pakistan from going nuclear? We accept the global policemanship of United States. And what is the advantage that we are getting? You want to play a global leader role along with United States. I do not know what is that enlightened national interest. We feel national interest is on the other side. On energy security, we have been talking about pipline from Iran to get gas and Mani Shankar Aiyar's contribution was substantial in making a breakthrough. Poor chap, all along he has visited so many countries and he was trying to insulate this country from the energy insecurity. He wants to insulate the country with the security of the energy requirements. He has been removed. That is the Prime Minister's privilege. I do not want to question it. Is it linked with the United States? Is it linked? Some people have asked me. I said I do not know, we have to ask the Prime Minister. Is it because he is more interested in Iran that is why he has been removed from the Cabinet? Or is the replacement out of the insistence of somebody? What is the enlightened national interest? Kindly take the Parliament into confidence and explain. Sir, I come to women's reservation. I was rather indecent in making a comment while President of India was reading this. He said, 'political reservation in legislative bodies to women will be made in the near future.' I asked, 'your Excellency, when is that near future? Major parties are interested in reservation, you are interested in reservations, they are interested in reservations and we are interested in reservations for women. What is the constraint? Who are opposing it? It is the number game. You have got the numbers. Why don't you pass it? Neither they could pass it nor you are passing it.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are supporting you.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: At least I had one supporter there. I am more privileged and I have been enriched.

SHRI V. NARAYANASAMY: For the right cause we will support you.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: You have made the President to say 'decriminalisation of electoral process and politics'. Are you really

interested in decriminalisation of politics and electoral system? Are you really interested? Then remove all the tainted Ministers from your Cabinet. Very eloquently he has been presented. I don't need to elaborate. We have to publish in the newspapers about some Ministers that some Minister is wanted. That was the sorry state of affairs. We have to publish in the newspapers that so and so Minister is wanted and if anybody brings him, he would be richly rewarded. Such a kind of tainted Ministers you are keeping in your Cabinet. Your allies have got some criminals in the Cabinet. And, you want to say that you are trying to de-criminalize politics and electroal system! Yesterday, in a by-election, in Visakhapatnam, we have seen to what extent you have criminalised the politics and it is known to the entire world. The Election Commission, for the first time in the annals of history, has to depute two observers to make a study on the spot before they order for counting. That is the sorry state of affairs.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Ramachandraiah, time allotted to your party is 27 minutes. You have already taken thirty minutes. So, please try to conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I am concluding, Sir.

SHRI N. JOTHI: Sir, Opposition should be given more time than the Ruling Party.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): I am only making a statement of fact that time allotted to his party is twenty-seven minutes and he has taken thirty minutes.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I am concluding. Sir ultimately, they are losing their conscience. That is my worry ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): You address the Chair...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I will sum up, Sir.

I urge tl ' overnment not to try to trample our national interest. Don't try to r ..e extra-Constitutional authorities. You have got the power.

You are leading a coalition with twenty-three partners. Well. Very good. Do it. They have done it. They have done it extremely well. And, you also do well. That is our desire. But, let us have the pride of this country being ruled by a renowned economist who is competent to take any decision. It is only then we feel proud. Otherwise, if somebody is interested, let them come to the forefront. Let them come to the front. Nobody is objecting. Let us not say that there is 'inner voice' or some other excuses. Let them come to the front, take the reins and lead the administration.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Finally, Sir, I want to say one thing. There seems to be a confrontation between the Legislature and Judiciary. This has to be avoided. So, I request the Government to take all the political parties into confidence and convene a meeting and try to erase the confrontation. The role of the organs of democracy is to supplement and complement to each other. It is clearly defined. If one organ is weak, the other organ will takeover. If the Legislature is strong, then Judiciary cannot be overactive. When we are failing in solving the problems of the people and sending the same to the Judiciary. Judiciary will, naturally, become active. So, the role of every organ is clearly defined and there should not be any misunderstanding. This atmosphere is not good for the democracy of the country. This has to be taken note of by the Government and it should take all political parties into confidence and try to solve it.

My last point is....

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, I am on a Point of Order. Sir, there is no Cabinet Minister in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There is a Cabinet Minister sitting here. Mr. Soz is there.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: So, Sir, ultimately, my request to the Government is this. You have to concentrate more on farmer's welfare. You make more investment in agriculture which can cater to the needs of nearly 70 per cent of the people. Create more employment opportunities

by investing more in the infrastructure. That can be possible only when you are able to improve the economic standards of the common man. The hon. President has suggested for increase in the savings. This is possible only when you improve their economic standards. Those savings can be channellised to the productive sectors. Only then, you can achieve this 8 per cent economic growth. Sir, 8—10 per cent growth rate is not a panacea of solving all the problems. It is needed. High growth rate is needed. But, as long as the fruits of development does not percolate to the common man, the purpose is not served; our mission is not fulfilled. So, I request the Government to kindly take care of all these issues into consideration. Thank you.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, जो डा॰ कर्ण सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मुझे भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के भाषण सुनने को मिले, कल और आज। उनका कहना था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा कोई भी काम नहीं है, जिससे रोमांचित हुआ जाए। शायद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को उस पक्ष के हमारे माननीय वक्ताओं ने नहीं पढ़ा और न ही पढ़ने की हिम्मत की। उनके सामने एक ही बात थी-बहुत हताशा, बहुत निराश और जो पराजित हो जाते हैं, उनकी यही मनोदशा होती है तथा यही मनोदशा व मानसिकता उनकी झलक रही थी, क्योंकि जब से इस सरकार को जनादेश मिला है, डा॰ मनमोहन सिंह जी की इस सरकार को जनादेश मिलने के बाद के इन 20 महीनों में इस सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में एक नहीं, अनेकों कदम उठाए हैं। आज वे निराश हैं, जो कभी कहते थे-भारत का उदय हो गया, आम आदमी की आमदनी बढ़ गई, किसान के चेहरे पर प्रसन्नता है और उस अभियान में एन॰डी॰ए॰ और बी॰जे॰पी॰ की सरकार ने करीब 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी देश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से इस बात को याद दिला दिया कि उनकी सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल में देश में ऐसा एक भी काम नहीं किया, जिसका उल्लेख किया जा सकता हो। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, वेंकैया जी भी जा चुके हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, वे कहते हैं कि यह अभिभाषण आम लोगों की व्यथा के बारे में कुछ नहीं कहता है, यह आधा-अधूरा भाषण है, जो सही नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में सारा विश्व, सारा देश जानता है कि डा॰ मनमोहन सिंह जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, बुद्धिमता और व्यवहारिकता के माध्यम से इन 20 महीनों में गठबंधन की सरकार को चलाया है। हमारे वामपंथी साथियों के बारे में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग कई प्रकार की

बातें करते हैं, लेकिन वामपंथी इस सरकार का साथ बराबर मजबूती के साथ दे रहे हैं। उपसभापति महोदय, कांग्रेस का गठबंधन की सरकार को चलाने का यह पहला अनुभव है, लेकिन हम अपने वामपंथी साथियों को बराबर जानते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में नहीं हैं, जो बार-बार इस बात को कहता है कि वामपंथी भ्रम में हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे भ्रम में नहीं हैं। जो साम्प्रदायिकता के जहर को घोलने वाले थे, जिनकी सरकार के 23 घटक दल थे और उनमें किस प्रकार की सर-फुटव्वल होती थी, किस प्रकार की बयानबाजी होती थी, उस सरकार के कारनामों को, क्रियाकलापों को, उनकी गतिविधियों और कारगुजारियों को हमने बहुत करीब से देखा है।

महोदय, ये लोग कहते हैं कि देश में चार प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री डा॰ मनमोहन सिंह जी हैं और इन लोगों को यू॰पी॰ए॰ की चेयरपरसन से बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है इनको, जब ये सोनिया गांधी का चित्र कहीं पर देख लेते हैं। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी पर न मालूम कितने अनर्गल आरोप लगाए, किस प्रकार की बेहूदगी की बातें कहीं और किस प्रकार का भ्रम का वातावरण फैलाने की कोशिश की, लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा जो आप यूपीए की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इस बात की परवाह न करते हुए यह दिखा दिया कि देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। आज गठबंधन की सरकार बीस महीने से चल रही है और माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बात को बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि वे श्रीमती सोनिया गांधी की फोटो देख कर ही घबरा जाते हैं। जब वे सोनिया गांधी जी की फोटो देखते हैं, सोनिया गांधी जी के कार्यों को देखते हैं, यूपीए की चेयरपर्सन के नाते उनका सरकार को सलाह देना, सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी लेना और अपने गठबंधन के साथियों को साथ में लेकर चलने की उनकी क्षमता, यह सब देखकर वे घबरा जाते हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी विचारों को साथ लेकर, इस बीस महीने के अंतराल में हमने इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया है कि देश की सरकार अपने किए गए वायदों को पूरा कर रही है।

माननीय राजनाथ सिंह जी अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, वे कहते हैं कि हम रोमांचित क्यों हों। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर यदि हम एक नजर डाल कर देखें तो 1999 से 2003 के दौरान विकास की दर लगभग 5% थी, वहीं 2004-2005 में 7.5% की वृद्धि दर्ज करके डा॰ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि भविष्य में आने वाला समय एक अच्छा समय होगा। 2005-2006 में 8% से भी अधिक विकास की दर संभावित है। हमारे लोकतंत्र पर अर्थव्यवस्था का जबरदस्त असर है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख किया कि राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाएं हुआ करती थीं। उन्होंने यह बहुत सही कहा कि देश को जहां देश को तोड़ने की बात होती थी, देश में फूट पैदा करने की बात होती थी, अब उन बातों के स्थान पर देश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाया जा सकता है, ये सारी चर्चाएं होती हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकार। इन चार स्तम्भों को मजबूती से खड़े किए जाने पर ही लोकतंत्र की मजबूती होती है। डा॰ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इन चार स्तम्भों की नींव पर एक नया दौर प्रारम्भ किया है और मैं समझता हूं कि यह सरकार इसमें सफल भी रही है, वह स्तम्भ है ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम''। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यह क्रांतिकारी सामर्थ्य रखता है। विश्व में यह पहली बार हो रहा है कि एक बृहद् रोजगार कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आरम्भ में 200 अल्पविकसित जिलों में लागू किया गया है और यह कार्यक्रम निर्धनों के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कार्यक्रम हमें रोमांचित करने वाला नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, और तो और प्रधान मंत्री जी से यह भी कहलवाया गया था कि हम हर वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। मैं जिनसे यह बात कह सकता था, वे तो इस समय यहां पर उपस्थिति नहीं हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि छः वर्ष के कार्यकाल में इस सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आप बोलिए ना ...(व्यवधान)... मैं मानता हूं कि श्री मोती लाल वोहरा जी एक ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए, यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं यील्ड नहीं कर रहा, आप इनके चेहरों की ओर देखिए जो हताश हैं, निराश हैं ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि:*

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: जो इस बात को कहते हुए नहीं थकते थे कि हम अब इस सरकार में आए हैं और एनडीए की सरकार आने वाले चालीस वर्षों तक शासन करेगी। छः साल में ही हिन्दुस्तान की जनता ने उनके सभी कारनामों को देख लिया ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि:*

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए, आप बीच में इंटरेप्ट नहीं कीजिए, देखिए वे बुजुर्ग हस्ती हैं, आप बैठ जाइए।

---

* Not recorded.

श्री मोती लाल वोरा: मेरा कहना है कि हमारे उड़ीसा के साथी बहुत भोले हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गिरोह में फंस चुके हैं कि निकल ही नहीं पाते। उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। आप खुलकर बोलिए, लेकिन मैं आपको ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अलका जी, आप भी खामोश रहिए, वे भी खामोश हो जाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति महोदय, यह हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के संचालन में हमने यह नहीं देखा कि यह दो सौ जिलों में कौन-कौन से जिले में किया है तथा वहां किस-किस पार्टी की सरकार है, केवल हमने इस बात को ध्यान में रखा कि इन दो सौ जिलों में एक परिवार के एक व्यक्ति को सौ दिन का काम मिले। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की थी कि पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने का दमभोक्ती करने वाली पार्टी आज जनादेश के अभाव में परेशान है। सत्ता हाथ से निकल गई है, सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद में आज उनको लगने लगा है कि भारत उदय की बात कहना उनके लिए बहुत आसान था लेकिन भारत का उदय नहीं हुआ, भारत चमक रहा है यह नहीं हुआ।

तीसरा काम, भारत निर्माण की जो एक समन्वय योजना है और 2009 तक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लक्ष्य होंगे, देश के प्रत्येक गांव को बिजली उपलब्ध कराना, एक हजार की आबादी वालों को सड़क से जोड़ना, पांच सौ की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ना, हर बस्ती में पेयजल की व्यवस्था करना, टेलीफोन की व्यवस्था करना। क्या यह सरकार इस बात को नहीं कर सकती थी? सरकार की मानसिकता केवल यह थी कि कांग्रेस को हमेशा कोसना, कांग्रेस के 45 साल के शासनकाल में देश में अगर विकास हुआ, देश में अगर तरक्की हुई, देश में अगर उन्नति हुई, दुनिया के हर देश जो पश्चिमी राष्ट्र थे, जो विकसित राष्ट्र थे इस बात को कहते थे कि हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत के पहले प्रधान मंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू की यह सूझबूझ थी कि आज दुनिया के वे विकसित राष्ट्र भारत की बात को मान रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आज भारतवर्ष दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। यह क्या रोमांचित करने वाली बात नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को रोमांचित इसलिए नहीं कर रही है कि वे पराजित मानसिकता में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन नहीं चाहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई-बन्धुओं को, वहां के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलें। वे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते थे लेकिन इस दिशा में उन्होंने कौन सा कार्य करके दिखाया वह तो आज कहने की स्थिति में नहीं हैं।

आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वे रोमांचित हो सकते थे, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों से ही रोमांचित होता है और अगर यह अभिभाषण उन्होंने सही ढंग से पढ़ा होता, सही ढंग से उसे समझा होता तो फिर यह नहीं कहते कि इस भाषण में कुछ नहीं है। आजादी के बाद शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन सबसे बड़ा प्रयास है। 63 शहरों में लागू यह मिशन शहरी निर्धनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सर्वशिक्षा अभियान की बात कहती है। आज हम कह सकते हैं कि आज 12 करोड़ बच्चे इससे लाभांवित हो रहे हैं। और आगे इसमें जो पोषण आहार का सकारात्मक हमने प्रयत्न किया मध्यान्ह भोजन का उसका भी लाभ मिलेगा। क्या यह कार्यक्रम इनको रोमांचित नहीं कर रहे हैं, क्या हिन्दुस्तान की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि डा॰ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने गठबंधन की सरकार ने इन कार्यक्रमों को हाथ में लिया। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वसुलभता बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यक परिवारों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने से शैक्षणिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। मैं पूछ सकता हूं क्या, क्योंकि जिनसे पूछना चाहता था वे तो हैं नहीं और वे जानते हैं क्योंकि पराजय तो उनके सामने दिख रही है, उनकी मानसिकता किस प्रकार के कार्य कर रही है वह दिख रही है। किसानों के कल्याण की बहुत बातें करते थे। देश का किसान अगर सुखी रहेगा तो देश प्रगति कर सकता है, तरक्की कर सकता है। किसानों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि के क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान के दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और लगभग 14 हजार करोड़ का वित्तीय पैकेज भी इसमें शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रभावशाली बनाया जा रहा है और इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और सरकार इसको करने के लिए तैयार है। छोटे और सीमांत किसानों की जीविका में सुधार लाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना की जो शेष अवधि बची हुई है, उस शेष अवधि में वर्ष 2005-06 में 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है। ये जानकारियां इस बात को कह सकती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की बहुत बातें कही गई हैं। एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है और एक सौ पिचहत्तर हजार करोड़ रुपये वाली इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

भारत में विश्व स्तर के हवाई अड्डे बनाने की बात कही है। हमारी व्यापक नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है। दिल्ली, मुम्बई और उसके साथ में बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता आदि स्थानों पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। ... (व्यवधान)...

नगर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): मैं आपके पीछे आकर बैठ गया हूं। ... (व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: उपसभापति महोदय, मैं प्रफुल्ल पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सी दिक्कतें उनके सामने आईं, लेकिन अगर हम दुनिया के देशों में घूम कर देखें, तो हमें पता चलता है कि दुनिया के देशों के हवाई अड्डे किस प्रकार के हैं। इन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण दुनिया से आने वाले लोगों को विश्वास दिलायेगा।

रेल व्यवस्था एक बार फिर हमारे लिए गर्व का विषय बन गई है। सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का उच्च क्षमता वाले दो माल कारिडोर-लुधियाना से सोननगर तक पूर्वी कारिडोर और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से दादरी तक का पश्चिमी कारिडोर बनाने का निर्णय लिया है। देश में बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष बल दिया गया है। बिजली की बात बहुत किया करते थे हमारे भाजपा वाले और एनडीए की सरकार के समय में बिजली के उत्पादन की जितनी गिरावट आई, आज उस गिरावट को सम्भालते हुए देश में बिजली की स्थिति को सुधारने में विशेष बल दिया गया है। दाभोल विद्युत परियोजना की बात हमारे साथियों ने कुछ कही। इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है और इस वर्ष उसका उत्पादन भी संभावित है। चार-चार हजार मेगावाट क्षमता वाले पांच अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संचालन को आसान बनाया जा रहा है।

सूचना के अधिकार की बात बहुत कही गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय था, सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करके यह विधान भ्रष्टाचार को कम करने वाला सिद्ध होगा।

न्याय प्रणाली के बारे में, मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के लोग माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ें जहां से वह प्रारम्भ हुआ है अंत तक जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, उन को सही ढंग से पढ़ लेते, तो आज जिस प्रकार की बातें वे कह रहे हैं, निराशाभरी बातें वे कह रहे हैं, वे शायद नहीं कह पाते। न्याय-प्रणाली में सुधार-जहां उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में बहुत मामले हमारे लम्बित रहते हैं, इन लम्बित मामलों को भी निपटाने का निर्णय लिया है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हर मुद्दे पर रोमांचित इसलिए हो रहे हैं कि हमारी सरकार ने, 20 महीने की सरकार ने इन मुद्दों को, जो हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में थे, हम न्यूनतम साझा कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। वे अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कहते कुछ थे और करते कुछ थे, जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे, उनका हाल आपने देख लिया वह उधर बैठे हैं।, हम इधर बैठे हैं। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम जनादेश को लेकर बैठे हैं और अपने घटक दलों को साथ में लेकर चलने की हममें क्षमता हैं हम जानते हैं कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं हमें अपने वामपंथी साथियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बार-बार इस बात को कहा है कि सरकार पांच साल तक चलेगी। पांच साल चलेगी, उसके आगे आने

वाले और पांच सालों तक हमारी सरकार चलेगी। डा॰ मनमोहन सिंह जी के समान ऐसा न्यायप्रिय, ऐसा विद्वान ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: बिहार में क्या हुआ? ... (व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: बिहार में 15 वर्ष राज किया है, एक दो वर्ष नहीं। ...(व्यवधान)... आप तो पांच साल में चले गये। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, भंडारी जी। ... (व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति जी, अल्पसंख्यकों के नाम पर इन्होंने बहुत आसूं बहाये। 15 सूत्रीय कार्यक्रम इस देश में पहले भी था। इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में हम पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। यह कार्यक्रम हमारे अल्पसंख्यक साथियों को विश्वास है कि एक ही सरकार कर सकती है और वह कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार ने इन कार्यक्रमों को शुरू किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में इन कार्यक्रमों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली थी और आज भी हम इस जिम्मेदारी से कहीं अलग नहीं हटे हैं। महिलाओं के लिए अधिक संरक्षण के लिए-महिलाओं के साथ अत्याचार की बहुत घटनाएं घटती हैं-दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, पर्यावरण की सुरक्षा, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठा गए हैं। उपसभापति महोदय, आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जम्मू-कश्मीर में 24000 करोड़ का पैकेज जम्मू-कश्मीर की सरकार को दिया गया और उसके साथ-साथ राज्य में जो भूकंप आया था , उस भूकंप से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और उसके साथ-साथ देश के अनेक राज्यों ने जो आर्थिक सहयोग दिया, उसका परिणाम है कि आज लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, उग्रवादियों और अन्य राष्ट्रविरोधी शक्तियों से दृढ़ता से निपटा गया है। हमने आतंकवादियों को हवाई-जहाज में नहीं बिठाकर घुमाया। हमने उनके साथ अत्यधिक सख्ती के साथ बर्ताव किया। कल कहा गया कि अक्षरधाम में घटना हुई, कहा गया कि रघुनाथ मंदिर में घटना हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि घटनाएं हुई थीं। लेकिन इन आतंकवादियों को रोकने की दिशा में आपकी सरकार ने अगर कड़े कदम उस वक्त उठाए होते तो देश में आतंकवादियों की यह हिम्मत नहीं होती। राष्ट्र को हमारी सशस्त सेना पर गर्व है। सर, मैं एक-एक बिन्दु को कह रहा हूं। इस एक,-एक बिन्दु को पढ़ने के बाद मुझे लगा, चूंकि कल मैंने भाषण नहीं पढ़ा था, आज पढ़ने के बाद लगा कि दरअसल इनके सारे बिन्दुओं पर उसका एक जबर्दस्त प्रभाव है और आने वाले समय में, एक वर्ष के कार्यक्रम का जो नक्शा सामने है, उसमें हम उन सारे कामों को पूरा करेंगे। सर, हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। पड़ोसियों के

3.00 P.M.

साथ अच्छे संबंध कायम करने की दिशा में अगस्त, 2005 में प्रधान मंत्री जी की जो राजस्थान यात्रा हुई थी, उस यात्रा का जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। 21वीं सदी में हमारा देश राष्ट्रों के समूह में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा। आज की अर्थव्यवस्था बेहतर निष्पादन को बनाए रखने की स्थिति में है। साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखना इस देश की सौ करोड़ जनता के लिए आवश्यक है और सौ करोड़ की जनता भाईचारे के वातावरण में रहना चाहती है, हिल-मिलकर रहना चाहती है, झगड़ा नही चाहती। जहां झगड़े होंगे, फसाद होंगे, दंगे होंगे, वहां विकास नहीं हो सकता। उपसभापति महोदय, मैं इस बात को कह सकता हूं कि भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश चाहे कितनी ही वे करके देख लें, वे इसमें पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध होंगे और उनको फिर इस बात को यहां पर बैठकर कहना पड़ेगा कि यूपीए की, गठबंधन की सरकार ने इस बीस महीने में काम किया है और आने वाले चालीस महीनों में हम निरंतर इसी प्रगति के साथ काम करेंगे। देश के अंदर से बेरोजगारी को खत्म करने की बात हमने कही थी। इस संबंध में हमने कार्यक्रम शुरू किया है और जिस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पीछे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मंत्रिमंडल के सारे साथी उसका पूरा समर्थन करते ही हैं। तो क्यों नहीं हम इस पर रोमांचित हों, क्यों नहीं हम इस पर गर्व का अनुभव करें। महोदय, जो वस्तुओं की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, उस दिशा में भी सरकार का ध्यान गया है और हमारी कोशिश होगी-अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, उस पर तो कंट्रोल नहीं है लेकिन जो कुछ बढ़ रहा है, उसे रोकने की दिशा में अगर कोई सरकार सक्षम है तो यूपीए की, गठबंधन की सरकार सक्षम है और यह सक्षम सरकार इस बात को सिद्ध करेगी कि देश में एक ऐसी सरकार, गठबंधन की सरकार आयी जो पिछले 6 वर्षों की सरकार से भिन्न थी, उनकी चाल में, चरित्र में और चित्रण में एक अलगपन था, एक ऐसी पैनी बात थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत मायूस हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं, सिर को धुन रहे हैं कि आखिर हम क्या करें, कहां जाएं और अपने आपको कोस रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं...

लेकिन तहलका का एक ही उदाहरण पर्याप्त है। इससे उस सरकार के चरित्र और चित्रण का पता चल सकता है। मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हुए इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं। उनके द्वारा सरकार की नीतियां व कार्यों का विवरण जो अभिभाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपके समक्ष इस सदन में चर्चा करना चाहता हूं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण 62 बिंदुओं के रूप में है, जिसमें सरकार की नीतियों व कार्यों का बयान देश के हित में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए, तो वाकयी ये नीतियां बहुत ही अच्छी हैं और अगर इनका क्रियान्वयन किया जाए, तो देश का विकास हो सकता है। महोदय, आजादी के बाद 42 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने केन्द्र व अधिकतर राज्यों में सरकार चलाने का कार्य किया। जनहित में नीतियां भी काफी अच्छी से अच्छी बनाई, किन्तु उन नीतियों का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं होने के कारण वे समस्त नीतियां कागज़ में ही रह गईं। उसी तरह से इस अभिभाषण में भी नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन की कोई रूपरेखा नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें क्रियाविन्त करने का सरकार कोई कारगर उपाय करेगी और समयबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करेगी, तब तो संभव हो सकता है अन्यथा वह भी कागज़ मे रह जाएगा।

महोदय, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस पर हम भारतवासियों को गर्व हैं, किन्तु आज इस लोकतंत्र पर अपराधतंत्र, सामंततंत्र, धनबल, बाहुबल हावी होकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। अतएव, समय के रहते इसका निराकरण करना सरकार का एक आवश्यक कार्य होना चाहिए।

महोदय, आज़ादी के साठ साल बीत जाने के बाद क्या हम यह सुनिश्चित करने में सफल हो पा रहे हैं कि भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा सपना संजोकर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार और हरेक वोट की एक ही कीमत सुनिश्चित की थी कि आम जनता अपने अधिकार का समुचित उपयोग कर अपना उद्धार स्वयं करेगी, किन्तु आज इस सदन में मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वोट के अधिकार के प्रति जागरूकता न होने के कारण देश के विभिन्न कोनों में आज तक आम जनता या तो बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन देख नहीं पाई है या और कतिपय कारणों से वोट के अधिकारों से भी वंचित रह जाती है या अज्ञानता के कारण दस रुपए के शराब के पाउच पर अपना अमूल्य वोट बेचने का काम करती है। इस महान लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक चिंताजनक बात है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करे, ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की बहाली हो सके। महोदय, अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मेरी सरकार ने हमारे किसानों के ज्ञान तथा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह एक अच्छा और सराहनीय कदम है, किन्तु अभिभाषण में ऐसे किसानों का कोई ज़िक्र नहीं है जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मज़दूर हैं, खेती में पूरे परिवार सहित काम करते हैं, किन्तु इन्हें सिर छिपाने के लिए भी नीली छतरी के अलावा कोई सहारा नहीं है। ऐसे खेतिहर मजदूर आए दिन सामंती जुल्मों के शिकार होते हैं और गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। वे केवल रोजी-रोटी की तलाश में ही पलायन करते हैं। मेरा यह मानना है कि बड़े-बड़े शहरों

में रेल की पटरियों के किनारे, गंदे नालों के किनारे, सड़कों के किनारे वे झुग्गी-झोपड़ी बनाकर जानवर से भी खराब जीवन जीने को मजबूर होते हैं। सरकार का ध्यान इस प्रकार के शरणार्थियों पर कतई नहीं जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के शरणार्थियों पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। यही नहीं आधुनिकीकरण या शहर के सुन्दरीकरण के नाम पर सरकार द्वारा इन्हें उजाड़ने का भी काम किया जाता है। यह एक चिंता का विषय है। अत: हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिन भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की संख्या गांव में लगभग दस से बीस प्रतिशत है, इनके विकास के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाए, तभी हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए अभिभाषण में भूमि सुधार का भी जिक्र आया है, उसे समयबद्ध तरीके से कानून बनाकर लागू किया जाए तभी खेतिहर मजदूरों का विकास संभव हो सकेगा और ग्रामीण पलायन भी रोका जा सकेगा, यह मेरा सरकार से अनुरोध है। आर्थिक विकास की बात का जहां तक प्रश्न है, आजादी के बाद इस देश का चतुर्मुखी विकास हुआ है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। आजादी के दौरान जहां हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज हमें गर्व है और मैं अपने वैज्ञानिकों एवं श्रमिकों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से आज देश में सुई से लेकर सुपर जेट विमान तक बन रहा है। हम देशवासियों को इस पर गर्व है, किन्तु इस आर्थिक विकास का लाभ किस को कितना मिल रहा है, यह चिंतन करने का विषय है। आजादी के बाद अगर हम इस पर चिंतन करें तो स्पष्ट नजर आता है कि विकास का लाभ जितना गरीबों को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है बल्कि अधिकांश भाग अमीरों की जेबों में जा रहा है। इससे आजादी के बाद अमीर-गरीब की खाई बढ़ती ही नहीं जा रही बल्कि भयावह रूप भी लेती जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस ओर सरकार को गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। वक्त रहते गरीब-अमीर की खाई को कम करने की जरूरत है अन्यथा इनके अनेकों दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। महोदय, जब माननीय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि केन्द्र से अगर एक रुपया चलता है तो गांव तक जाते-जाते 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब अगर केन्द्र से एक रुपया चलता है तो अब क्या 15 से ज्यादा पहुंच रहा है या और कम हो गया है, सरकार को यह चिंतन और मनन करने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहा गया हैं कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य सामाजिक तौर से, शैक्षिक तौर से, पिछड़े नागरिकों के लिए निजी तौर पर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में संविधान संशोधन किया है। यह एक सराहनीय कार्य है, किन्तु इससे इन जातियों का भला होने वाला नहीं है। इन वर्गों के हितों के लिए विशेष अभियान चलाकर सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की जरूरत है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो विनिवेशकरण किया जा रहा है, उसके कारण सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जिससे आरक्षित वर्ग के लोग प्रभावित

हो रहे हैं। अत: इन वर्गों के हितों के लिए जल्द ही विधेयक लाकर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ आजादी के 60 साल बाद भी उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका, विधान परिषद् और राज्य सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि इन वर्गों का उत्थान हो सके।

अब मैं भारत के अतीत के विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली रहा है। भारत देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत धन-धान्य से भरपूर था, भारत संपन्न था, इतना ही नहीं इस देश को जगद्गुरु भी कहा जाता था। आज यह चिंतन और मनन का विषय है कि जिस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा हो, आज उस भारत को क्या हो गया है कि इसमें जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस पर हजारों रुपए का विदेशी कर्ज़ा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के नागरिक को अकेले नहीं, बल्कि बीवी और बच्चों सहित 8 घंटे से लेकर 12 घंटों तक खेत-खलिहानों, कल-कारखानों में काम करने के बाद दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तन ढकने को अच्छा कपड़ा और रहने को आवास नहीं मिलता है। संपन्न भारत आज विपन्न भारत बन गया है। आज हमें इस उच्च सदन के माध्यम से विचार और चिंतन करने की जरूरत है कि संपन्न भारत के विपन्न होने का कारण क्या है, क्योंकि इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में दु:ख है और दु:ख का कारण है, अगर इस कारण का निवारण कर दिया जाए तो दुनिया से दु:ख दूर हो सकता है। मैं दुनिया की बात तो नहीं करता, परन्तु भारत का नागरिक होने के कारण भारत में दु:ख के कारणों का पता लगाना हम सब प्रबुद्धजनों का दायित्व है।

महोदय, मेरी राय में जब हमारा देश सोने की चिड़िया रहा होगा, उस समय इस देश में जात-पात, ऊंचा-नीचा, छोटा-बड़ा, छूत-अछूत का भेदभाव नहीं रहा होगा। इस कारण उस समय इस देश में इंसान और इंसानियत, भाईचारा तथा मानवता चरम सीमा पर रही होगी, तभी इस देश को सोने की चिड़िया के खिताब से नवाज़ा गया, किन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में जातिवाद भयावह रूप ले रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है कि आज इस देश में जो भाईचारा, इंसानियत और मानवता की भावना होनी चाहिए, जातिवाद के कारण वैसी भावना नहीं है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के चंद चालाक लोग इस जातिवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के संत सर्वश्री कबीरदास, रविदास, दादू, नानक, मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी तथा हमारे देश में महापुरुष जैसे महात्मा ज्योति बा फुले, रामास्वामी नायवर, नारायना गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, इन सभी लोगों ने कहा है कि इंसानों की जातियां नहीं होती हैं। बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा कि जाति-विहीन समाज की स्थापना के बगैर स्वराज की कल्पना

करना निरर्थक है। आज हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि इस जातिवाद रूपी अभिशाप का कैसे जड़ से सफाया किया जाए। आज भी देश को भ्रमित करने के लिए एक तरफ सामाजिक समरसता के नाम पर, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इस भ्रमजाल को फेंककर, स्वार्थ से ऊपर उठकर, आज देश को सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है।

मैं माननीय श्री कांशीराम जी और बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि अनेकों बाधाओं के बावजूद वे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारे दोनों नेता मंच से नारा लगाते हैं कि ''जाति तोड़ो - समाज जोड़ो'', लेकिन मुझे खेद है कि इस देश की मनुवादी व्यवस्था के पोषक, इस महान कृत्य को करने वालों को जातिवादी होने की संज्ञा देते हैं और जाति बनाने वालों को, समाजवादी की संज्ञा देते हैं। इसीलिए माननीय कांशीराम जी ने कहा है कि देश के लिए एक नागनाथ है, तो दूसरा सांपनाथ है। आज मैं सदन के माध्यम से इन दोनों तरह के लोगों से अपील करता हूं कि अपनी स्वार्थपरक प्रवृत्ति को छोड़कर जातिवाद का विनाश करने और समतामूलक समाज बनाने के लिए आगे आएं। मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि ऐसा होने पर देश से जल्दी ही जातिवाद का नाश या सफाया हो सकेगा और इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। श्री राजनाथ जी आज यहां नहीं हैं, मैं उनकी कल की बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, किन्तु गांधीवाद की हत्या कांग्रेस कर रही है। मेरी राय में अब गांधीवाद के साथ-साथ इस देश को अम्बेडकरवाद की जरूरत है। इस तरफ सरकार को पहल करनी चाहिए, ताकि यह चरितार्थ हो सके कि ''आम का हाथ कांग्रेस के हाथ''। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It seems that today is the 'International Telugu Day', so he wants to speak in Telugu.

SHRI NANDI YELLAIAH (Andhra Pradesh):

श्री उपसभापतिः आपको तेलुगु में बात करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा।

श्री नंदी येल्लैयाः हमारे पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर हिन्दी के बाद तेलुगु में बात करने का ...(व्यवधान)... मैं आपसे निवेदन करता हूं।

SHRIMATI VANGA GEETHA: (The hon. Member spoke in Telugu).

श्री उपसभापतिः शरद जोशी जी, बोलिए। It is not going on record because they will not be able to record it. You have not given notice to speak in Telugu. Nobody understands it.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, the President's Address for which we are here debating on the Motion of Thanks consists of 62 points; and there are 162 amendments. I find, towards the end of this debate, that the entire debate is off the track, in the sense, that we are not taking note of each of the bullets or each of the points that has been made by the President. Nor are we taking into consideration the various amendments that have been proposed. This is taken as a debate free for all. The opponents would, of course, take the opportunity of attacking the ruling Government as if it was an electoral campaign, and the ruling party people, particularly those who aspire to get some posts, try to use the opportunity for pleasing their bosses. I think this is hardly the correct tenor for holding a debate on the Motion of Thanks for the President. I would suggest in the proper way later on that this debate on the Motion of Thanks should be carried out either on the basis of each of the points that is raised by the President or on the basis of amendments that are proposed by various members. Otherwise, the debate would become entirely pointless. As far as I see the debate, the basic situation is like this. The deficiencies in infrastructure, whether you are talking of power or telephones etc., all came up during the period of socialist planning and were inherited by the Government of Shri P.V. Narsimha Rao and our present Prime Minister who was the then Finance Minister. These are the people we have to thank for taking up the challenge and giving the entire Indian economy a different turn. *(Interruptions)* Since then, apparently, both the ruling party and the opposition party have lost their economic agenda and they are mouthing cliches in order to get advantage in elections. Today, the point is not whether we should have socialism or we should have economic reforms. That is not the point. The point is whether we follow the Arrow's theorem which specifically states that community decisions can only be irrational, and against that, the Amartya Sen thesis which says that in spite of the Arrow's theorem, there has to be some kind of a community action in the fields of hunger, education, health, etc. That is really the economic controversy in the present political situation. I am afraid, the President, while making the forecast for the future has not really grasped the issues and has not really put forward the issues that are involved. What has happened is, there are some very important issues that have been skirted. For example, FDI in retail trade, in my opinion, is a decision that is going to change the entire complexion of the Indian economy. As a farmers' movement man, I would say that if

only instead of the Agricultural Produce Marketing Committees, we had the organised retail trade, the Indian farmer would not have been forced to commit suicide as he is doing today. That is an issue which has been entirely skirted. Then, there is the question of the policy on Iran. There is not a word on it. Then, we have the question of farmer suicides. We are talking of helping the farmers. But the point, that more than four or five thousand farmers have committed suicides and are committing suicides even today, has been skirted. I wish some of these points had been made. Then the speech would have been more relevant. Similarly, there were number of constitutional problems which have been raised by the bigger leaders of different political parties. I would not like to talk about them. Then, Sir, there are some points where only a future promise is made. Having skirted around some issues, there are certain issues where only a promise has been made. For example, in paragraphs 13, 14, 15, 27, 28 and 40, we talk of the National Rainfed Area Authority, the National Bio-technology Mission, the Committee of Infrastructures and the National Knowledge Commission. These are all to happen and even the National Rural Employment Guarantee Scheme officially is to be inaugurated only on the 1st of March. It has not even started today. So, these are all about things that may or may not happen and it really does not make any sense. But the fact is that as the National Rural Employment Guarantee Scheme has been implemented, we have reason to believe that it is going to be a major nest of rampant corruption. We have experience of that in the State of Maharashtra and I am quite sure, it's going to be a scheme for national corruption all over and if anybody gets रोमांच by having corruption on that scale, he is entitled to that.

Then, there are some positive points which I would like to examine. Firstly, it is said that the agricultural credit has been increased by 60 per cent. There was a statement by the Finance Minister last year, saying that the credit available for agriculture will be increased from Rs. 80,000 crores to Rs. 1,30,000 crores. And the question that arises is, where did all this money go? In the Consultative Committee on Agriculture, the Minister of Agriculture gave an explanation that this money has actually reached the farmers and he said, if you make an inventory of the statements by the commercial banks, then the amount has reached the farmers. On the other hand, in the statement made here, the Minister of Agriculture says that loans are going through the cooperative mechanism.

One does not know whether loans are going to the farmers through the cooperative mechanism or through commercial banks. As a person who stands in the field and who has daily contacts with farmers, I would say that these loans are not going to any farmer and farmers continue to be driven in long numbers to the desperate action of suicides. Then, there is a question of the revival of cooperative structures. I have read recently in the newspapers, the Prime Minister declaring that Rs. 13,000 crores — I hope, Mr. Bimal Jalan is also listening to me, — have been made available for restructuring of the cooperative societies, and Shri Sharad Pawar, the Minister of Agriculture, has also said that Rs. 16,000 crores will go to the cooperative structure. That makes a total of Rs. 29,000 crores. And the fact remains that no farmer is entitled to get any loan from the cooperative bank because they are already bad debtors, they are not entitled to get any fresh loans. Under the circumstances, the big mystery is, what happened to those Rs. 29,000 crores, which have been talked about.

Then, Sir, there is the question of wheat imports, and if you permit me, Sir, I would like to take a few minutes on this. It is in this House that I have pointed out that there was some mystery about the missing of 9 lakh tonnes of wheat. It is only a month back that the Minister for Agriculture has made a positive statement in this House that there was no shortage of wheat, and that we will not be required to import any wheat this year. I remember that I specifically gave a cutting from the *Hindu Business Line,* which said that some wheat was being imported, and the Minister for Agriculture repudiated that suggestion and said that we will not need any import of food. There was a missing quantity of 9 lakh tonnes. Where did it go? I think, according to my guess, it went into the Food for Work Programme, just disappeared into the Food for Work Programme. And, now, we are importing it in such a manner that the arrival cost in Punjab is Rs. 1200/- per quintal, while we are giving Rs. 640/- to our farmers. The suggestion made is that this wheat will be used only in the South, and if you take the landing cost in the South, then, the difference is very much reduced. But, the fact remains that just a month before the procurement season starts, importing wheat from outside is a grossly anti-farmers action which should have been really referred to in the speeches on the President's Address, which has not been done to at all.

Then finally, I would like to make a categorical statement that there are people who are happy about the Sixth Pay Commission being appointed. The Fifth Pay Commission made two types of recommendations. In the first type of recommendations, they suggested improved work conditions and perks for the Government staff, and in the second set, they made suggestions that would improve the performance and the yield of the Government servants. All those constructive suggestions in the second category were outright rejected, and only the recommendations relating to salary increases and the perks increases were implemented. Sir, the result has been, you can ask any Chief Minister of any State, whether he is a Congressman or a BJP man, the Fifth Pay Commission has made the total ruination of the State economy, and if the Sixth Pay Commission comes in, and if the Sixth Pay Commission is led by the same motives of popularity, I am afraid, the Sixth Pay Commission and the implementation of its recommendations would see the end of the economic sanity and economic solvency of this country. These are the points which I would have liked to see in the President's Address. Otherwise, I think, we ought to thank the President for the fact that he has made a succinct statement, reading in between the lines. The fact remains that for non-members, like Shri Motilal Vora, should read carefully in between the lines of the address made, they will see more reasons for a vote of no confidence in the Government, rather than being exhilarated at the report. Thank you.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों को उजागर करता है। इस बजट सत्र से पहले लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, वह सिर्फ मात्र कोई रस्म या औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि इससे सरकार की नीयत और आने वाले समय में सरकार की क्या योजना है, उसका संकेत मिलता है। जैसा अन्य कई लोगों ने भी कहा कि राष्ट्रपति जी ने तमाम महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन मुख्य रूप से जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में और किस तरह से हम देश को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, उस पर उन्होंने अधिक जोर दिया है।

उपसभापति महोदय, अगर यह सरकार इस बात का दावा करती है कि पिछले 20 महीनों के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है, तो यह गलत नहीं है। आज हमारे देश की जो विकास दर है, वह लगभग 8 प्रतिशत है, इसी तरह से शेयर बाजार में भी काफी उछाल आया है, लेकिन इन तमाम चीजों का लाभ हम किस तरह से आम आदमी को पहुंचाएं, यह इस

यू॰पी॰ए॰ सरकार की नीयत है और कोशिश है कि हम अपने तमाम आर्थिक कार्यक्रमों का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों, दबे हुए वर्गों, पिछड़े वर्गों तक पहुंचाएं। इन वर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए और उसी दिशा में कई ठोस कदम पिछले 20 महीनों में उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि जो पिछली एन॰डी॰ए॰ की सरकार थी, उससे भी कुछ सीखने का मौका हमको मिला है। पिछली सरकार ने एक ऐसा दावा किया था, भारत शाइन कर रहा है, भारत के चमकने की बात कही, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन की बात कही, लेकिन उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुचा, जिसके कारण उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन, हम कहना चाहेंगे कि यू॰पी॰ए॰ सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है और इस सरकार ने जो भी कार्यक्रम या योजनाएं बनाईं, उनमें इस बात का ध्यान रखा और खासकर ग्रामीण विकास का ध्यान रखा। भारत निर्माण कार्यक्रम, जो यू॰पी॰ए॰ सरकार ने लिया है, वह एक बुनियादी कार्यक्रम है। जैसा हम हमेशा कहते आए हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और भारत का यदि सही निर्माण हो सकता है तो वह उसी समय संभव हो सकता है, जब गांवों का विकास हो, गांवों का निर्माण हो, क्योंकि आज भी आजादी के इतने लम्बे अरसे के बाद भी हमारे गांवों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज भी वहां लोग जिस तरह का जीवन बिता रहे हैं, वह चिंता का विषय है और इसलिए यू॰पी॰ए॰ सरकार ने आने के बाद जो भारत निर्माण का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया, मैं समझता हूं कि यह इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

इसके साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे देश की जो जनसंख्या है, उसमें नौजवानों की जनसंख्या सबसे अधिक है और उनमें भी बेरोजगार नौजवानों की संख्या अधिक है। आज जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके समाने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उनके सामने अंधेरा है, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज गांवों से बहुत बड़े पैमाने पर लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में भटक रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, गांवों के अन्दर कैसे उन्हें रोज़गार मुहैया किया जाए, सरकार के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सरकार ने संविधान में एक संशोधन करके उसे बड़े ही अच्छे ढंग से निभाया है। आज़ादी के बाद से आज तक जो काम नहीं हुआ था, उस काम को इस सरकार ने करने की कोशिश की। खासतौर पर जो हमारे लोग गांवों में रहते हैं या ज़ो खेतिहर मज़दूर हैं, रोज़गार गारंटी योजना के तहत उन लोगों को कम से कम सौ दिन के रोज़गार की गारंटी देने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने अभी 200 जिलों को इसमें शामिल किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, जल्द से जल्द यह सरकार इस कार्यक्रम को सारे देश में, यहां तक कि शहरों में भी लागू करने का काम करेगी जिससे रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश के सामने है, उसका किसी हद तक समाधान होगा।

इन तमाम चीजों के पीछे एक चीज़ को हमें जरूर देखना होगा, वह यह है कि हम कार्यक्रम तो बनाते हैं, उसमें राशि का आबंटन भी होता है, साधन भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग हो, इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए और इसकी निगरानी बराबर होनी चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि बहुत सारे कार्यक्रम, खास तौर पर जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, उनमें कई तरीके का भ्रष्टाचार होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारी जो नीयत होती है या हमारा जो कार्यक्रम होता है कि उसका लाभ हम गांवों के लोगों तक पहुंचाए, वह हम नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह से लोगों के अन्दर एक मायूसी पैदा होती है, जिसके कारण सरकार की योजना सफल नहीं हो पाती है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि किसी भी देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, उसे देश की मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक है और वे देश की मुख्य धारा से तभी जुड़ेंगे जब शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले। ऐसा करने पर ही वे आगे बढ़ सकते हैं और देश की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने याद दिलाया है कि सरकार ने एक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया है। देश के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी वेल्फेयर के लिए या अल्पसंख्यक समुदाय की भलाई के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है। मैं समझता हूं कि यह मंत्रालय कारगर ढंग से अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेगा फिर चाहे वह शिक्षा का सवाल हो अथवा कोई और सवाल हो, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान में लाभ हो सकता है। सरकार ने इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

उपसभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का लाभ हम समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचा सकें। यह एक बहुत ही उचित कदम है और हमेशा हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना के अन्दर जो विकास हो रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमें उसके मुकाबले में आना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए और इसके लिए सरकार को काफी प्रयत्न करने की जरूरत है। विकास के लिए मैं समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ है, वह है बिजली। हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं, औद्योगिकीकरण की बात करते हैं या फिर हम अनाज की पैदावार को बढ़ाने की बात करते हैं। किसानों को भी बिजली की जरूरत है, उद्योगपतियों को भी बिजली की जरूरत है। इसलिए आज हमारे देश में जो बिजली की कमी है उसको हमको पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि सरकार ने ठोस कदम उठाया है। अभी तक हमारे देश की जो क्षमता है वह लगभग एक लाख मेगावाट की है, लेकिन आने वाले समय

में यह कोशिश की जा रही है कि इस क्षमता को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां बिजली की पैदावार हो जिससे हम अपने विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ा सकें।

उपसभापति महोदय, जो भी स्कीम या जो भी बातें कही जा रही हैं राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है कि एक तो एम्प्लोयमेंट, सिर्फ रूरल एम्प्लोयमेंट की बात नहीं कही गई है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को कैसे एम्प्लोयमेंट मिले, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस तरह का प्रावधान करने की कोशिश यह सरकार कर रही है जिससे लेबर इंटेंसिव सैक्टर में हमको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, खास तौर से टेक्सटाइल्स में, गारमेंट में, लेदर में, लेदर गुड्स में, फूड प्रोसेसिंग में, आई॰टी॰ हार्डवेयर में, इलेक्ट्रोनिक्स में और इस तरह से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जिन पर सरकार काम कर रही है और सरकार की यह कोशिश है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लोयमेंट हम जेनरेट करें, जिससे जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको अवसर मिल सके। उपसभापति महोदय, इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जो भी अभिभाषण दिया है वह इस सरकार के आने वाले अगले साल के जो भी कार्यक्रम हैं उसमें दर्शाया है और मैं समझता हूं कि इस अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी इस पर हमारे विपक्ष के लोगों ने आपत्ति की है मैं समझता हूं कि वह राजनीति से प्रेरित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो सच्चाई सामने आई है कि आज दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की जा रही है, जो आर्थिक उपलब्धियां हमारे देश में पिछले 20 महीने में हुई हैं उसकी तारीफ सारी दुनिया में की जा रही है। इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका लाभ जो हमारी कोशिश है कि आम आदमी को मिले उसको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): माननीय उपसभापति जी, मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं लोक सभा से राज्य सभा तक पहुंचा, कुछ समय लगा और मुझे यहां बैठकर बहुत सारी बातें सुनने का मौका मिला।

श्री उपसभापति: आप सामने आकर भी बोल सकते हैं, आपकी मेडन स्पीच है, सामने आ जाइए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: एक ही बात है, मैं यहां कंफरटेबल हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। कांग्रेस और इस देश के इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का आजादी की लड़ाई से पहले का इतिहास और कांग्रेस का आजादी के बाद का इतिहास, बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। हमेशा ही यहां के गरीब आदमी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। आजादी से पहले के इतिहास में कांग्रेस के कितने ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इस देश को आजादी दिलाई। जो लोग आज टीका-टिप्पणी करते हैं, जो कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं, शायद उनमें से भी कोई भी उस समय मौजूद नहीं था। अगर इतिहास की वह लड़ाई

नहीं होती, अगर जलियांवाला बाग नहीं होता, अगर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उस लड़ाई में नहीं कूदते, तो शायद इस देश को इतनी जल्दी आजादी मिलने वाली नहीं थी। सर, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हमें ही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग यह समझते हैं कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है तो शायद वे गलत हैं, क्योंकि इस देश के लिए कुर्बानी देने वाली कांग्रेस ही थी और कोई दूसरी पार्टी उस समय नहीं थी जो लोग आये हैं, वे बाद में आये हैं, वे इतिहास में अब पैदा हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जहां पहले दिशा दी, वहां कांग्रेस आज भी देश को एक सही दिशा पर ले जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस गरीबों की साथी है, कांग्रेस कमजोर लोगों की साथी है। आजादी के बाद जब से कांग्रेस की सरकारें बनीं, रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन बातें कांग्रेस के बुनियादी उसूल रहे हैं। वे चाहते थे कि देश सम्पन्न हो, वे चाहते थे कि लोगों को रोजगार मिले, छोटे उद्योग बढ़ें और उसी तरफ उन्होंने आगे काम किया। अभी कुछ बातें ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, it has been a tradition not to disturb maiden speeches. Mr. Agarwal, आप बोलिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: कुछ बातें कही गईं जिसमें डा॰ मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा, श्रीमती सोनिया जी के लिए भी कहा, तो दुनिया के इतिहास में शायद कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने लिए सीट छोड़ दी हो, जिसने कहा हो कि मैं प्रधान मंत्री नहीं बनना चाहती और उन्होंने डा॰ मनमोहन सिंह जी को प्रधान मंत्री बनाया। शायद इतना बड़ा फैसला दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी नेता ने नहीं लिया होगा। आज उनकी भावना को समझते हुए, हमें उस भावना को एप्रिसिएट करना चाहिए, यह कहना चाहिए, हां, अगर हम कुर्बानी दे सकते हैं, तो हम देश को आगे ले जाने के लिए अच्छी नीतियां भी बना सकते हैं। जिस समय उन्होंने डा॰ मनमोहन सिंह जी को चुना, तो दुनिया के हर देश ने तारीफ की। हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास अच्छा रहा है, हम मजबूत हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं और वे सारी बातें हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई हैं, जिनको लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। बिना आपसी सद्भाव के देश मजबूत नहीं हो सकता है, कुछ चर्चा अभिभाषण में की गई है। अगर हम ध्यान से काम करेंगे, अगर हम उन लोगों के खिलाफ डटकर अच्छे शब्दों का, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें हिन्दू-मुसलमान--सिख-ईसाई के नाम पर बांटना चाहते हैं या हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, वे हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब भी कोई हादसा हुआ, तो उसमें त्रिशूल बांटने का काम किसने किया, लोगों को मुसलमानों या किसी और कौम के खिलाफ भड़काने का काम किसने किया, क्या वजह है, क्या हम उनको बांटकर देश को

मजबूत कर सकते हैं? क्या हम उनको बांटकर एक साथ लेकर चल सकते हैं? क्या हम अलग-अलग दिशाओं में ले जाकर उनके खिलाफ नफरत पैदा करके हम उनको मजबूत कर सकते हैं? सर, जब हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनको दिल से लगायेंगे, हम उनको पढ़ाई की ओर ले जायेंगे, हम उनको रोजगार की ओर ले जायेंगे, उनको रोजगार देंगे, तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं।

सर, राजीव जी के नाम से कुछ स्कीमें रखी गईं, उन पर भी ऐतराज किया गया। मैं नहीं समझता कि उनको राजीव गांधी के नाम पर ऐतराज था या उन स्कीमों पर ऐतराज था, जो देश के लिए लागू की गई हैं। श्री राजीव गांधी कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, दुनिया में उनका नाम लिया जाता था, दुनिया में उनको सुना जाता था, दुनिया में उनके शब्दों को सुना जाता था, दुनिया में उनकी राय जानी जाती थी, एक मजबूत हिन्दुस्तान की कल्पना करने वाला वह नौजवान इन्सान, जो हिन्दुस्तान में कम्प्युटर लाया, जो महिलाओं को रोजगार की ओर ले गये और देश में दिशा देने वाली संस्थाओं की ओर ले गये, उन्होंने 18 साल के युवाओं को वोटिंग का राइट दिया। आज मैं नहीं समझ सका कि वह क्या कहना चाहते थे, क्या राजीव गांधी जी के नाम से उनको इतना ऐतराज है कि उनके नाम से हम कोई स्कीम चालू करते हैं तो वह नहीं की जानी चाहिए।

सर, मैं यहां बैठा था तो सोच रहा था, जब श्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि शायद अपोजीशन के लीडर कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे सरकार को परेशानी महसूस होगी। शायद वह विदेश नीति पर ईरान की चर्चा करेंगे, शायद सार्क की चर्चा करेंगे, शायद वह पाकिस्तान से अपने रिश्तों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने उस विषय में नहीं कहा। मैंने सोचा था कि शायद वह डब्ल्युटीओ के बारे में कुछ कहेंगे, जो हमारी वाणिज्य नीति से रिलेटिड है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा। उन्होंने एफडीआई के बारे में एक शब्द नहीं कहा। बिजली के उत्पादन के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद राजनीति में जो गिरावट है, जो बहुत सारे लोग पकड़े गए और स्टिंग ऑपरेशन में उनके नाम आए, उसके बारे में, उसकी मुखालफत करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके कत्ल हुए-राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए मैं इसे मेंशन करना चाहता हूं-उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं समझता था कि जो पार्टी, जिसको वे कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है जो अभी चंद साल पहले हुई, वह हमारे लिए कहते हुए सोचेंगे। किस तरह उन्होंने अपने, उनके जो दो नेता थे, उनके साथ क्या व्यवहार किया? अभी कुछ समय पहले किस तरह उन्होंने अपने पार्टी प्रेज़ीडेंट की* करके पार्टी से बाहर निकाला, अपने पथ से अलग किया...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: *शब्द रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

---

* Not recorded.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: हमारा मुकाबला किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। हमारे नेता मज़बूत रहेंगे और देश के लिए काम करते रहेंगे...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह रिकॉर्ड से निकाल दिया है।

श्री अजय मारू (झारखंड)**:** सर, इनकी मेडन स्पीच है इसलिए हम टोक नहीं रहे हैं... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: निकाल दिया है। मैंने खुद निकाल दिया है।...**(व्यवधान)**...

श्री अजय मारू: उन्होंने कहा कि देश को बांटने का काम हमने किया। मैं चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: जब आप बोलेंगे तब अपनी बात कहिएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: वे सीनियर एमपी हैं...**(व्यवधान)**... वे जानते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए...**(व्यवधान)**...आप बैठिए। वे क्या बोलेंगे, आप और मैं नहीं कहेंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, कुछ बातें, जो मैं चाहता था कि उस अभिभाषण में हों, उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें से एक है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली के अपने फैसले दिल्ली वाले नहीं ले सकते। सिर्फ असेंबली से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में पहले एक कमेटी रही, फिर कारपोरेशन रही, फिर मेट्रोपोलिटन काउंसिल बनी, फिर असेंबली दी गयी लेकिन आज जो हालात दिल्ली में इस समय हैं, उसके लिए जरूरी है कि यहां एक मजबूत सरकार हो। मजबूत सरकार तभी हो सकती है, जब हमें अपने फैसले लेने का हक दिया जाए। इसलिए आज मैं समझता हूं कि मेरी बात वहां तक पहुंचेगी और इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा ताकि यहां के लॉ ऐंड ऑर्डर के बारे में, यहां की जमीन के लैंड यूज़ के बारे में या और चीजों के बारे में हमें भटकना न पड़े और अलग-अलग जगह, अलग-अलग मिनिस्टरीज़ में न जाना पड़े और हम अपने फैसले खुद ले सकें। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है और मैं आशा करता हूं कि सरकार उसको जरूर मानेगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सर, दूसरा कम्प्यूटर एजुकेशन के बारे में है जिसका जिक्र शायद इसमें नहीं है। आज दुनिया बहुत दूर जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में कम्प्यूटर एजूकेशन नहीं देंगे तो शायद वे बहुत पीछे रह जाएंगे। आज चार साल का बच्चा भी कम्प्यूटर चलाना जानता है और कम्प्यूटर ऐसी चीज़ है जो जरूरत की चीज़ है और एजुकेशन में अगर उसे शामिल किया जाएगा तो उससे बहुत लाभ होगा और हमारे नौजवान आगे जाकर अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं करेंगे। तीसरा, कॉमन वेल्थ गेम्स के बारे में है, जिसका शायद इसमें जिक्र नहीं है। कॉमन वेल्थ गेम्स 2010 में दिल्ली में होने वाले हैं लेकिन

उसकी क्या तैयारी हो रही है? अभी, हम देखते हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। कोई भी उस दिशा में काम करने को तैयार नहीं है। हमारा इतना बड़ा हिन्दुस्तान है, इतनी लम्बी चौड़ी सड़कें हैं लेकिन एक भी धावक हमारा ऐसा नहीं है, मिल्खा सिंह के बाद, जिसने अभी तक कोई मैडल लिया हो। कोई भी तैराक हमारा ऐसी नहीं है, जबकि इतनी बड़ी हमारी बाउंडरी है, चारों तरफ समुद्र है, इतनी बडी-बडी नदियां हैं लेकिन हमारे तैराक कोई मैडल लेकर नहीं आ सकते। हॉकी में हमारा नाम था, लेकिन आज की तारीख में हम उसमें भी बहुत पीछे हो गये। उसके बाद फुटबॉल देख लीजिए। तो क्या सरकार कोई ऐसी मजबूत संस्था बनाएगी या मिनिस्टरी की तरफ से कोई ऐसा काम करेगी ताकि इन स्पोर्ट्स बॉडीज को सही किया जा सके? इनको इनके हवाले छोड़कर अगर नुकसान होता है, अगर नाम नीचा होता है तो भारत का नाम नीचा होता है। कहीं भी अगर कोई मैच होता है तो लाखों हिन्दुस्तानी उसको देखते हैं और उनके दिल धड़कते हैं। अगर हम हारते हैं तो यह हार किसी को अच्छी नहीं लगती। सिर्फ 2010 में गेम्स का मैनेजमेंट करना काफी नहीं है। उस दिशा में हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनको भी अगर हम पूरी तरह से तैयार करेंगे तभी हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। चौथे, जिसका जिक्र अभी तारिक अनवर साहब ने भी किया, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि चीन से जो माल आ रहा है, उससे हमारे छोटे उद्योगों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो माल यहां लाकर बेचते हैं, उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, हमारी जो घरेलू नीति है, जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको लाइसेंस दिए, बिजली दी, पानी दिया, तो आज इसकी जरूरत है कि हम कोई ऐसी रोक लगाएं, ताकि वह माल आकर हमारे उद्योगों को खराब न कर सके, उनको बंद न करे। उद्योग बंद होंगे, तो लोग बेरोजगार होंगे और उनको रोजी-रोटी के लिए तड़पना पड़ेगा।

महोदय, मेरा आखिरी प्वाइंट बिजली के उत्पादन के बारे में है। इस समय कम से कम दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है और कई ऐसी जगहें हैं, जहां से दिल्ली को जो बिजली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। तकरीबन 800 से 1000 मेगावॉट बिजली कम है और मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसी स्कीम दिल्ली को देंगे कि बिजली का उत्पादन पूरा हो। हमारे यहां जो उद्योग बंद हो रहे हैं, जो कारखाने बंद हो रहे हैं, वे दोबारा से चालू हो सकें, उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। यहां से बहुत सामान एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मंडी है और अगर वह पूरा नहीं हो पाए, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री अजय मारू, बोलिए। आपकी पार्टी के पास 29 मिनट बचे हैं और आपके अलावा कृपाल परमार जी भी हैं, तो समय का ज़रा ध्यान रखिएगा।

4.00 P.M.

श्री अजय मारू: उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, पूर्व वक्ता माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने जो बातें कहीं, क्योंकि संसद में उनकी आयु मुझसे अधिक है, लेकिन यहां maiden स्पीच थी, इसलिए टोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हमारे दल द्वारा देश को तोड़ने की बात, बांटने की बात कही, तो मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आर्मी में जो एक समुदाय के लोगों की गणना की बात कही है, इससे कोई देश जुड़ने की बात नहीं हो रही है। इससे तो देश को बांटने की बात हो रही है और उससे सेना का मनोबल भी गिरा है।

उन्होंने बाद में जो चार मुद्दे उठाए, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कमियां उन्होंने बताईं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और आशा करता हूं कि इसको भी अभिभाषण में किसी न किसी रूप से जोड़ा जाएगा। महोदय, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी ने और हमारे दल के पूर्व अध्यक्ष माननीय वेंकैया नायडु जी ने काफी विस्तार से इस अभिभाषण की आलोचना की और मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत हूं और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से यू.पी.ए. सरकार ने अपने कार्यकाल का जो ब्यौरा पेश किया है, वह न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि पूरी तरह दिशाहीन है। स्वयं राष्ट्रपति जी ने समय-समय पर देश के भविष्य के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनकी इस भाषण में कहीं पर भी कोई झलक दिखाई नहीं देती, पर कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकार इन समस्याओं से बचती चली आ रही है।

महोदय, भाषण के प्रारंभ में यही यू.पी.ए. ने अपनी पीठ थपथपानी आरंभ की और कहा कि 1999 से 2003 के दौरान, यानी एन.डी.ए. के शासन काल में अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, वह पांच प्रतिशत थी और उसे उन्होंने कहा कि वह उत्साहपूर्वक नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तत्पश्चात् यानी जब यू.पी.ए. शासन में आ गया, तो 2004-05 में यह विकास दर साढ़े सात प्रतिशत हो गई और उन्होंने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यह विकास दर आठ प्रतिशत होगी। महोदय, मैं यहां बताना चाहता हूं कि 1991 से 1998 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। 1998 में NDA के शासन में आने के बाद जो भी निर्णय लिए गए, उसके बाद ही विकास दर बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 2004-05 में यह विकास दर साढ़े सात प्रतिशत हुई है। महोदय, इसके साथ-साथ इस भाषण में मुद्रास्फीति, इन्फलेशन की जो दर है, वह साधारण स्तर पर कही गई है। लेकिन यह सच है कि UPA शासन के दौरान महंगाई तेजी से बढ़ी है। आज आम जरूरतों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है, चाहे

वह आटा हो, गेहूं हो, चीनी हो, तेल हो, दूध हो और चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो अथवा रसोई गैस हो। मैं रसोई का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि NDA के शासन काल में ऑन डिमांड यानी मांगने पर मिलती थी, लेकिन आज पूरी स्थिति बदल गई है। हर जगह इसकी कालाबाजारी हो रही है। तथा हमारे प्रदेश झारखंड में इसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। महोदय, मध्यम आय वर्ग के लोगों का बजट इस मंहगाई के कारण पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है तो हम निम्न आय वर्ग के लोगों की हालत का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। महंगाई पर अभिभाषण में न तो कोई चिंता व्यक्त की गई है और न ही इस पर काबू पाने के लिए कोई इच्छा जाहिर की गई है। महोदय, भाषण के पैरा-7 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ करने की बात की गई। यह अच्छी बात है, पर ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज उन केन्द्रों पर नहीं हो सकता है। उसके लिए ग्रामीणों को शहरों की ओर आना पड़ता है। आज हम सब सांसद देखते हैं कि प्रतिदिन एम्स में अपने मरीजों को दिखाने के लिए हमें रोज-रोज पत्र लिखना पड़ता है । जब तत्कालीन NDA सरकार देश में इस समस्या के निराकरण के लिए एम्स की तर्ज पर 6 राज्यों में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था और अन्य 11 राज्यों में सरकारी मैडिकल कॉलेज संस्थानों को एम्स जैसा करने का प्रस्ताव रखा था, उनमें मेरा प्रदेश झारखंड भी था, लेकिन पिछले बीस महीनों में इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र है। महोदय, इसी तरह पैरा -17 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में कहा गया है, जो चार लेन की Golden Quadrilateral योजना है, उसका काम पूरा होने वाला है, लेकिन वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है। हम सब जानते हैं कि Golden Quadrilateral योजना NDA सरकार ने आरम्भ की थी और उस समय इसका काम तेजी से चल रहा था। जहां तक मुझे जानकारी है कि इसको इस वर्ष में पूरा हो जाना था, लेकिन UPA की सरकार के आने के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो गई और इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन आगे खिसकती गई। हमें इसके बारे में अब जो जानकारी मिली है कि यह 2007 या 2008 में किसी समय पूरी होगी। इसके बारे में हमें समाचारपत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक आठ ऐसे राज्य हैं जहां भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां Golden Quadrilateral योजना के 471 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, वहां आज मुश्किल से 71 हैक्टेयर जमीन एक्वायर हुई है। अत: सरकार को इस मामले में वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और दस हजार किलोमीटर के अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या योजना है और इसके लिए धन कहां से आएगा, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। महोदय, अभी हाल में ही एक समाचार छपा था जिसमें नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया ने एशियाई विकास बैंक से जो ऋण लिया था, उसकी पहली किश्त के भुगतान में विलम्ब कर दिया था, जिसके चलते हमारी साख एशियन डेवलेपमेंट बैंक में कम हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में ऋण की अदायगी नहीं की गई और इसमें जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्य किया? इसके अलावा

हमारे प्रदेश में नेशनल हाईवे-33 जो बहरागोड़ा से बरई तक है, जिसका DPR भी हो गया था और उसका कार्य NDA के शासनकाल में आरम्भ हो गया था, लेकिन आज UPA सरकार के आते ही वह कार्य बंद कर दिया गया है। महोदय, अभिभाषण के पैरा-20 में रेल व्यवस्था पर संतोष एवं गर्व की अनुभूति की गई है। परन्तु यात्रियों की सुरक्षा के लिए चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है। हाल के दिनों में ट्रेनों में लूट-पाट, बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, फिर भी इस मामले में कोई भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

महोदय, उसी तरह दूरसंचार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है और यह सच भी है। शुल्क में कमी आई है। पर यह भी सच है कि हाल के दिनों में दूरसंचार की सेवा के स्तर में काफी गिरावट आई है। आज बी॰एस॰एन॰एल॰ के ग्राहकों द्वारा कनेक्टिविटी की समस्या सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि हर जगह महसूस की जाती है। ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क पर नवम्बर, 2005 के दौरान कंजेशन पर जो अध्ययन पेश किया है, उसके अनुसार निजी कम्पनियों और बी॰एस॰एन॰एल॰ के बीच कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा खराब देखी गई है। ट्राई ने कंजेशन का अधिकतम स्तर 0.5 परसेंट तय किया है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है।

महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इससे किसी को भी विरोध नहीं है, परन्तु हम सब जानते हैं कि न्यायालयों में जो लम्बित मामले हैं, वे दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। उच्च न्यायालयों में 36 लाख तथा जिला और उसके निचले स्तर के जो न्यायालय हैं, उनमें ढाई करोड़ से ज्यादा मामले लम्बित हैं न्यायाधीशों की कमी के चलते भी यह स्थिति और चिन्ताजनक होती जा रही है। महोदय, हमारे देश के 21 उच्च न्यायालयों में, जहां न्यायाधीशों के 675 पद हैं, वहां आज भी 122 पद रिक्त हैं। समय-समय पर इस सदन के माध्यम से सरकार की ओर से आश्वासन मिलता रहा, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पिछले सत्र में जब मैंने अपने प्रदेश झारखंड के बारे में और उच्च न्यायालय के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट किया था, तो न्याय मंत्री जी ने कहा था कि एक महीने के अन्दर वे पद भर दिए जाएंगे, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश झारखण्ड के उच्च न्यायालय में, जहां न्यायाधीशों के 12 पद हैं, वहां आधे पद अभी भी खाली हैं आम लोगों को न्याय नहीं मिलने की वजह से, कई सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया है और न ही इस पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की है।

महोदय, अभिभाषण के पैरा 26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग गठित करने की बात कही गई है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी कार्य-पद्धति, पी॰एस॰यूज॰ में अधिक कर्मचारियों के चलते घाटे, सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने तथा सजा को और कड़ा बनाने-सम्बन्धी सरकार की कोई भी नीति इसमें स्पष्ट नहीं होती है।

महोदय, विश्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सरकारी कर्मचारियों की जो औसत आय है, वह 75 हजार रुपए प्रति वर्ष है, जबकि हमारे देश में आम नागरिक की वार्षिक आय 15 हजार 6 सौ रुपए है। यानी भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन आम नागरिक की आय से 5 गुना अधिक है। इंग्लैंड में अगर हम इन्हीं आंकड़ों को देखते हैं, तो वहां सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक में 1.4 गुना अधिक, सिंगापुर में 2.9 गुना अधिक, चीन में 1.2 गुना अधिक और मलेशिया में 2.9 गुना अधिक है। महोदय, अगर हम इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के प्रोफेसर, श्री आर॰ वैद्यनाथ की बात मानें, तो उनके अनुमान से भारत में सरकारी कर्मचारी साल-भर में डेढ़ लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में प्राप्त करते हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार वर्तमान में कर्मचारियों पर 37 हजार करोड़ रुपए वेतन के रूप में दे रही है। यानी अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार से मिलने वाली राशि से यह 4 गुना अधिक हो जाती है। अगर आम आदमी की आय और इन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली राशि को मिलाएं, तो यह 25 गुना अधिक हो जाती है। मैं यह नहीं मानता कि सभी सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं। अत: आम आदमी की आय कैसे बढ़े, सरकार ने इस विषय पर इस अभिभाषण में कोई भी चिन्ता जाहिर नहीं की है और मंहगाई की मार उल्टे उसे झेलनी पड़ रही है।

महोदय, हमारे देश में आज भी 200 जिले ऐसे हैं, जो बहुत पिछड़े हैं। यह सरकार उन्हें विकसित करने के लिए क्या कार्य कर रही है, यह तो पता नहीं लेकिन मेरे प्रदेश झारखंड के हजारीबाग जिले में एन॰डी॰ए॰ के शासन काल में चल रही योजनाओं को बन्द करने का कार्य यू॰पी॰ए॰ सरकार कर रही है। इसका जिक्र आज के शून्य काल में और कल के भी शून्य काल में हुआ था।

वहां पर वर्ष 1999 से एनडीए सरकार ने जो इन्कम टैक्स विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला था, उसको 6 साल बाद यह सरकार यह कहते हुए बंद कर रही है कि वहां पर न रेल सुविधाएं हैं, न होटल की सुविधाएं हैं और वह उग्रवाद प्रभावित इलाका है यह सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यह इससे पता चलता है।

महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 40 में कहा गया है – ''मेरी सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान की तर्ज पर कोलकाता, पुणे और पंजाब में बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता के नए केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है।'' मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्व की एन डी ए सरकार ने भुवनेश्वर में इसी की तर्ज पर भारतीय विज्ञान संस्थान खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अगले कुछ महीनों में पश्चिमी बंगाल में चुनाव को देखते हुए और वर्ष 2007 में पंजाब में चुनाव को देखते हुए भुवनेश्वर और एक अन्य स्थान से वे केन्द्र हटाकर इन स्थानों पर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही इस पैरा 40 में दो स्थानों का तो स्पष्ट उल्लेख किया गया वे हैं कोलकाता और

पुणे, लेकिन पंजाब में किस स्थान पर यह केन्द्र बनेगा, अमृतसर में बनेगा, कहां पर बनेगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

महोदय, अंत में मैं अपने राज्य झारखंड का जिक्र करना चाहूंगा। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और प्रगति के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। हमारी बार बार मांग रही है कि खनिजों में, विशेषकर कोयला की रायल्टी बढ़ाई जाए। यहां पर अभी हमारे कोयला मंत्री जी बैठे हैं जब यह प्रथम बार कोयला मंत्री बने थे तो इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि कोल इंडिया का हैडक्वार्टर झारखंड में लाया जाएगा। इसके साथ ही डीवीसी का हैडक्वार्टर भी झारखंड में लाया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार क्या कार्य कर रही? एचईसी, यानि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन उसके पुनरूद्धार के लिए केन्द्र ने जो सौतेला व्यवहार अपनाया हुआ है, उसके बारे में तथा अन्य रुग्ण उद्योगों के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। एचईसी के लिए हाल में जो पैकेज की घोषणा की गई थी, उसके बारे में स्वयं झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पैकेज मूर्ख बनाने वाला है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस उद्योग की, जिसकी स्थापना हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने की थी, इस एचईसी उद्योग को पूरा सहयोग दिया जाए।

श्री दीपांशकर मुखर्जी: सिंदरी का आपने नहीं बोला।

श्री अजय मारू: महोदय, मैंने सिंदरी का जिक्र इसलिए नहीं किया, क्योंकि राम विलास पासवान जी ने यह आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीने में वहां पर जो खाद का कारखाना है, उसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। अब जब सिंदरी का जिक्र आया है, तो मैं एक जानकारी इस सदन को देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मैं पार्लियामेंटरी स्टेंडिंग कमेटी ऑन कैमिकल एंड फर्टिलाइजर की बैठक में अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में कृभको, जिसमें भारत सरकार का 273 करोड़ रुपया लगा हुआ है। जब हम उसकी समीक्षा कर रहे थे, तो एक ऐसी बात प्रकट हुई, जिसकी ओर इस सदन को ध्यान देना चाहिए, कि उस कोपरेटिव संस्था ने उत्तर प्रदेश की ओसवाल फर्टिलाजर की एक यूनिट को 1900 करोड़ रुपए में खरीदा। इसमें एक प्रावेट कंपनी से 280 करोड़ रुपए लेकर 40 प्रतिशत की पार्टनरशिप उसमें दे दी गई। इसमें न तो कोई बिड मांगी गई, बल्कि गुपचुप तरीके से श्याम इन्फोटेक जो कंपनी है, जो फर्टिलाइज़र के पेशे में नहीं है, उस कंपनी को पार्टनरशिप दे दी गई मैंने इस प्रश्न को दूसरे मंचों से भी उठाया है। इससे पता चलता है कि यूपीए सरकार की क्या नीति है? इस कोपरेटिव संस्था में किसी तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई, बल्कि उस कंपनी को खरीदने में जो 1900 करोड़ रुपए की लागत आई, उसमें उस कोपरेटिव संस्था ने एक प्राइवेट कंपनी को अपनी पार्टनरशिप दे दी । उस चालू ओसवाल फर्टिलाइजर को खरीदते समय न तो उस कंपनी की वेल्युएशन की गई और जब उस कंपनी को खरीदने का निर्णय हुआ और एजीएम बुलाई गई, तो उस एजीएम में न तो उसके मैंनेजिंग

डायरेक्टर और न ही चेयरमैन उपस्थित हुए। उनके पीछे यह तय कर लिया गया और 1900 करोड़ रुपए में उस यूनिट को खरीद लिया गया। इसमें क्या घपला हुआ है, उसकी बात तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस बारे में सदन को जानकारी दे।

महोदय, जैसाकि में बता रहा था कि झारखंड उग्रवाद से जूझ रहा है और 22 जिलों में से 18 जिलों में उग्रवाद फैला हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र भी मदद करे।

महोदय, इन सभी बतों को देखते हुए मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आधा-अधूरा और दिशाहीन नजर आता है और मैं समझता हूं कि इसमें कई संशोधनों की आवश्यकता है। अत: मैं अभिभाषण को इसके वर्तमान स्वरूप में पारित किए जाने का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशित): उपसभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, सबसे पहले मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और अपने तेलगू भाई-बहनों को आज के अवसर पर बधाई भी देना चाहती हूं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सब प्रकार के कार्य का, योजनाओं का लेखा-जोखा दिया गया है और भविष्य के लिए दिशा-निर्देश भी दिया गया है। अनेकों बातें हैं, मैं कुछ चुनी हुई बातों पर ही ज़िक्र करने की कोशिश करुंगी। सबसे पहली बात, जिस पर आज सुबह ही चर्चा हुई, किसानों की आत्महत्या को लेकर है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन *मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की,* ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी अपनी छोटी समझ के मुताबिक खेती की जो पद्धति हम लोगों ने अपनाई है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है और जिसे आर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं या हम लोगों ने जिसे नाम दिया है अहिंसक खेती, उसकी तरफ देश को ही नहीं, दुनिया को भी आगे बढ़ना होगा ताकि धरती माता की भी रक्षा हो, सॉयल की फर्टिलिटी भी कायम रहे और किसानों को कम से कम लागत में खेती करने का अवसर भी प्राप्त हो और साथ ही साथ किसानों के कर्जे में डूबने की नौबत न आए। तो अहिंसक खेती की तरफ, आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मैं आपके द्वारा सदन का और सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं। महोदय, इसके साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के उस वाक्य को मैं पढ़ देना चाहती हूं

"While we remain concerned over infiltration and cross-border terrorism and expect Pakistan to fulfil its commitment in this regard, we reiterate our commitment to the composite dialogue process."

जो आखिरी वचन है कि हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है इस बातचीत को आगे बढ़ाने की, यह बड़ा ही आशा देने वाला वचन है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि

बातचीत चल रही है, रास्ते खुल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और इसके लिए दोनों सरकारों को मुबारकबाद देनी होगी। अभी हाल ही में जो ट्रेन चली-खोखरापार-मुनाबाव, कराची से जोधपुर तक, मैं बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के दोस्तों ने भी कहा कि कराची में तो ऐसा जश्न का माहौल था, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत खुश थे लोग, ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बंट रही थीं। हमने यह भी सुना कि जोधपुर में भी वैसा ही माहौल था, जब वहां की ट्रेन आई, लोग उतरे। तो दोनों तरफ यह जो खुशी का हज़हार हुआ है, हालांकि यह एक छोटी सी बात है–ट्रेन का चलना 40 साल के बाद, लेकिन इस छोटी-सी बात से भी पता चलता है कि दोनों देशों की जनता क्या चाहती है। उधर लाहौर-अमृतसर के बीच भी बस अब चलने वाली है, वह ननकाना साहब तक जरूर चलनी चाहिए ताकि ननकाना साहब के हमारे सारे भक्तजनों को सीधे अमृतसर से वहां जाने का मौका मिले। यह भी एक ऐसा कदम है कि जिसकी जितनी भी सराहना की जाए, थोड़ी ही है। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वह जो कश्मीर में सभी रास्ते हैं, चाहे स्कर्दू और कारगिल हो, चाहे रावलाकोट और पुंछ हो, चाहे जम्मू और सियालकोट हो, सभी रास्ते खोल दिए जाएं ताकि लोगों का आपस में आना-आना हो, तिजारत हो, माल भी इधर से उधर जा सके, साथ ही साथ लोग अपने बिछड़े हुए साथियों और रिश्तेदारों से मिल सकें और एक नयी फिज़ा बन सके। अमन सेतु और पुंछ से लेकर जो रास्ते खुले हैं, उसके लिए हम बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं इस तरह से और भी जितने रास्ते खोले जा सकते हैं, खोले जाएं। अभी जो एक ट्रेन चलाई गई है, इसे दोनों तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। उस ट्रेन को अगर अजमेर शरीफ से लेकर झूलेलाल जी के स्थान तक चलाया जाए, तो दोनों समुदायों के भक्तजनों का आना-जाना इतना आसान हो जाएगा और एक नई फिज़ा बनती चली जाएगी।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि दोनों देशों की जनता चाह रही है कि दोस्ती हो, संबंध सुधरें, अमन हो और जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमन के लिए जो तड़पन जनता में है, उसी को याद रखते हुए हम दोनों देशों से अपील करना चाहेंगे कि ज़रा अपनी रफ्तार को तेज़ करें। यह ठीक है कि हम सही लाइन पर जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार को और तेज किया जाए। वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, मुझे वह शेर याद आता है:

तारीख़ की नज़रों ने, वो दौर भी देखा है।

लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।।

अब वह लम्हा आ गया है, अब हमसे ख़ता न हो। ख़ता न इधर से हो, न उधर से हो और अमन की राह पर हम तेज़ी से आगे बढ़ें ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी सब समस्याओं का निपटारा कर सकें।

आज सबसे मुश्किल समस्या जो लगती है, जिसे कश्मीर की समस्या कहा जाता है, लेकिन बात यह है कि

समस्या मुश्किल है हुकूमतों के लिए।
मुश्किल नहीं है आवाम के लिए।।

दोनों देशों की जनता को जितना मिलने दिया जाएगा और जितना बात-चीत करने दिया जाएगा, समस्या का हल उतना ही निकलता नज़र आएगा और फिर वह दिन, वह लम्हां दूर नहीं रहेगा जब हम देखेंगे कि हमने जिसे चीज़ को बहुत मुश्किल समझा था, वह तो बहुत आसान निकली, इसलिए मैं इसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहती हूं।

टेररिज्म, दहशतगर्दी या आतंकवाद की जो बात है, यह तो आजकल एक ऐसा शब्द हो गया है कि कभी-कभी हम लोग जब किसी मीटिंग या सैमिनार में जाते हैं, तब लगता है कि भगवान का नाम कम याद करते हैं, लेकिन आतंकवाद का नाम ज्यादा याद करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे कोई इन्कार नहीं है, लेकिन यह समस्या ऐसी है जो सबकी है। आतंकवाद यदि हमारे लिए एक समस्या है तो यह हमारे पड़ोसियों के लिए भी एक समस्या है। मैं यह जरूर अर्ज करना चाहूंगी कि जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दी को चाहने वाले लोगों ने हमारे खिलाफ़, हिन्दुस्तान में जगह-जगह ऊधम मचाया और यहां तक कि दिवाली के दो दिन पहले भी ग़लत काम किए, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा, उन्हीं आतंकवादियों ने दो बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ साहब पर भी हमला किया था, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यह जो आतंकवाद है, यह जो दहशतगर्दी है, हम कहेंगे कि यह कॉमन एनिमी है। यहां मैं पड़ौसी के लिए दुश्मन शब्द का इस्तेमान नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जो आतंकवादी हमको भी सता रहा है, उनको भी सता रहा है और हर देश को सता रहा है, उनका मुक़ाबला सभी को मिल कर करना होगा। हमारा काम ऐसा साझा होना चाहिए जिसमें हिन्दुस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सभी मिलकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाएं कि इन चन्द तत्वों का मुकाबला हम मिल कर करें, जो हम सबके लिए जीना मुश्किल कर देते हैं।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह साल भारत-चीन मैत्री का वर्ष है, "India-China Friendship Year" है और हम क्यों न इसका भी लाभ उठाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हमने यह हाथ बढ़ाया तो है, हमने कुछ काम भी किए हैं, जिसके लिए यह सरकार सराहना की पात्र है, लेकिन यह कार्य कुछ और तेज़ी से आगे बढ़े तो इधर भी और उधर भी एक दोस्ती की फिज़ा बनती चली जाएगी। जिससे हम अवाम की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए मिलकर और ज्यादा काम कर सकें। इसी सिलसिले में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो जिक्र किया था कि अपने समाज के 15 करोड़ भाई-बहनों के लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं और जिसमें से एक काम जो हुआ है कि मॉयनोरिटीज के मिनिस्टर बनाए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त वे सभागार में मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूं और यह भी कहना चाहती हूं कि यह एक ऐसा कदम है जिसकी हर सोचने-समझने वाले हिन्दुस्तानी को सराहना करनी चाहिए।

लोग सवाल उठाते हैं, हमारे भाइयों ने भी यहां पर कई सवाल उठाए। मैं आपको एक सेमिनार की बात सुनाना चाहती हूं। हमारे यहां के कुछ भाई-बहनों की जहनियत, मानसिकता वाले बड़े-बड़े लोगों का जमघट था। वहां पर हमारे एक दोस्त रिटायर्ड कर्नल ए॰आर॰ खान साहब भी मौजूद थे। वहां यही कहा गया कि यह तो जान देने का सवाल है आर्मी में, सिक्योरिटी की जब बात आती है तो यह देखना होता है कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए कौन तैयार है और कहने का इशारा क्या था, आप समझ सकते हैं। तो हमारे खान साहब से रहा नहीं गया, वे उठ खड़े हुए और कहने लगे कि आप सब दानिशों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो तीन जंगें-लड़ाइयां हुई हैं उनमें किसने अपना खून बहाया है या किस के बेटे ने बहाया है? तो सब खामोश। तो कर्नल साहब बोले कि यह आपके सामने बन्दा खड़ा है जिसने दो जंगों में न सिर्फ अपना खून बहाया है, बल्कि एक जंग में मुझे मरा समझकर फैंक दिया गया था, वह बन्दा यहां खड़ा है। हमसे पूछा जा रहा है कि लॉयल्टी का सवाल उठता है जब सिक्योरिटी की बात होती है। किससे आप पूछ रहे हैं? यह बात मैं आज जरूर कहना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की फौज में जो कोई है, मुझे गौरव के साथ कहना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है जो आज भी सेक्युलर है। मैं यहां गुजरात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि वहां की जो विक्टम औरतें थी 2002 के कार्नेज के वक्त, वहां मुझे कैम्पों में बताया कि ये जो फौजी हैं वे तो देवता हैं, लेकिन यह जो पुलिस वाले हैं यह बड़े राक्षस हैं, क्यों? इसलिए कि फौजियों ने ऐसा काम किया था कि लोगों को वे देवता नजर आए। क्योंकि यह तो फौज की हमारी परम्परा है, उसकी रक्षा हमेशा होनी चाहिए। लेकिन सच्चर साहब ने जो वह मांग की, उसमें कौन सी बेजा मांग थी। उससे दोस्तों के दिल में क्यों आग लग गई है। उन्होंने खाली यह कहा कि जरा गिनती करके बता दीजिए, गिनती तो होती ही है। इस गिनती करने से कौन सा सम्प्रदायवाद पनपने वाला है और हिन्दुस्तान की फौज ऐसी कच्ची सोच की नहीं है, वह हमेशा सेक्युलर बनी रहेगी, हमको पूरा भरोसा है। गिनती सिर्फ इसलिए की जा रही है, मैं एक पुरानी बात बताना चाहती हूं 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब फौज में जो मुस्लिम समाज के थे, उनसे कहा गया कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कुछ लोग मजबूरी में चले गए, लेकिन एक बिग्रेड, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, सारे सोल्जर्स और अफसरों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे चाहे हमको कोर्ट मार्शल करो, हम यहीं हिन्दुस्तान में रहेंगे। मसला खड़ा हो गया और फिर यह फैसला हुआ कि कुछ को रहने दिया जाए। तो इसलिए कुछ को रहने दिया गया, औरों को जबर्दस्ती भेजा गया तो संख्या, तादाद कम हो गई। अब उसकी जरा गिनती हो जाए और पता चले कि किस तरह ठीक से बेलेंस हो। तो कौन सा बेजा काम किया था सच्चर साहब ने, जो एक जाने-माने न्यायाधीश और सेक्युलर सोच के इंसान हैं।

उस पर हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह एक मानसिकता है, यह एक जहनियत है जो हमेशा हमारे दिमाग में घुसा हुआ कीड़ा है, वह हमको

सही राह पर जाने नहीं देता है। क्या यह शब्द है, जिसे कहते हैं तुष्टिकरण, किसका तुष्टिकरण, कौन जनता में काम कर रहा है, मैं चुनौती के साथ कहना चाहती हूं कि इस देश के, हर प्रदेश के गांव-गांव के लोगों में, मैं पैदल घूमी हूं, इस देश को मैं जानती हूं और इस देश के गरीबों का हाल जानती हूं, इस देश के मुसलमानों का हाल जानती हूं और कहना चाहती हूं मीराबाई के भजन को याद करते हुए, ''घायल की गति घायल जाने, जो काई घायल होय।'' क्या दर्द है हमारे मुस्लिम भाई-बहनों के दिल में, कौन जान सकता है, जिनके तार उनके दिलों के साथ जुड़े होते हैं, वे जान सकते हैं और वह दर्द कैसे मिटेगा, कैसे रोजगार के मौके मिलेंगे, कैसे शिक्षा के मौके मिलेंगे, कैसे जो एक खौफ-डर है उससे मुक्ति मिलेगी, ये सारे सवाल हमारे सामने हैं और इसीलिए यह सरकार इस दिशा में जो अच्छे कदम उठा रही है, उनकी हम जरूर सराहना करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि और आगे बढ़ें---हमारे इस भारत देश में, सब हमारे भाई-बहन हैं। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात, जो मैंने अपने पड़ौसी देशों के हुक्मरानों से भी कही थी कि मेरे देश के हिन्दू-मुसलमान दोनों की रक्षा करने के लिए आज कोई गांधी बचा नहीं है, हम बहुत छोटे सेवक हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरी दो आंखें हैं---एक हिन्दू और एक मुसलमान और जब एक आंधी उठी थी हिन्दू राष्ट्र बनाने की, तो गांधी जी ने कहा कि यह देश हिन्दू राष्ट्र नहीं बनेगा, यह देश भारतीय राष्ट्र बनेगा, इंडियन स्टेट होगा और इसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज गांधी नही हैं, आज अगर हम चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म बचे, आज अगर हम चाहते हैं कि सबकी रक्षा हो, सबको समान अधिकार मिले, तो हमको दो काम साथ-साथ करने होंगे, यह मेरी जाती व्यक्तिगत राय आप समझिये। एक तरफ हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई का नारा और उसके लिए जो कुछ करना है वह सब करें और साथ-साथ हिन्द-पाक दोस्ती जिंदाबाद, दोनों नारे लगाने होंगे और जंग नहीं अमन चाहिए यह भी नारा लगाना होगा। हमें दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ाने का काम और भारत में सेक्युलरिज्म की रक्षा का काम, दोनों साथ-साथ करने होंगे और करेंगे और इसके लिए एक जन-आंदोलन खड़ा करना होगा। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, अवाम की होती है और मैं देख रही हूं कि किस तरह एक ट्रेन चल पड़ी, तो पाकिस्तान में हमारों लोग जश्न मनाने के लिए खड़े हुए और हमारों लोग हिन्दुस्तान में जश्न मनाने के लिए खड़े हुए, मुझे उम्मीद है कि जितने आने-जाने के रास्ते खुल जायेंगे और जितने हम लोग एक-दूसरे से मिलेंगे, तो दोनों देशों में ऐसा एक सैलाब आयेगा, ऐसा एक जन-आंदोलन अमन का खड़ा होगा कि नफरत की सारी दीवारों के ढा दिया जायेगा। वह दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही आने वाला है। अवाम की ताकत पैदा हो रही है। हां, एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दोनों देशों की सरकारें अभी भी वीजा के मामले में इतनी कोताही करती हैं कि हम लोगों को एक-दूसरे से मिलने में लगता है कि चांद पर जाना आसान है, लेकिन दस कदम पार करके पड़ौसी से मिलना मुश्किल है। जरा वीजा को भी जितना ढीला कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश हो, यह मैं कहना चाहती हूं। यह जो माइनारिटीज़ के लिए अलग विभाग बनाया है,

इसके जरिये से मुझे उम्मीद है कि बहुत काम होगा और बड़ा काम करना होगा, मेरी बहनों के लिए, मेरी मुस्लिम समाज की बहनें बहुत तकलीफ में हैं। कैसे इनको ऊपर उठाया जाये, कैसे शिक्षा और रोजगार के अवसर दिये जायें, कैसे नई सोच उन तक पहुंचाई जाये, इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि 1857 की जंगे-आजादी को हम फिर याद करने वाले हैं। डेढ़ सौ साल पहले पूरे होने वाले हैं। वह बहुत ही अच्छा फैसला है। वह एक ऐसा वक्त था - 1857 के वक्त न कोई हिन्दू था, न कोई मुसलमान था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई और जाति का था, उस वक्त हर कोई हिन्दुस्तानी था और चलता था नारा - खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी साहिबा का। सबसे ज्यादा अगर किसी की शोहरत थी तो झांसी की रानी की थी। मुझे इस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस होता है कि अंग्रेज अफसरों ने, जो बड़े-बड़े सेना के नायक थे, उन्होंने अपनी सरकार को लिखा कि हमारे दुश्मन की फौज में, एक नौजवान महिला सबसे काबिल जनरल उस वक्त थी, यह अंग्रेजों को कहना पड़ा। The best, the ablest and the most competent general of our enemy's army was a young woman, the Rani of Jhani, सब बातों को हम याद करें और उस वक्त सबने किस तरह मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसको भी याद करें। वह एक ऐसा अवसर होगा जो देश में साम्प्रदायिक एकता और सद्भावना को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा - हम इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में भी मैंने बात की तो लोगों ने कहा, हम लाहौर में, पेशावर में, 1857 के वक्त जो बहुत कुछ हुआ है, हम भी यहां मिलकर मनाएंगे, हम सब मिलकर मनाएंगे। कैसे मिलकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसको याद करेंगे ताकि दिलों को जोड़ने का काम आसान हो जाए। इस फैसले के लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहती हूं। यह साल भगवान बुद्ध के 2550 के महा-परिनिर्वाण का है। पचास साल पहले प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का पर्व बहुत शानदार तरीके से मनाया था और सारे बौद्ध देशों से लोगों को बुलाया था। अब, पचास साल के बाद, हमें खुशी है कि इस सरकार ने फिर एक राष्ट्रीय समिति बनायी है और पहला काम यह हुआ कि चीन की महान हस्ती हुएन सांग, जिनको चीनी लोग शुआन चांग कहते हैं, उनके नाम से एक बहुत बड़ी कान्फ्रेंस नालंदा में हुई और सारी दुनिया के देशों से लोग आए। तब हमने देखा कि कितना बड़ा काम नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ है जिसे आज भी सारी दुनिया याद करती है। उसको भी याद करें, शुआन सांग को भी याद करें, भारत-चीन मैत्री वर्ष को भी साथ मनाएं, यह मेरी इस वक्त पर गुज़ारिश है। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि हमारा नया नारा कुछ नया होना चाहिए जो मेरे गुरु विनोबा भावे ने दिया था - जय जगत। सारी दुनिया की जय हो। धन्यवाद।

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to avail of this opportunity to raise two or three issues reference to which has been conspicuously absent from the speech of the Rashtrapati, but which I think deserve the attention of the whole nation if we are to maintain the health and vibrance of our democracy. After the Rashtrapati's speech last year, a number of developments have taken place in this country, some of which give us cause for pride and happiness, while some make us feel concerned and unhappy. The most important developments, in my opinion, which should have caused us great concern as Members of Parliament and which continues to cause great concern are the incidents of dishonourable behaviour on the part of some Members of Parliament. I am referring to the two incidents of gross corruption alleged against some Members of Parliament, one relating to receiving money for raising question on the floor of the House, and the other relating to the misuse of MPLADS funds. Unfortunately, the weakness of our community, of our nation is that we show anger, revulsion, annoyance, and outrage when a particular incident of corruption give us a shock, but very soon, we forget all about that. And when some new instances of gross corruption come to our attention, we forget the earlier one which should have been discussed and for which we should have arrived at some solution. I have always felt that it is this weakness on the part of our nation, which has made us earn the dubious distinction of being one of the most corrupt nations in the world. I have always felt that if there is one factor which prevents us from becoming one of the most advanced nations in the world, it is corruption in public life. You may say that many other nations also suffer from the same disease. But we have all the potential to become one of the two or three topmost nations in the world if only we handle this problem of corruption in a serious manner. Unfortunately, as I said earlier, if something happens we feel outraged, and then we forget all about it. We have become tolerant to corruption. We have developed a permissive attitude to corruption, and it is this tolerance and permissive attitude which is perpetuating this evil in our country. Many suggestions have been made as to how this problem should be tackled. Many experts have gone into this issue, but I am sorry to say, not one set of these suggestions has been accepted or implemented by the present or the previous Governments. By mere discussions on the floor of the House or *bhashans* from platforms we can not solve this problem. Sometimes, I have a feeling that if only Gandhiji had been given

five or ten more years of his precious life, he would have helped us to tackle this problem effectively. His life was spent for laying the standards for public morality. He himself was the greatest measuring rod for integrity, honesty in public life. Unfortunately, his cruel assassination happened immediately after independence, and after him, not a single soul has risen in our nation, who could carry the torch forward or who could use the present opportunities to fight this great evil which is really eating the vitals of our nation. I don't think the Parliament does have that moral authority to give that lead, I don't think the political class has that authority, I don't think the bureaucrats have that authority; the doctors have no authority, the teachers have no authority because all of them have shown themselves to be as corrupt as the others whom they criticise. We have only to wait for another Gandhiji to arise or another Jai Prakash Narain to arise to lead us this way. But as a nation, we should be willing, prepared mentally tuned, to have that type of a second *Messiah* who will lead this country, this nation, out from the morass into which it has fallen. I earnestly thought, wished that the President's Address would have contained, at least, a small paragraph about the determination of the Government to fight corruption and to maintain higher standards of probity but the Address disappointed me in that. I will come to the second issue. The Government is deciding, in a short while, to give help to people to fight elections, help to the political parties to maintain their activities. The type of resistance that is forthcoming may not be very great, but, at least, a beginning is likely to be made. But I would like to warn the Government and also the Members of Parliament that before we decide to use public funds for the maintenance of political parties' working or for giving assistance to individuals to fight elections, we should insist on all political parties to have within their own working, to adopt for their own working, certain standards of accountability, certain standards of transparency and also certain standards of inner democracy. For 30-40 years the western democracies have been trying this practice of helping parties and individuals to fight elections and giving public funds. But they have also passed necessary legislations to see that the parties maintain inner party democracy and remain accountable for the funds that they receive and the funds that they spend. Then only they get the entitlement for State aid. But we are not bothered about it. We are thinking of providing State aid to political parties and candidates without taking care of the weaknesses of the party system. It does not have the inner party

democracy and it does not have accountability to the public. Funds are received and funds are spent in crores by some parties. But no audited accounts are made available to the public to make the public feel happy that these funds are being spent in the right way and for the right reasons.

The third point that I want to raise is about our electoral system. The President's in his Address has said that our electoral system has an impeccable record and is the pride of the nation. I am afraid, he has not used the right word as the subject of the sentence. I would say, the Election Commission in India has an impeccable record and is the pride of the nation. But I will not subscribe to the view or the statement that the electoral system has an impeccable record. Our electoral system, in the past 58 years of our independence, has not even assimilated the basic things which are necessary for claiming this title of having an impeccable record. Its record is very poor. Malpractices have been there in all the elections. The role of criminal elements in society has become so conspicuous that there is no word to describe what it is. People have been led to march or made to march to the polling booths without knowing what they are going to vote for or why they are going to vote for a particular candidate. There are so many loopholes in our system; there are so many deficiencies in our system. Here again, so many committees and commissions have recommended what should be done. But very little action has been taken. We have this great institution of Election Commission which has to fight all the odds that it faces and, in addition to that, face the criticism also. I give my tribute whole-heartedly to the manner in which the Election Commission has functioned.

But I would like to tell you, Mr. Deputy Chairman, and I would like to inform the Members of the House that we can't continue this sytem in this way for many more elections. There are limits to which an Election Commission can go and there are limits to which it can stand the strain. One day they will also break down. Look at the frequency of elections. Every moment, every day, every week, every month, there is an election. There are elections for the State Assemblies and there are elections for the Parliament separately. There are elections for a few groups of States and then come elections for another few groups of States. Then comes the instability in Government administration at the State level. When the code of conduct comes into operation, development schemes are kept in abeyance. Then come the movement of police from one State to another

State and the movement of civil servants from one place to another place. Enormous expenditure is involved. We have to have a system by which the country will have elections at a particular time. We have to have a system by which if the Government loses majority in Parliament, it will not go out of office immediately and result in fresh elections, but another Government has to be voted in its place by a simultaneous vote of affirmative confidence before there is a vacuum created by its resignation. Once a Government is elected for five years, it should continue for five years, unless in the middle it is thrown out and another Government comes in its place. Simultaneously, you can throw out a Government and bring in another Government; otherwise, this practice of continuing elections from month to month and almost from day to day and everybody remaining in an election mode in the country for days together, is not going to be a solution to our problem. The Election Commission may fail in its task of commanding the loyalty and approval of the nation on this.

I will conclude by raising an issue pertaining to the State from which I have been elected. It may be a local demand but it is a serious demand and that is the demand of the Konkan region of the Maharashtra State to have a statutory development board of its own. This would need an amendment of article 371 of the Constitution. This amendment had taken place and Statutory Development Boards were established for the backward regions of Vidarbha and Marathwada, but Konkan was left out. The Konkan region is as backward as Vidarbha and Marathwada. For some reasons, it was left out and it has been tagged along with the rest of Maharashtra which includes very advanced places like Pune, Mumbai City, Thane and all that. Konkan has not got its legitimate share. As one who is responsible for introudcing this new scheme of development boards in Maharashtra, I very strongly feel that proper justice has not been done to Konkan. The matter is pending with the Government. The matter was pending with the previous Government also. No firm decision is being taken. I wish to avail of this opportunity to press the importance and urgency of this decision. Thank you.

डा॰ **प्रभा ठाकुर** (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति जी। मैं यहां इस सदन के विद्वान और वरिष्ठ सदस्य, माननीय डा॰ कर्ण सिंह जी द्वारा उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्तुत हुई हूं। मैं इस अभिभाषण का हार्दिक स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं। इसलिए कि यह वह दस्तावेज है, जिसका इस देश की पूरी आम जनता ने भी स्वागत किया है और तहे-दिल से समर्थन किया है, क्योंकि यह अभिभाषण ''बहुजन हिताय'' और ''बहुजन सुखाय'' का संदेश देता है।

महोदय, यों तो आज तक जितने भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण हुए होंगे, मैं यह नहीं मानती कि उनमें कोई ऐसा अभिभाषण हुआ होगा या सरकार का कोई ऐसा संकल्प आया होगा कि जिससे देश की सौ में से सौ, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का निराकरण हो गया होगा। मैं सबके विचार सुन रही थी, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस सरकार को अभी कुल 21 माह हुए हैं इतने कम समय में कुछ ठोस उपलब्धियां जो हैं तथा कथनी और करनी का जो अन्तर नहीं है, जनता देख रही है कि नीति और नीयत का अन्तर नहीं है। यू॰पी॰ए॰ सरकार का जो साझा कार्यक्रम बना है, उसके अनुरूप यह सरकार जो एक-एक कदम उस दिशा में बढ़ा रही है, इसे पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, पूरा मीडिया देख रहा है और उसका आकलन भी कर रहा है। आज इससे आम जनता का विश्वास इस सरकार की ओर बढ़ा है, मनमोहन सरकार की ओर विश्वास बढ़ा है और देश को यह आस बंधी है कि ये कोरे कागजी वादे, कोरी कागजी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि जो करती है, कहती है, उसको अमल करने की नीयत भी रखती है। उस पर अमल करना चाहती है। इसलिए आज पूरे देश की जनता का विश्वास इस सरकार में बढ़ा है।

इस दृष्टि से मैं यह कहूंगी कि यह अभिभाषण देश की आम जनता को राहत देने वाला है। देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग हैं, जो समाज के कमजोर तबके से हैं, उन सभी को एक नई आशा देने वाला, उनमें एक नया विश्वास पैदा करने वाला यह अभिभाषण है। इस ओर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दृष्टि है, क्योंकि इस अभिभाषण से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारे देश की महान सांस्कृतिक विरासत है अनेकता में एकता की, उस विरासत को, उस पहचान को यह सरकार संजो कर रखना चाहती है। यह लक्ष्य, यह उद्देश्य इस अभिभाषण से सामने आया है।

महोदय, अब यों तो विपक्ष का धर्म यही होता है आलोचना करना । तुलसी दास जी ने भी कहा है - निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय। चाहे वह प्रतिपक्ष में बैठे लोग हों, या जो कभी साझा सरकार में बैठे हों उनमें से कुछ लोग हों, स्वस्थ आलोचना ही लोकतंत्र का एक स्वस्थ पहलू है, मजबूत पहलू है। इससे लोकतंत्र हमेशा मजबूत होता है। अच्छे सुझावों का, चाहे वे विपक्ष से आएं या सहयोगियों से आएं, उनका हमेशा स्वागत होता है। यह सरकार कोई किसी पूर्वाग्रह से बंधी हुई नहीं है। इनमें कुछ सुझावों को, जो जनहित से, जन-कल्याण से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। सरकार उन पर ध्यान देती है और उन पर अमल करती है।

5-00 P.M.

महोदय, आज देश की जो अमन पसंद जनता है, शांति पसंद जनता है, शांतिप्रिय जनता है, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं, अब वे धर्म के नाम पर, जाति और संप्रदाय के नाम पर बांटने वाली हिंसक राजनीति और ऐसे दलों की विचारधाराओं से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। लोग शांति और अमन में जीना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए खुशहाल सुनहरा भविष्य चाहते हैं, माताएं और बहनें चाहती हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, वे सुख शांति और सुरक्षा में जीना चाहते हैं। इसका विश्वास इस सरकार से फिर से जो दिया है, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादा की स्थापना होती है, उसके मूल्यों की स्थापना होती है, इस विश्वास को जो फिर से दिया है, उसके लिए मैं इस सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का हार्दिक स्वागत करती हूं।

महोदय, इस सरकार की प्रतिबद्धता है और इस सरकार की प्रशंसा योग्य बात यह है कि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का, अवसंचरना को विकसित करने का, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के संकल्प को इसमें प्राथमिकता दी गई है। किसानों के हितों को सर्वोपरि मान्यता देते हुए इस सरकार ने जो योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देती हूं। नौजवानों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर सुलभ हों, इसके लिए जो ग्रामीण रोजगार गारंटी का विधेयक यह सरकार लेकर आई है और विधेयक लेकर ही नहीं आई, अमल भी हो रहा है। यह घोषणा तो पिछली सरकार के समय भी पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी, एक करोड़ बेरोजगार को हर वर्ष रोजगार देने का, लेकिन वह कागजी घोषणा मात्र बन कर रह गई। यह भी देश की जनता ने देखा और आज भी इस देश की जनता देख रही है कि 200 जिलों को, जो कि कमजोर और पिछड़े जिले हैं इस देश के, उनको पहले इस कड़ी में, श्रृंखला में जोड़ते हुए यहां ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी योजना केवल घोषणा मात्र नहीं रही बल्कि उस पर अमल शुरू हो चुका है। इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है, प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे गांवों में एक आशा की, एक खुशहाली की एक नई चेतना आई है, एक नया विश्वास आया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं, जिन पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। इनमें घरेलू हिंसा से निवारण के लिए, महिलाओं को न्याय देने के लिए, महिलाओं को हिंसा, शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसा विधेयक यह सरकार लाई है। बालिकाओं को, भ्रूण हत्या सिर्फ इसलिए इस देश में होती है, क्योंकि आज भी इनको द्वितीय श्रेणी में माना जा रहा है। इसके निवारण के लिए भी सरकार ने एक बड़ा सशक्त प्रयास करते हुए जो यह विधेयक लाई है हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक में संशोधन करके कि पुत्री को पुत्र के समान अधिकार मिलें, उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो, उसका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूं।

यह एक बहुत ही ठोस कदम है, इससे पूरे देश की महिलाओं का आत्म-सम्मान जागा है, उनको एक आत्म-सम्मान मिला है, उनकी एक हैसियत बनी है और इसके लिए मैं इस सरकार को बहुत बधाई देती हूं तथा यह भी आशा करती हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा॰ प्रभा ठाकुर : मैं आपके प्रति भी बहुत आभारी हूं कि आप महिलाओं के प्रति हमेशा बहुत उदार और सदाशय रहे हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: इसके लिए आपको ज्यादा धन्यवाद।

डा॰ प्रभा ठाकुर : मैं यह भी कहना चाहूंगी, महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: 5.00 बज गए हैं, अगर एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकती हों तो जल्दी करें।

डा॰ प्रभा ठाकुर : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी।

महोदय, मैं बातें कहना तो बहुत चाहती थी, लेकिन चूंकि अब समय की सीमा है, मैं कुछ बातें ही कहना चाहती हूं। कल माननीय वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी नेता, श्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ बाते कहीं। वे ऐसी निराधार बातें थीं कि अगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी तो मेरे मन में थोड़ी पीड़ा रह जाएगी। उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस ने गांधीवाद की हत्या की। ऐसा शब्द उन्होंने कहा, मैं सुनकर अचंभित रह गई, स्तब्ध रह गई! यह वाक्य उनको कहने के लिए कहां से निर्देशित हुआ, मैं नहीं जानेती। आज भी कांग्रेस उन्हीं गांधीवादी मूल्यों को लेकर चल रही है, जिनके बारे में गांधी जी ने कहा था - *वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे,* उसी आदर्श को लेकर आज भी कांग्रेस चल रही है। इसीलिए इस सरकार को जो शोषित तबके हैं, उनकी पहले चिंता है और इसी आदर्श को लेकर यह सरकार चल रही है। गांधीवाद की हत्या की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इस देश में गांधी जी की हत्या किसने की थी, कृपया यह भी वे जरा बताएं? उनका जो यह ऐतराज था कि इतनी योजनाओं पर राजीव गांधी जी का नाम क्यों लगा हुआ है, महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह नाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या महात्मा गांधी, ये ऐसी विभूतियां हैं, जो मरकर भी अमर हैं, लोगों के मन में जिंदा हैं। ये ऐसे नाम हैं, जिन पर हमें गर्व है और गर्व है कि उनके नाम से योजनाएं जानी जाती हैं। जनता की तरफ से तो कभी ऐतराज आया नहीं, उधर से ऐतराज आया तो बात मेरी समझ में नहीं आई।

महोदय, मैं आपको राजस्थान की बात बताती हूं। ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक लाया गया, राजस्थान में वह राजस्थान गारंटी विधेयक बनकर रह गया। उसमें मुख्य मंत्री जी की फोटो

छपी हुई है और वह इस रूप में प्रचलित हो रही है, जैसे राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वह योजना लागू की गई हो।

श्री सभापति: बहुत बड़ी बात कह दी है आपने।

डा॰ प्रभा ठाकुर : महोदय, आज राजीव गांधी सबके मन में हैं क्योंकि उनका इस देश के लिए एक त्याग है, एक बलिदान है, इसलिए उनका इस देश में इतना सम्मान है और इतनी मान्यता है।

अंत में, अपनी कुछ मांगों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। सरकार ने त्वरित न्याय प्रणाली की मंशा जताई है, मैं इसका स्वागत करती हूं न्याय जल्दी मिलना चाहिए, कई वर्षों से जो लोग जेलों में बंद हैं - महिलाओं को शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति के लिए, बलात्कार के मामलों में, उनको शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। किसानों के लिए ब्याज दर में और कमी की जानी चाहिए और उनके ऋण लेने की प्रक्रिया भी और आसान हो। राजस्थान जैसे अकालग्रस्त राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

माननीय रेल मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि घाटे की रेल को उन्होंने करोड़ों के मुनाफे में पहुंचा दिया बिना किराए में वृद्धि किए।

श्री सभापति: यह बात आपको सबसे पहले ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर : इसलिए आप खोखरापार-मुनाबाव वाली रेल को, बहुत मांग है, अजमेर तक लाने की कृपा करें। लोग भी यह चाहते हैं कि वे वहां आएं-जाएं।

श्री सभापति: यह लो। अजमेर तक नहीं लाए तो धन्यवाद वापिस कर लिया जाएगा।

डा॰ प्रभा ठाकुर : पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिर यह चाहते हैं कि 'गरीब नवाज़' के दर्शन करके फिर वे अपनी राजस्थान की यात्रा प्रारम्भ करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा॰ प्रभा ठाकुर : अंत में इस सरकार का जो संकल्प है, उसे चार पंक्तियों में कहना चाहूंगी, जो मनमोहन सरकार का संकल्प है, जो यू॰पी॰ए॰ की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया जी का संकल्प है कि:—

कांटे हैं कि कंकर, कभी रुककर नहीं देखा
जब चल पड़े हैं आगे, तो मुड़कर नहीं देखा
और जिस दिन से चले हैं, बस मंजिल पे नज़र है,
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।।

यहीं मैं आपका आह्वान करूंगी कि आप भी इसी दृष्टि से चलें और स्वाधीनता संग्राम की 150वीं जयंती को मनाने का समय आया है। यह आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, हम सब इसमें साझीदार बनें। आजादी तो दिला दी देशभक्तों ने, मर-मिटने वालों ने और महात्मा गांधी ने, अब इस आजादी को सशक्त बनाते हुए, इस देश को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और आर्थिक रूप से सशक्त इस देश को अग्रणी देशों में लाएं इस जिम्मेदारी का हम संकल्प लें। धन्यवाद।

STATEMENTS BY MINISTERS

Justice Rajindar Sachar Committee

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, with your permission I make the following statement:

On 9th March, 2005 a High Level Committee under the chairmanship of Justice Rajindar Sachar was set up "for preparation of a report on the social economic and educational status of the Muslim community of India."

According to the 2001 census the Muslims of India formed the largest minority group of over 138 million, constituting about 13.4% of the country's population. The Muslim community is reportedly afflicted by widespread illiteracy, low income and irregular employment implying a higher incidence of backwardness relative to other religious groups of India.

The High Level Committee was mandated to obtain relevant information from Departments and Agencies of the Central Government, State Governments and also conduct an intensive literature survey to identify published data, articles, research on relative social, economic and educational status of the Muslims of India at the State, Regional and District levels, to address the reasons for backwardness and to formulate appropriate policy to intervene as and when it is necessary.

The Ministry of Defence in its letter dated 14th September, 2005 sent to the High Level Committee clearly brought out that the existing policy of the Government on recruitment in the Armed Forces is based on merit and is open to every citizen of the country including the members of the Muslim community without any discrimination on the basis of their caste, creed, religion or region. The Armed Forces are professional, apolitical, secular and the most disciplined force the country has today. Indian Armed Forces have an all India orientation in which each State contributes its fair share of manpower to the Armed Forces.